हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

18 मार्च, 2002

खण्ड-1, अंक 9

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 18 मार्च, 2002

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(9)24
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(9)28
शोक प्रस्ताव	(9)29
नियम 64 के अधीन वक्तव्य	(9)30
राज्यपाल से संदेश	(9)31
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(9)32
अति विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत	(9)36
समितियों की रिपोर्टस प्रस्तुत करना--	
(i) लोक लेखा समिति की 52वीं रिपोर्ट	(9)37
(ii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 49वीं रिपोर्ट	(9)38
(iii) अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की समिति की 26वीं रिपोर्ट	(9)39
(iv) सरकारी आश्वासनों समिति की 32वीं रिपोर्ट	(9)39
वाक आउट्स	(9)39
वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9)42
वेयक्तिक स्पष्टीकरण--	
कैप्टन अजय सिंह यादव एम.एल.ए. द्वारा	(9)49
वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9)50
बैठक का समय बढ़ाना	(9)75
वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9)75
बैठक का समय बढ़ाना	(9)77
वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9)77
बैठक का समय बढ़ाना	(9)78
वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9)78
बैठक का समय बढ़ाना	(9)79
वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(9)79

मूल्य : 75 00

हरियाणा विधान सभा

सोमवार 18 मार्च, 2002

विधान सभा की बैठक, विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Setting up of Rice Mills in the State

***965. Shri Ramesh Rana :** Will the Minister for Cooperation be pleased to state whether any Rice Mill has been set up by HAFED in the State during the last year; if so, the name of the places where these were set up ?

सहकारिता मंत्री (श्री करतार सिंह भड़ाना) : हाँ, श्रीमान् जी। गत् वर्ष के दौरान हैफेड ने सिरसा जिले में दो चावल मिलें, एक डींग व दूसरी कालांवाली में स्थापित की है।

श्री रमेश राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहूँगा तथा इसके साथ ही एक निवेदन भी करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, घरौण्डा की मण्डी विश्व स्तर की मण्डी है उसके भाव "Zee T.V." से टैलीकॉस्ट होते हैं और बड़े-बड़े अखबारों में भी प्रकाशित होते हैं। वहां पर हैफेड की एक चावल मिल लगी हुई है। इस मिल की मशीनरी बहुत पुरानी हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या इस मिल की कैपेसिटी बढ़ाने का सरकार का कोई विचार है, यदि नहीं तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मिल का आधुनिकीकरण किया जाए और इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए।

श्री करतार सिंह भड़ाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूँगा कि इनके द्वारा पूछा गया सप्लीमैंट्री सवाल मेन सवाल से सम्बन्धित नहीं है। हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को यह बताना चाहूँगा कि मेरे हल्के में मतलौडा में हैफेड की एक राईस मिल है जो कि बन्द कर दी गई थी। क्या माननीय मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस मिल को दोबारा चलाने के लिए विचार कर रही है ? यदि हां तो इसको कब तक चालू कर दिया जाएगा ?

श्री करतार सिंह भड़ाना : अध्यक्ष महोदय, इसको एग्जामिन करवा लेंगे और यदि इसको चालू कर सकते हैं तो इसको चालू करेंगे।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि होडल तथा पलवल का एरिया दक्षिणी हरियाणा में धान का सब से बड़ा उत्पादन केन्द्र है और वहां पर बड़ी भारी मात्रा में धान पैदा होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूँगा कि किसानों की मांग को देखते हुए क्या होडल या पलवल के क्षेत्र में कोई हैफेड की धान की मिल लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री करतार सिंह भड़ाना : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है, फिर भी मैं माननीय साथी को यह बताना चाहूँगा कि इसको एग्जामिन करवा लेंगे और यदि किसानों का सहयोग होगा और वहां पर चावल मिल की आवश्यकता होगी तो वहां पर चावल मिल लगाने बारे विचार कर लिया जाएगा।

तारांकित प्रश्न संख्या : 931

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री नफे सिंह राठी सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Land Scandal of Ambala Cantt.

***1059. Sh. Anil Vij :** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state-

(a) whether any enquiry in regard to the land scandal of Ambala Cantt. has been conducted by the Urban Development Department recently; if so, details thereof ; and

(b) whether it is a fact that the Government land held on lease / old grant has been sold by some influential persons recently; if so, the details thereof ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) : —

(क) हाँ, श्रीमान् जी। अम्बाला सदर के ओल्ड ग्रांट बंगलों व ओल्ड ग्रांट लीज तथा लीज की प्रोपर्टीज के बारे में नगर विकास विभाग, हरियाणा द्वारा जाँच की गई। इस सम्बन्ध में विवरण अनुबन्ध 'क' में सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) हाँ, श्रीमान् जी। विवरण अनुबन्ध 'ख' में सदन के पटल पर रखा जाता है।

अनुबन्ध 'क'

अम्बाला सदर एक्साईज्ड ऐरिया में चार प्रकार की सम्पत्तियां हैं जिसके अधिकार एक्सीजन एग्रीमेंट 1977 के अनुसार हरियाणा सरकार में निहित हैं। भारत सरकार के पत्र दिनांक 5-2-1977 के अनुसार, रक्षा मंत्रालय,

भारत सरकार की सम्पत्ति का अधिकार, एक्साईज्ड ऐरिया में हरियाणा सरकार को निःशुल्क स्थानान्तरित है और एक्साईज्ड ऐरिया के सम्बन्ध में कैन्टोनमैंट बोर्ड की सम्पत्ति के अधिकार निःशुल्क अधिसूचित क्षेत्र समिति को स्थानान्तरित हुए। इस प्रकार राज्य सरकार अम्बाला सदर नगरपरिषद् क्षेत्र में स्थित ओल्ड ग्रांट स्थलों की मालिक बन जाती है। सम्पत्ति के चार प्रकार ओल्ड ग्रांट बंगले, ओल्ड ग्रांट होल्डिंग, लीज होल्ड प्रोपर्टीज व कृषि सम्बन्धी प्लॉट हैं।

नगरपरिषद् व सरकार के विभिन्न अधिकारियों / कर्मचारियों से मिलीभगत करके व झूठी व जाली दस्तावेज के माध्यम से सम्पत्तियों के अवैध हस्तांतरण द्वारा ग्रांट / लीज की शर्तों की गम्भीर उल्लंघना के बारे में सरकार को सूचना मिलने पर दिनांक 4-7-2001 को उपायुक्त अम्बाला को निम्न प्रकार से कार्रवाई करने के लिए कहा गया :--

1. ऐसी भूमि मानचित्रों के अनुमोदित भवन मानचित्र निलम्बित करना जोकि resumption की प्रक्रिया में हैं।

2. प्लॉटों के बैनामों (sale deeds) के पंजीकरण जो तीसरे पक्ष (third party) के अधिकार जताते हैं और जो resumption की प्रक्रिया में हों, को रद्द करना।

3. दिनांक 31-1-95 की बैठक के उपरांत एवं 11-3-98 को उपायुक्त अम्बाला व कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद्, अम्बाला सदर की उपस्थिति में तत्कालीन वित्तायुक्त एवं सचिव, स्थानीय शासन के दोहराने के बावजूद सरकारी हिदायतों की अवहेलना के लिए सम्बन्धित राजस्व व परिषद् अमला की जिम्मेवारी निर्धारित करना।

4. आगामी किसी भी निर्माण व तबदीली को रोकने हेतु तात्कालिक कार्रवाई करना।

5. यह देखना कि यथास्थिति के आदेशों की पट्टेदारों द्वारा कोई उल्लंघना तो नहीं की गई है।

6. रिजम्पशन के मामलों का उद्यमता से अनुसरण करना।

नगर विकास विभाग के अधिकारियों की एक समिति को मामले में जाँच करने को कहा गया जिन्होंने अपनी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की। संक्षेप में, रिपोर्ट में निम्नलिखित गम्भीर अनियमितताएं सामने आई --

1. नगरपरिषद्, अम्बाला सदर द्वारा Excised area में बिना सरकार की पूर्व अनुमति के भवन मानचित्रों को अवैध रूप से पास करना।

2. Excised area अम्बाला सदर में नौ बंगलों के बारे में सरकार के निर्देशों के बावजूद भी अनाधिकृत निर्माण / भूमि का उद्देश्य परिवर्तित करना व निर्मित क्षेत्र में बढ़ौतरी आदि करके ओल्ड ग्रांट बंगलों की ओल्ड ग्रांट नीति की अवहेलना करना।

3. हरियाणा सरकार का अनुमोदन न प्राप्त करके Excised area अम्बाला सदर में ओल्ड ग्रांट व लीज जायदाद का अवैध हस्तांतरण करना।

4. नगरपरिषद् अम्बाला सदर एवं सम्पदा अधिकारी Excised area अम्बाला सदर द्वारा अवैध रूप से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना।

5. नगरपरिषद् अम्बाला सदर द्वारा अतिक्रमण / अनाधिकृत निर्माण को रोकने में असफल रहना व इसके अतिरिक्त नगरपरिषद् अम्बाला सदर द्वारा प्रस्ताव पारित करके दुकानों के सामने लगे शटरों को नियमित करने की सिफारिश करना।

[श्री सुभाष गोयल]

6. बिना सरकार की अनुमति के लकड़ी के अस्थाई खोखों को पक्का निर्माण में बदलना।

जाँच रिपोर्ट में सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश के साथ कैन्टोनमैंट कानून की पालना करना व विशेष कानूनी एवं एनफोर्समैंट प्रकोष्ठ के गठन का सुझाव दिया।

सरकार ने जाँच अधिकारी की सिफारिशों का अनुमोदन प्रदान कर दिया है और मामले में और छानबीन व निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों की आपराधिक जिम्मेवारी आदि निर्धारित करने हेतु, रिपोर्ट राज्य चौकसी ब्यूरो को भेजने के आदेश पारित किये गये।

सरकार के निर्णय अनुसार जाँच रिपोर्ट राज्य चौकसी ब्यूरो को और छानबीन हेतु भेज दी गई है।

अनुबन्ध 'ख'

1. **बंगला नम्बर 123 (2.53 एकड़)**

यह बंगला महाराजा पटियाला के नाम पर था परंतु गृह कर निर्धारण रजिस्टर में मूल ग्रांट होल्डर के स्थान पर यह श्रीमती सरन कौर विधवा कर्नल सुजान सिंह, महारानी मोहिन्द्र कौर इत्यादि के नाम दर्ज हो गया जिसके लिए न तो कोई सबूत है और न ही सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया गया। यह पाया गया है कि श्रीमती सरन कौर विधवा श्री सुजान सिंह का नाम बिना सरकार के पूर्व अनुमोदन के व उत्तराधिकार-नामा प्राप्त किये बिना ही शपथ-पत्र के आधार पर दिनांक 10-6-1996 को दर्ज किया गया है। महारानी मोहिन्द्र कौर इत्यादि के नाम भी गृह कर रिकॉर्ड में collusive decree के आधार पर दिनांक 27-8-96 को दर्ज किये गये थे। collusive decree में न तो परिषद् और न ही सरकार पार्टी थी और यह स्थानान्तरण सरकार के अनुमोदन के बिना ही अवैध रूप से किया गया था, जबकि यह एक सर्वविदित सत्य है कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 87 के अन्तर्गत गृह कर रजिस्टर में कोई भी नामान्तरण उचित प्रक्रिया अपनाने उपरांत विधि-सम्मत् जैसा दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाता है।

2. **बंगला नम्बर 125-बी (0.28 एकड़)**

मैसर्ज हरनाम दास एंड संज इस बंगला का मूल ग्रांट होल्डर था। परन्तु नगरपरिषद् के 1980-83 के गृह कर रिकॉर्ड में श्री ओम प्रकाश और श्री अशोक जैन के नाम दर्ज किये गये हैं। यह पाया गया कि यह सम्पत्ति बनावटी सेल-डीड के आधार पर पहले श्री वी.के. जैसवाल के नाम स्थानान्तरित की गई थी जिसे नगरपरिषद् अधिकारियों द्वारा बिना सरकार के अनुमोदन के स्वीकार कर लिया गया। परिषद् प्राधिकारियों ने इस झूठे डीड को कभी भी सरकार के ध्यान में नहीं लाया। श्री वी.के. जैसवाल ने इस सम्पत्ति को अवैध रूप में आगे श्री अशोक जैन को बेच दिया।

3. **बंगला नम्बर 125 (सैवोय होटल) (2.98 एकड़)**

श्रीमती माया देवी कोछर इस बंगला की मूल ओल्ड ग्रांट होल्डर थी। वर्तमान में निर्धारण रजिस्टर में श्रीमती निर्मला रानी और श्री जसबीर सिंह के नाम दर्ज किये हुए हैं। ऐसा कोई दस्तावेज जिसके आधार पर स्वामित्व को बदला गया है नगरपरिषद् के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

4. **बंगला नम्बर 126 (पैरी होटल) (3.75 एकड़)**

कंवर अमृत लाल इस बंगला का मूल ओल्ड ग्रांट होल्डर था। इसे अम्बाला में दिनांक 13-7-88 को पंजीकृत हुए सेल-डीड के माध्यम से अवेश प्रोपर्टी डीलर को स्थानान्तरित किया गया। नगरपरिषद् द्वारा कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया परन्तु नगरपरिषद् द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश दिनांक

13-7-88 के द्वारा इसका नामान्तरण असैसमैंट रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया। अवेश प्रोपर्टी डीलर ने इसका कुछ भाग आगे श्रीमति रजनी धमीजा पत्नी श्री गुलशन धमीजा को अम्बाला में दिनांक 25-2-92 को पंजीकृत हुई सेल-डीड के माध्यम से स्थानान्तरित कर दिया। कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया लेकिन फिर भी नगरपरिषद् ने इस सम्पत्ति को रजनी धमीजा व गुलशन धमीजा के नाम मामान्तरित कर दिया। इस प्रकार निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

5. बंगला नम्बर 125-ए (मैट्रो पोल) (4.089 एकड़)

श्रीमति दुर्गा देवी पत्नी श्री जानकी दास और श्री मनमोहन सिंह इस प्रोपर्टी के वास्तविक ओल्ड ग्रांट होल्डर थे। वर्तमान में यह सम्पत्ति गंगा राम एंड संज के नाम पर दर्ज है। यह नामान्तरण नगरपरिषद् द्वारा वर्ष 1980 में किया गया था। जिन दस्तावेजों के आधार पर यह किया गया था, वह नगरपरिषद् के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थे।

6. बंगला नम्बर 126-ए (एम्पलायमैंट एक्सचेंज बिल्डिंग) (4.09 एकड़)

मैसर्ज ए.पी. मिशनरी इस बंगले का वास्तविक ओल्ड ग्रांट होल्डर था। यह सम्पत्ति वास्तविक ग्रांट द्वारा दिनांक 3-4-1986 को सम्पादित हुए सेल-डीड के माध्यम से स्थानान्तरित की गई थी। परंतु इस नाम पर नामान्तरण का कोई रिकॉर्ड नगरपरिषद् में उपलब्ध नहीं है। मैसर्ज जैन ब्रदर्ज ने वर्ष 1987 में सेल-डीड के माध्यम से आगे इस सम्पत्ति को मैसर्ज रामा बिल्डर्ज को स्थानान्तरित कर दिया और गृह कर रिकॉर्ड में इस का नामान्तरण कार्यकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 6-12-88 के द्वारा किया गया। परंतु सम्बन्धित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में असैसमैंट रजिस्टर में श्री सुरजीत सिंह गुलाटी का नाम दर्ज है।

7. बंगला नम्बर 127-ए (ओल्ड आईस फैक्ट्री) (2.44 एकड़)

इस बंगला के वास्तविक ओल्ड ग्रांट होल्डर श्री कुलभूषण और कुलदीप प्रकाश इत्यादि थे। वर्तमान में सम्पत्ति श्री मनमोहन सिंह लिब्रहान के नाम पर है। श्री मनमोहन सिंह लिब्रहान इत्यादि के नाम पर सम्पत्ति collusive decree के आधार पर स्थानान्तरित कर दिया गया। परिषद् रिकॉर्ड में सम्पत्ति के नामान्तरण से पूर्व माननीय न्यायालय के आदेशों को न तो चुनौती दी गई और न ही सरकार के ध्यान में लाया गया।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बड़े विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अम्बाला छावनी में प्रभावशाली लोगों द्वारा सरकारी जमीन बेची गई है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूँगा कि ये प्रभावशाली व्यक्ति कौन-कौन हैं, और इनके द्वारा क्या-क्या इर-रैगुलैरिटीज़ की गई हैं और कितनी प्रोपर्टी बेची गई है और कितने रुपये में बेची गई है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ******

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठें। (विघ्न) इनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाए। (विघ्न)

श्री सुभाष गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को बताना चाहूंगा कि ओल्ड ग्रांट बंगलों में 17 प्रापर्टीज की पहचान की गई है जिसमें विशेष रूप से बिहारी लाल ट्रस्ट सर्वे नम्बर 188, अवहेलना के कारण लीज समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है। ***** एक बंगला नं. 127-बी, इसमें यथा स्थिति बनाई रखी जाए। इसकी तारीख कोर्ट में 6-5-2002 की है। मैसर्ज बनारसी दास सर्वे नम्बर 192 लीज समाप्ति हेतु नोटिस जारी किया गया है। यह केस कोर्ट में है। इसमें आज की तारीख 18-3-2002 लगी हुई है। चौथा लाल दास, गार्डन

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री सुभाष गोयल]

सर्वे नम्बर 207/4695 लीज हेतु समाप्ति कारण बताओ नोटिस दिया गया है। इसी प्रकार ओल्ड ग्रान्ट लीज होल्डर जायदाद के बारे में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है कर्नल सी.पी. सिंह बंगला नम्बर 123 बनाम सम्पदा अधिकारी इसमें निर्णय सुरक्षित रखा गया है इसमें अगली तिथि 15-4-2002 की लगी है। एस.बी.एस. इन्द्र सिंह, बंगला नम्बर 124 बनाम हरियाणा राज्य, सम्पदा अधिकारी, इसमें बहस के लिए 15-3-2002 की तारीख निश्चित थी। ***** बंगला नम्बर 127-ए, बनाम हरियाणा राज्य, यथास्थिति की पुष्टि, इसमें अगली तारीख 6-5-2002 की लगी हुई है। शेष बंगला होल्डर्ज ने कारण बताओ नोटिस पर निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपनी याचिका दायर की हुई है इसमें अगली तारीख 18-3-2002, 21-3-2002 और 18-4-2002 है श्रीमान् जी।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक बहुत ही हिम्मत वाला काम किया है जहां सरकार ने यह कह रखा है कि अगर कहीं पर भी सरकारी भूमि को खुर्दबुर्द किया जाएगा तो उसमें कार्यवाही की जाएगी और इसमें सरकार ने जाँच भी की है। जैसा कि इस रिपोर्ट में दिया गया है यह जो अनियमितताएं हैं इनमें राज्य चौकसी ब्यूरो को छानबीन के लिए भी केस भेज दिया गया है। मेरी शंका यह है कि इसमें करोड़ों रुपयों की भूमि को बेचने का मामला शामिल है। जिन्होंने यह ज़मीन बेची है ये कोई छोटे-मोटे आदमियों का काम नहीं हो सकता है। यह तो बड़े-बड़े व्यक्तियों का और बड़े-बड़े अधिकारियों की मिली भगत से सरकार की सम्पत्ति को चूना लगाया गया है। इसमें **** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अनिल विज जी आप नाम न लें आप स्पलीमैंटरी पूछें। यह जो जस्टिस का नाम लिया गया है वह रिकॉर्ड नहीं किया जाए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : *******। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : इस मामले की जाँच हो रही है इसमें आपको दिक्कत क्या है, आपको क्या कष्ट हो रहा है। यह करोड़ों का मामला है, सरकारी सम्पत्ति का मामला है। (शोर एवं व्यवधान) इस बारे में हरियाणा की जनता को जानने का हक है। (शोर एवं व्यवधान) यह हरियाणा की जनता का अधिकार है और जवाब में कैटेगरीकली नाम आए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : *******।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : *****।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। कर्ण सिंह जी आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति की है कि जो मामला अदालत में विचाराधीन हो उस पर यहां पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। हम सदन के सदस्यों की इस बात से सहमत हैं। लेकिन इसमें अम्बाला कैंट का जो मामला है वह किसी एक पर्टिकुलर कोठी का मामला है जोकि कोर्ट के विचाराधीन है उसमें सरकार की सैंकड़ों एकड़ भूमि ऐसी है जो बहुत कीमती है और वहां पर नाजायज

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

तरीके से लोगों ने कब्जा किया हुआ है उसमें सरकार का सैंकड़ों करोड़ों रुपयों का नुकसान है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस का जो जिक्र किया गया है वह कार्यवाही से निकाल दिया जाए क्योंकि वे यहां पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूँगा कि यह एक अहम मुद्दा है। अगर कोई स्टेट का नुकसान करे या स्टेट की भूमि पर कब्जा करे और उस पर कोई कार्यवाही हो तो आप कम उस पर तो कम से कम आपत्ति न किया करें। स्टेट के हितों को ध्यान में रखा करो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है चीफ जस्टिस का नाम कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रभावशाली लोग हैं चाहे वे जो भी हैं जो भी उनके नाम हैं जिन्होंने चोरी की है, अगर चौकसी ब्यूरो की जाँच में वे दोषी पाए जाएंगे तो क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी इस बारे में मंत्री जी बताएं।

श्री सुभाष गोयल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्य को बतलाना चाहूँगा कि जैसा अभी हमारे लीडर ऑफ दी हाऊस मुख्य मंत्री महोदय ने भी बतलाया कि इसमें तकरीबन 110 करोड़ रुपये का आंकलन किया है, 9 बंगला जमीन का, जो साढ़े 26 एकड़ के करीब है। ओल्ड ग्रांट होल्डिंग की 238.50 एकड़ जमीन है जिसका 950 करोड़ रुपये के करीब का आंकलन किया है और 212 एकड़ जमीन लीज होल्ड प्रोपर्टीज के तहत है। कृषि की 131 एकड़ जमीन है और जो 45 प्लाटस हैं जिनकी अवधि 1983 में समाप्त हो गयी थी, यह सब तकरीबन-तकरीबन 1300 करोड़ रुपये का मामला बनता है। अध्यक्ष महोदय, जैसाकि अभी मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि यह हजारों करोड़ रुपये का मामला बनता है इसलिए सरकार इस बारे में बड़ी चिंतित है और इस बारे हाई लेवल मीटिंग करके इसकी स्क्रीनिंग चल रही है। जैसा अभी सम्मानित सदस्य ने कहा कि इस बारे में विजीलैंस डिपार्टमैंट इंक्वायरी कर रहा है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस विजीलैंस इंक्वायरी में जो भी शख्सियत दोषी पायी जाएगी चाहे वह बड़ी हो या छोटी हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि लगभग 1300 करोड़ रुपये की भूमि में सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से प्रभावशाली लोगों ने काफी बड़े हिस्से को नाजायज तरीके से प्लाटस काटकर बेच दिए हैं और चौकसी ब्यूरो इसकी जाँच भी कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि चौकसी ब्यूरो की रिपोर्ट इस बारे में कब तक आ जाएगी? पहले यह कहा गया था कि चौकसी ब्यूरो की यह रिपोर्ट अगस्त तक जारी कर दी जाएगी लेकिन अब मार्च का महीना जा रहा है अब तक यह रिपोर्ट जारी नहीं की गयी। मैं जानना चाहूँगा कि कब तक यह जाँच पूरी कर ली जाएगी और कब तक इसमें जो दोषी लोग हैं, वे सजा पा सकेंगे?

श्री सुभाष गोयल : सम्मानित अध्यक्ष महोदय, चौकसी ब्यूरो ने तकरीबन पचास अधिकारियों की इंक्वायरी की है तथा सात अधिकारियों की इंक्वायरी अभी करना बाकी है। हमें उम्मीद है कि शायद अप्रैल के महीने या मई महीने में यह जाँच की रिपोर्ट आ सकने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, लीगल कारणों से इसमें कुछ देरी भी हो सकती है। हम इस बारे में पूर्णतः जागरूक हैं। मैं आपके माध्यम से इस बारे में थोड़ी-सी विस्तृत जानकारी सदन को देना चाहूँगा कि हम इस बारे में मीटिंग करके माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निर्देशन में एक लैंड पोलिसी बनाने जा रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी और दलाल साहब, आप यहां पर बैठकर बातचीत न करें। अगर आपको बातचीत करनी ही है तो लॉबी में जाकर बातचीत करें।

श्री सुभाष गोयल : अगर इस बारे में हरियाणा में कहीं भी किसी प्रकार की अनियमितता हो रही होगी उसको कैसे रोका जा सकेगा, यह इस पोलिसी में क्लीयर होगा। अध्यक्ष महोदय, हमने डी.सी. अम्बाला और लीगल

[श्री सुभाष गोयल]
ऐडवाइजर मि. भटनागर की इस बारे में राय मांगी है उनकी राय आने के पश्चात् वह मंत्रीमंडल के रूबरू आएगी। इसके बाद ही हम लैंड पोलिसी बनाएंगे ताकि आगे से कोई भी किसी भी प्रकार की हरियाणा की जमीन पर नाजायज कब्जा न कर सके। अध्यक्ष महोदय, हम इस बारे में एक पोलिस बनाने जा रहे हैं।

Augmentation of Drinking Water Supply

*927 **Shri Lila Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any Augmentation of Drinking Water Supply Scheme has been sanctioned for Kaithal, Bhiwani, Ambala Sadar, Ambala City etc. ; if so, the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : श्रीमान् जी, हां। कैथल, भिवानी , अम्बाला सदर व अम्बाला शहर में पेयजल बढ़ौतरी की योजनाएं पहले से कार्यरत हैं। भूमिगत जल की गुणवत्ता खराब होने के मद्देनजर, कैथल शहर में 14.85 करोड़ रूपये के अनुमान की पेयजल योजना पर कार्य चल रहा है। टयूबवैलों से अपर्याप्त पानी की उपलब्धता के कारण अम्बाला सदर और अम्बाला शहर में क्रमश: 15.03 करोड़ रुपये व 8.75 करोड़ रूपये की अनुमानित राशि के तहत नहरी पानी पर आधारित पेयजल योजनाओं का कार्य चल रहा है। भिवानी में नहर पर आधारित पेयजल योजना की क्षमता की बढ़ौतरी कार्य 19.85 करोड रूपये के अनुमान के तहत कार्य चल रहा है।

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम सी.पी.एस. महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा। कैथल के एरिया में नीचे का पानी खराब होने की वजह से यह पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। कैथल की जनता की यह 25-30 साल पुरानी मांग थी। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए एक ही बार में 15 करोड़ रुपये का प्रौजैक्ट देकर कैथल शहर के लोगों के लिए जिस प्रकार पानी की व्यवस्था की मैं उसके लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, कैथल व उसके आसपास का जितना भी एरिया है वहां पर नीचे का पानी खराब है इसलिए कैथल की जनता ने अनेक बार मांग रखी थी परन्तु इस सरकार से पूर्व पिछली जो भी सरकारें आईं उन में से किसी ने भी इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब कैथल के लोगों ने आदरणीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष यह मांग रखी तो उन्होंने उसी समय 4 करोड़ रुपये की राशि रिलीज कर इस काम की स्पीड को बढ़ाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक-दो मांगें और रखना चाहूँगा। हमारे दो तीन गांव हैं उनमें अब भी नीचे का पानी खराब है जैसे डोह खेड़ी, पट्टी अफगान, दिल्लोंवाली, जगदीशपुरा व बड़ा गांव हैं। हमारी मांग है कि इन गांवों में एक-एक टयूबवैल और लगाया जाए। पाडली गांव में एक टयूबवैल लगा हुआ है व एक टयूबवैल की और जरूरत है। इसी तरह गांव दिवाल व पुन्दरेहड़ी में भी आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने 70-80 लाख रुपये खर्च करके कैनाल बेस्ड स्कीम को मंजूर किया। उसके लिए भी मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। इस पर जल्दी काम शुरू किया जाए यह मेरा अनुरोध है।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार मेरे साथी भाई लीला राम जी ने यह कहा कि कैथल के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग थी। पूरे हरियाणा की स्थिति इसी प्रकार से है हरियाणा प्यासा मर रहा था इसलिए इन चारों जगहों पर, चारों शहरों में कैथल, अम्बाला सिटी, अम्बाला सदर व भिवानी में 49 करोड़ 74 लाख 6 हजार रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी गई है और 44 करोड़ 17 लाख रुपये की राशि उसके लिए आबंटित भी कर दी गई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लीला राम जी ने कहा है कि हमारे कुछ गांव हैं उनमें भी

बहुत समस्या है। अध्यक्ष महोदय, इनके पूरे कैथल जिले में 44 योजनाओं पर काम चल रहा है। इन 44 योजनाओं में 68 गांव कैथल के होंगे। इसके लिए 8 करोड़ 49 लाख 25 हजार रुपये लगेंगे और जिन पर काम चल रहा है। इन्हीं के हल्के के गांव क्वारथन की जलापूर्ति की योजना है और उसका काम युद्धस्तर पर जारी है। उसी प्रकार से इनके हल्के के गांव सिरेटा, मानस, फ्रांसमाजरा में जलापूर्ति योजना का इनलेट का कार्य, पूरे युद्धस्तर पर जारी है जिस पर 19 लाख रुपये खर्च होंगे। इसी तरह से इनके गांव क्योंड़क, दयोरा, बरोट खुराना व उजाना जो इनका अपना गांव है, इन पर सभी कामों पर लाखों रुपया खर्च करके इस समस्या का निदान किया जा रहा है। इस प्रकार की 68 योजनाएं हैं अगर मैं सारी की सारी यहां बताऊंगा तो समय लगेगा। 68 गांवों की लिस्ट यदि माननीय साथी विधायक लेना चाहें तो उनको मैं दे दूंगा। इस तरह की सारी योजनाओं पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्यों के प्रश्न नहीं लगे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके 20 विधायकों में से 11 ने प्रश्न दिये हैं और उन सभी के प्रश्न टेक अप किये गये हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आज लगना था लेकिन उसको टेक अप नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : आप अपने दस्तखत करके तो भेजते नहीं हो। प्रश्न आपका कैसे टेक अप किया जाये। अगर आपको इस बारे शंका है तो मेरे चैम्बर में आ जाना वहां आपको ऐसे प्रश्न आपके द्वारा भेजे हुये दिखा दिये जायेंगे जो बिल्कुल ब्लैंक हैं। अब आप बैठ जाइये।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन्होंने कैनाल बेस्ड वाटर स्कीम के बारे में कैथल, भिवानी, अम्बाला शहर और अम्बाला सदर के बारे में बताया है। मैं आपके माध्यम से माजरा साहब से पूछना चाहता हूं कि अम्बाला सदर में 15.3 करोड़ रुपये की लागत से नहरी पानी आधारित योजना के तहत पानी देने की स्कीम का कार्य चल रहा है और सरकार उसमें पूरी रूचि भी ले रही है। मैं माजरा साहब से पूछना चाहता हूं कि वह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैंने इससे पहले भी बताया है कि इस स्कीम के लिए काफी पैसा रिलीज हो चुका है और जिस प्रकार से भाई लीला राम जी का प्रश्न है कैथल के बारे में उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सिरसा ब्रान्च पर ड्रेन क्रोसिंग और हैड रेगूलेटर इरिगेशन विभाग द्वारा लगाना है और रेलवे क्रासिंग का काम भी किया जाना है पब्लिक हैल्थ विभाग ने इन सबकी लागत जमा करा दी है। जब यह कार्य पूरा हो जायेगा तो यह स्कीम काम करना शुरू कर देगी। जहां तक भिवानी की स्कीम की बात है वह मार्च, 2003 तक काम शुरू कर देगी और अम्बाला सदर का मार्च 2004 तक शैडिल्यूड में है और यह काम मोस्ट प्रोबेबली समय पर हो जायेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माजरा साहब को बताना चाहता हूं कि जिस कनाल बेस्ड वाटर स्कीम के बारे में ये बात कर रहे हैं ये पानी ओपन चलता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई ऐसी स्कीम है जो इस पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर इसकी सफाई की व्यवस्था करवा सके और क्या इस पानी के सैम्पल लेकर उनको टेस्ट करवाने का कोई प्रावधान है।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, यह सब कार्य पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट द्वारा समय पर करवाया जाता

[श्री राम पाल माजरा]
है। इसका ट्रीटमैंट करवाया जाता है। माननीय साथी के नोटिस में कोई ऐसा इंस्टांस आया हो तो बतायें उसको हम चैक करवा लेंगे। वैसे हम सारे हरियाणा प्रदेश में अब कवर्ड खालों द्वारा इस स्कीम को लागू करने की योजना बना रहे हैं यह खुले खालों की योजना तो कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई थी जिनमें लोग रफा हाजत के हाथ तक धोते थे अब हम इस कैनाल बेस्ड वाटर स्कीम को कवर्ड खालों के माध्यम से शुरू कर रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के गांव मांडिया कलां में सैम्पल लिया गया था और वह सैम्पल लैबोरेटरी में फेल हो चुका है।

श्री राम पाल माजरा : स्वीकर सर, अब ये अपने हल्के के गांव की बात कर रहे हैं पता नहीं वहां के बारे ये कैसे कह रहे हैं वैसे हरियाणा प्रदेश की जनता पूरी तरह से पेय जल व्यवस्था से संतुष्ट है। इन वाला सैम्पल जरूर फेल हो गया होगा।

Construction of By-Pass

***856. Shri Puran Singh Dabra :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct :

(i) Southern By-pass from Delhi Road to Sirsa Road ;

(ii) Crossing Tosham Road, Rajgarh Road (NH-65) and Balasamand Road in Hisar ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : (i) और (ii) नहीं, श्रीमान् जी।

श्री पूर्ण सिंह डाबरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि हिसार के अन्दर जब हाइवे नम्बर 65 बड़ा बनेगा तो वहां ट्रैफिक का बड़ा भारी लोड रहेगा और इधर हाइ-वे नम्बर 10 पर भी बड़ा भारी ट्रैफिक का लोड है। हिसार में जबकि पहले से ही नार्दन बाई-पास बना हुआ है लेकिन वहां साऊदर्न बाई-पास की बहुत भारी आवश्यकता है। क्योंकि शहर में रोज बहुत हादसे हो रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इस पर विचार किया जाए ताकि ये बन जाए और इसके बनने से ट्रैफिक और लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि वैसे तो सब जगह बाई-पास की जरूरत है और इस सरकार के मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने गांवों के बाई-पास को पक्का भी कर दिया है, फिरनियों को पक्का कर दिया है। वैसे यह मामला अभी विचाराधीन नहीं है और अभी मैं समझता हूँ कि इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, मेरी सप्लीमैंटरी की डायरैक्ट रैलैवैंसी नहीं है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से सप्लीमैंटरी की बजाय बताना चाहूँगा कि दिल्ली, मथुरा और आगरा जो नैशनल हाइवे है वह बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। दिल्ली से जब चलते हैं और फरीदाबाद में एंट्री करते हैं तो अध्यक्ष महोदय, आपने भी अनुभव किया है कि बदरपुर में इतना नैरो पैसेज है, बोटल नैक है वहां सुबह और शाम दो-दो घण्टे तक जाम में हम फंस जाते हैं। फरीदाबाद पूरे उत्तरी भारत का इंडस्ट्रियल टाउन है, इससे वहाँ का बिजनैस इफैक्ट होता है। नैशनल हाइवे अथोरिटी ऑफ इण्डिया में कोई एलीवेटिड कोरीडोर बनाने का प्रपोजल पैण्डिंग पड़ा है और हम 20 सालों से

इसके लिए रो पीट रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से यह शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। इसलिए क्या इसके लिए कोई विशेष प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल बहुत अहम् है। वाकई बदरपुर के पास रोजाना ट्रैफिक जाम रहता है और कई-कई घंटों तक यह जाम लगा रहता है। हम पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार से इस मामले में जुड़े हुए हैं और उनसे हमारी खतोखिताबत जारी है और वे भी इस बात को सिद्धान्त रूप से मान रहे हैं कि वहां एक एलीवेटिड पुल बनना चाहिए। इसलिए इसके लिए हम केन्द्र सरकार से आग्रह कर सकते हैं, बार-बार जोर दे सकते हैं। हम प्रयासरत हैं और ज्यों ही वे इसका निर्णय करेंगे उनके निर्णय के बाद बहुत जल्द ही इस पुल को हम बना देंगे।

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, पूर्ण सिंह जी ने जो प्रश्न पूछा है वह रिलेवेंट सवाल है। मुख्य मंत्री महोदय जी जानते हैं कि हिसार बहुत बड़ा शहर हो गया है और आप जानते हैं नैशनल हाइवे वहां से गुजरता है वहां पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पर कमीशनर का ऑफिस भी है, वहां पर रेंज है, वहाँ इतनी बड़ी आबादी हो गई है। आप जानते हैं कि राजस्थान से राजगढ़ रोड और भिवानी साइड से उस पर ट्रैफिक आता है इसलिए वहां बाई-पास जरूरी है। बालसमंद रोड से दिल्ली हर हालत में बाई-पास बनना चाहिए। इससे भिवानी का सारा ट्रैफिक, बालसमंद साइड का ट्रैफिक, राजगढ़ का ट्रैफिक वहां से आकर बाहर निकल जाएगा। यह जरूरी भी है इस पर मुख्य मंत्री महोदय कुछ विचार करें और इस बाई पास को हर हालत में बनाया जाए। इस बारे में पहले भी प्रपोजल दी हुई है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी भजन लाल जी को बताना चाहूँगा कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। लेकिन यदि हम यह बता देंगे कि यह बाई-पास फलाना समय तक बन जायेगा तो विपक्ष के नेता कहेंगे कि यह प्रपोजल तो उनके समय की है। इसलिए मैं विपक्ष के नेता से स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि इस बारे इनकी कोई पुरानी प्रपोजल तो नहीं है।

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में जिस समय मैं मुख्य मंत्री था उस समय प्रपोजल बनाई थी। इन्होंने तो कुछ करना नहीं है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता के सदन को पूर्ण रूप से गुमराह किया है। इनके समय कि ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है। यदि ये इस तरह से सदन को गुमराह करेंगे तो इनकी खिलाफ ब्रिच ऑफ प्रीविलेज का मोशन भी आ सकता है। (विघ्न)

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में 7 साल पहले की प्रपोजल हमारे समय की है, 6 साल से तो हमारी सरकार नहीं है। लेकिन 7 साल पहले की प्रपोजल बाकायदा है और ****

श्री अध्यक्ष : यह रिकॉर्ड न किया जाये।

श्री रमेश कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे यहां अलग से कोई शुगर मिल नहीं थी लेकिन मुख्य मंत्री जी ने 50-60 करोड़ रुपये की लागत से हमारे यहां अलग से शुगर मिल बनवाई। इस मिल के लगने से जो हमारी तहसील के किसान हैं, जींद के किसान हैं वे शहर के अंदर से गन्ना लेकर निकलते हैं और पानीपत तथा सोनीपत के किसान भी ट्रैक्टर-ट्राले लेकर शहर के अंदर से ही निकलते हैं जिसके कारण गोहाना शहर में लोगों को बहुत परेशानी होती है। क्या गोहाना में जो सरकूलर रोड है वहां भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय कोई बाई-पास बनवायेंगे ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, जहां तक बाई-पास बनाने का ताल्लुक है इस बारे में मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूँगा कि इस समय ऐलनाबाद और सोनीपत के अंदर बाई-पास के लिए कार्य

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री राम पाल माजरा]

प्रगति पर है तथा झज्जर के लिए भूमि अधिग्रहण की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जैसा कि भजन लाल जी कह देते हैं कि फलानी प्रपोजल तो इनके समय की है, लेकिन इनके समय में जो भी प्रपोजल बनी थी इसके बाद एक पत्थर भी नहीं रखा गया। पता नहीं वे प्रपोजल कहां गईं। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने गोहाना में बाई-पास बनाने के बारे में प्रश्न पूछा था, माजरा साहब ने उसका तो जवाब दिया नहीं।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां बाई-पास बनाने जा रहे हैं उनके बारे में मैंने पूरे सदन को अवगत करवा दिया है। इसके अतिरिक्त ऐसा और कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या हथीन में भी कोई बाई-पास बनाया जायेगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह आश्वासन देना चाहूँगा कि हम लोगों के हितार्थ कहीं भी, किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे बशर्ते सरकार को आर्थिक दिक्कत न आये। अध्यक्ष महोदय, पैसे की हमारे पास कमी है लेकिन उसको ध्यान में रखते हुये चौधरी भजन लाल जी के समय की यदि कोई प्रपोजल है तो उसको हम प्राथमिकता के आधार पर लागू करेंगे।

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, भिवानी का बस स्टैण्ड दिल्ली रोड पर बनाया गया है। दिल्ली रोड से हांसी रोड तक, बस स्टैण्ड बनने के बाद, जो सड़क बनाये जाने की प्रोपोजल थी उसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि यह सड़क कब तक बनकर पूरी हो जायेगी।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए ये अलग से नोटिस दें क्योंकि इस वक्त इस बारे में बताया जाना असंभव है।

तारांकित प्रश्न सं. 831.

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री अमर सिंह ढांडे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Surplus Lecturers

***915. Sh. Bhag Singh Chhatar :** Will the Minister of State for Education be pleased to State --

(a) whether it is a fact that the Lecturers have been rendered surplus in Non-Government Colleges in the state during the year 2001 to 2002 till date on account of work-load; if so, the detail thereof ?

(b) If yes, in which Non-Government Colleges these lecturers have been adjusted ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ. बहादुर सिंह) : (क) तथा (ख) : हाँ, श्रीमान् जी। विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

शैक्षणिक सत्र 2001-2002 के लिए सरकारी सहायता-प्राप्त निजी महाविद्यालयों के शैक्षिक अमले के कार्यभार का आंकलन किया गया जिससे पता चला कि कुछ महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के 49 प्राध्यापक आवश्यकता से अधिक थे।

मानवीय आधार पर, सरकार ने ऐसे प्राध्यापकों को उन सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में समायोजित करने का निर्णय लिया, जहां उन विषयों के प्राध्यापकों की आवश्यकता थी। प्राध्यापकों से महाविद्यालयों/स्थानों के लिए विकल्प भी प्राप्त किये गये ताकि उन्हें कोई कठिनाई न हो। उनको वेतन सुरक्षण सहित निरन्तर सेवा का देय लाभ भी प्रदान किया गया।

ऐसे प्राध्यापकों तथा जिन महाविद्यालयों में उन्हें समायोजित किया गया है, का विवरण निम्नानुसार है :-

विषय : अर्थ शास्त्र

क्रमांक	प्राध्यापक का नाम	महाविद्यालय का नाम जहां प्राध्यापक आवश्यकता से अधिक था	महाविद्यालय का नाम जहां प्राध्यापक समायोजित किया गया
1.	डॉ. सुनीता गुप्ता	पब्लिक कन्या महाविद्यालय, रिवाड़ी	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी

विषय : रसायन शास्त्र

क्रमांक	प्राध्यापक का नाम	महाविद्यालय का नाम जहां प्राध्यापक आवश्यकता से अधिक था	महाविद्यालय का नाम जहां प्राध्यापक समायोजित किया गया
1.	श्री सूर्य प्रकाश	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	ए.आई.जाट महाविद्यालय, रोहतक
2.	डॉ. सुभाष सहगल	एस.ए. जैन महाविद्यालय, अम्बाला शहर	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
3.	श्रीमती रेणु मलिक	बी.पी.एस. कन्या महाविद्यालय, खानपुर कलां	ए.आई. जाट महाविद्यालय, रोहतक
4.	श्रीमती बीना सेठी	जी.जी.डी. एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	डी.एन. महिला महाविद्यालय, फरीदाबाद
5.	डॉ. सुरेन्द्र पाल भट्टी	डी.ए.वी. महाविद्यालय, अम्बाला शहर	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल
6.	श्री आर.एस. मुंजाल	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
7.	श्रीमती रीता सेठ	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	एम.एल.एन. महाविद्यालय, यमुनानगर
8.	श्री एम.के. जैन	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
9.	श्री एस.पी. गोयल	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	वैश्य महाविद्यालय, भिवानी

[चौ. बहादुर सिंह]

क्रमांक	प्राध्यापक का नाम	महाविद्यालय का नाम जहां प्राध्यापक आवश्यकता से अधिक था	महाविद्यालय का नाम जहां प्राध्यापक समायोजित किया गया
10.	श्रीमती वन्दना दुग्गल	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी
11.	श्रीमती रेणु वशिष्ठ	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	ए.आई जाट महाविद्यालय, रोहतक
12.	श्री एम.एल. गर्ग	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
13.	श्रीमती शशि सोलंकी	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार	डी.एन.महिला महाविद्यालय, फरीदाबाद
विषय : हिन्दी			
1.	डॉ. श्रीमती हरि किरण कौर	एस.एम.एस. खालसा लुबाना कन्या महाविद्यालय, बराड़ा (अम्बाला)	जी.एन.के. महाविद्यालय यमुनानगर
2.	श्री राम शर्मा	बी.पी.आर. महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
3.	डॉ. अशोक कुमार निराला	जी.जी.डी.एस.डी. महाविद्यालय पलवल	अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लबगढ़
4.	श्रीमती अनुरिता	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	कन्या महाविद्यालय, खरखौदा
5.	डॉ. श्रीमती कुसुम लता	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	एस.डी.महाविद्यालय, पानीपत
6.	डॉ. श्रीमती राजकुमारी शर्मा	आई.जी. महाविद्यालय, लाडवा (कुरुक्षेत्र)	आई.बी. महाविद्यालय, पानीपत
7.	डॉ. रामकुमार शर्मा	हिन्दू महाविद्यालय, सोनीपत	जी.एन. कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर
8.	श्री सुरेन्द्र कुमार	सी.आर.किसान महाविद्यालय, जींद	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार
विषय : भौतिक शास्त्र			
1.	श्री जितेन्द्र सिंह फोर	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद
2.	डॉ. महीपाल सिंह	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	ए.आई. जाट महाविद्यालय, रोहतक
3.	श्री प्रदीप अहलावत	के.एल.पी. महाविद्यालय, रिवाड़ी	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
4.	श्रीमती नवीन	के.एल.पी. महाविद्यालय, रिवाड़ी	अहीर महाविद्यालय, रिवाड़ी
5.	श्री सुशील कुमार	जी.जी.डी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	जी.एम. कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर

क्रमांक	प्राध्यापक का नाम	महाविद्यालय का नाम जहां प्राध्यापक आवश्यकता से अधिक था	महाविद्यालय का नाम जहां प्राध्यापक समायोजित किया गया
6.	श्री कृष्ण कांत गुप्ता	जी.जी.डी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	डी.एन. महिला महाविद्यालय, फरीदाबाद
7.	श्री आर.पी. तंवर	जी.जी.डी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
8.	डॉ. के.सी. गोयल	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	वैश्य महाविद्यालय, भिवानी
9.	श्रीमती मंजु अरोड़ा	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी
10.	श्री आर.पी. सिंह	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
11.	श्री अतर सिंह	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार	वैश्य महाविद्यालय, भिवानी
12.	श्री प्रेम सिंह	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
13.	श्री एस.सी. गुप्ता	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
14.	श्री मोहन लाल गुप्ता	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
15.	श्री एम.पी. अग्रवाल	आर्य महाविद्यालय, पानीपत	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
16.	श्री एम.सी.गुप्ता	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	हिन्दू महाविद्यालय, सोनीपत
17.	सुश्री शोभा खेड़ा	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	हिन्दू महाविद्यालय, सोनीपत
विषय : वनस्पति विज्ञान			
1.	डॉ. राज बंसल	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पेहवा	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
2.	श्री संजीव कुमार	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जगाधरी
3.	श्री वी.पी. कामरा	हिन्दू महाविद्यालय, सोनीपत	ए.आई.जाट महाविद्यालय, रोहतक (माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश)
विषय : प्राणि विज्ञान			
1.	डॉ. मन्जू मल्होत्रा	डी.ए.वी. महाविद्यालय, अम्बाला शहर	के.वी.ए.डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, करनाल
2.	श्रीमती शारदा	सी.आर.ए.महाविद्यालय, सोनीपत	ए.आई. जाट महाविद्यालय, रोहतक
3.	श्री एच.के. कस्सब	एम.एन. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाहबाद (कुरुक्षेत्र)	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर

[चौ. बहादुर सिंह]

क्रमांक	प्राध्यापक का नाम	महाविद्यालय का नाम जहां प्राध्यापक आवश्यकता से अधिक था	महाविद्यालय का नाम जहां प्राध्यापक समायोजित किया गया
विषय : गणित			
1.	श्री पी.के. खुराना	एन.बी.जी.एस. मैमोरियल महाविद्यालय, सोहना	ए.आई. जाट महाविद्यालय, रोहतक
विषय : वाणिज्य			
1.	श्री अजय शर्मा	डी.ए.वी. महाविद्यालय, चीका	आर.के.एस.डी. महाविद्यालय, कैथल
विषय : अंग्रेजी			
1.	डॉ. सुषमा शर्मा	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	एस.ए.जैन महाविद्यालय, अम्बाला शहर
2.	डॉ. अंजु जैन	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	एस.ए. जैन महाविद्यालय, अम्बाला शहर

श्री भाग सिंह छातर : अध्यक्ष महोदय, क्या यह तथ्य सही है कि राज्य में वर्ष 2001 से 2002 आज तक के दौरान कार्यभार के हिसाब से गैर सरकारी महाविद्यालयों में प्राध्यापक अतिरिक्त दिखलाए गए हैं, यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है, और किन-किन गैर सरकारी महाविद्यालयों में वे प्राध्यापक समायोजित किए गए हैं।

चौ. बहादुर सिंह : सर, जो सूचना इन्होंने मांगी थी, वह मैंने पहले ही सदन के पटल पर रख दी है। यह काफी लम्बी चौड़ी लिस्ट है। स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से सदन को बताना चाहूँगा कि शैक्षणिक सत्र 2001-2002 के लिए सरकारी सहायता-प्राप्त निजी महाविद्यालयों के शैक्षिक अमले के कार्यभार का आकलन किया गया जिससे पता चला कि कुछ महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के 49 प्राध्यापक आवश्यकता से अधिक थे।

मानवीय आधार पर, सरकार ने ऐसे प्राध्यापकों को उन सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालयों में समायोजित करने का निर्णय लिया, जहां उन विषयों के प्राध्यापकों की आवश्यकता थी। प्राध्यापकों से महाविद्यालयों/स्थानों के लिए विकल्प भी प्राप्त किये गये ताकि उन्हें कोई कठिनाई न हो। उनको वेतन सुरक्षण सहित निरन्तर सेवा का देय लाभ भी प्रदान किया गया।

ऐसे प्राध्यापकों तथा जिन महाविद्यालयों में उन्हें समायोजित किया गया है, का विवरण निम्नानुसार हैं :-

विषय : अर्थ शास्त्र

क्रमांक	प्राध्यापक का नाम	महाविद्यालय का नाम जहां प्राध्यापक आवश्यकता से अधिक था	महाविद्यालय का नाम जहां प्राध्यापक समायोजित किया गया
1.	डॉ. सुनीता गुप्ता	पब्लिक कन्या महाविद्यालय, रिवाड़ी	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी
विषय : रसायन शास्त्र			
1.	श्री सूर्य प्रकाश	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	ए.आई.जाट महाविद्यालय, रोहतक

क्रमांक	प्राध्यापक का नाम	महाविद्यालय का नाम जहां प्राध्यापक आवश्यकता से अधिक था	महाविद्यालय का नाम जहां प्राध्यापक समायोजित किया गया
2.	डॉ. सुभाष सहगल	एस.ए. जैन महाविद्यालय, अम्बाला शहर	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
3.	श्रीमती रेणु मलिक	बी.पी.एस. कन्या महाविद्यालय, खानपुर कलां	ए.आई. जाट महाविद्यालय, रोहतक
4.	श्रीमती वीना सेठी	जी.जी.डी. एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	डी.एन. महिला महाविद्यालय, फरीदाबाद
5.	डॉ. सुरेन्द्र पाल भट्टी	डी.ए.वी. महाविद्यालय, अम्बाला शहर	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल
6.	श्री आर.एस. मुंजाल	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
7.	श्रीमती रीता सेठ	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	एम.एल.एन. महाविद्यालय, यमुनानगर
8.	श्री एम.के. जैन	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
9.	श्री एस.पी. गोयल	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	वैश्य महाविद्यालय, भिवानी
10.	श्रीमती वन्दना दुग्गल	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी
11.	श्रीमती रेणु वशिष्ठ	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	ए.आई जाट महाविद्यालय, रोहतक
12.	श्री एम.एल. गर्ग	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
13.	श्रीमती शशि सोलंकी	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार	डी.एन.महिला महाविद्यालय, फरीदाबाद
विषय : हिन्दी			
1.	डॉ. श्रीमती हरि किरण कौर	एस.एम.एस. खालसा लुबाना कन्या महाविद्यालय, बराड़ा (अम्बाला)	जी.एन.के. महाविद्यालय यमुनानगर
2.	श्री राम शर्मा	बी.पी.आर. महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
3.	डॉ. अशोक कुमार निराला	जी.जी.डी.एस.डी. महाविद्यालय पलवल	अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लबगढ़
4.	श्रीमती अनुरित्ता	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	कन्या महाविद्यालय, खरखौदा
5.	डॉ. श्रीमती कुसुम लता	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	एस.डी.महाविद्यालय, पानीपत
6.	डॉ. श्रीमती राजकुमारी शर्मा	आई.जी. महाविद्यालय, लाडवा (कुरुक्षेत्र)	आई.बी. महाविद्यालय, पानीपत

[चौ. बहादुर सिंह]

क्रमांक	प्राध्यापक का नाम	महाविद्यालय का नाम जहां प्राध्यापक आवश्यकता से अधिक था	महाविद्यालय का नाम जहां प्राध्यापक समायोजित किया गया
7.	डॉ. रामकुमार शर्मा	हिन्दू महाविद्यालय, सोनीपत	जी.एन. कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर
8.	श्री सुरेन्द्र कुमार	सी.आर.किसान महाविद्यालय, जींद	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार
विषय : भौतिक शास्त्र			
1.	श्री जितेन्द्र सिंह फोर	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद
2.	डॉ. महीपाल सिंह	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	ए.आई. जाट महाविद्यालय, रोहतक
3.	श्री प्रदीप अहलावत	के.एल.पी. महाविद्यालय, रिवाड़ी	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
4.	श्रीमती नवीन	के.एल.पी. महाविद्यालय, रिवाड़ी	अहीर महाविद्यालय, रिवाड़ी
5.	श्री सुशील कुमार	जी.जी.डी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	जी.एन. कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर
6.	श्री कृष्ण कांत गुप्ता	जी.जी.डी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	डी.एन. महिला महाविद्यालय, फरीदाबाद
7.	श्री आर.पी. तंवर	जी.जी.डी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
8.	डॉ. के.सी. गोयल	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	वैश्य महाविद्यालय, भिवानी
9.	श्रीमती मंजु अरोड़ा	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी
10.	श्री आर.पी. सिंह	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
11.	श्री अतर सिंह	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार	वैश्य महाविद्यालय, भिवानी
12.	श्री प्रेम सिंह	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
13.	श्री एस.सी. गुप्ता	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
14.	श्री मोहन लाल गुप्ता	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
15.	श्री एम.पी. अग्रवाल	आर्य महाविद्यालय, पानीपत	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
16.	श्री एम.सी.गुप्ता	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	हिन्दू महाविद्यालय, सोनीपत
17.	सुश्री शोभा खेड़ा	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	हिन्दू महाविद्यालय, सोनीपत

क्रमांक	प्राध्यापक का नाम	महाविद्यालय का नाम जहां प्राध्यापक आवश्यकता से अधिक था	महाविद्यालय का नाम जहां प्राध्यापक समायोजित किया गया
विषय : वनस्पति विज्ञान			
1.	डॉ. राज बंसल	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पेहवा	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
2.	श्री संजीव कुमार	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जगाधरी
3.	श्री वी.पी. कामरा	हिन्दू महाविद्यालय, सोनीपत	ए.आई.जाट महाविद्यालय, रोहतक (माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश)
विषय : प्राणि विज्ञान			
1.	डॉ. मन्जू मल्होत्रा	डी.ए.वी. महाविद्यालय, अम्बाला शहर	के.वी.ए.डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, करनाल
2.	श्रीमती शारदा	सी.आर.ए.महाविद्यालय, सोनीपत	ए.आई. जाट महाविद्यालय, रोहतक
3.	श्री एच.के. कस्सब	एम.एन. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाहबाद (कुरुक्षेत्र)	जी.एन.के. महाविद्यालय, यमुनानगर
विषय : गणित			
1.	श्री पी.के. खुराना	एन.बी.जी.एस. मैमोरियल महाविद्यालय, सोहना	ए.आई. जाट महाविद्यालय, रोहतक
विषय : वाणिज्य			
1.	श्री अजय शर्मा	डी.ए.वी. महाविद्यालय, चीका	आर.के.एस.डी. महाविद्यालय, कैथल
विषय : अंग्रेजी			
1.	डॉ. सुषमा शर्मा	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	एस.ए.जैन महाविद्यालय, अम्बाला शहर
2.	डॉ. अंजु जैन	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	एस.ए. जैन महाविद्यालय, अम्बाला शहर

चौ. भजन लाल : स्पीकर सर, हमने पढ़ा हुआ मान लिया। (विघ्न एवं शोर)

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, ये सन्तुष्ट हो गए हैं। (विघ्न एवं शोर) इनकी सन्तुष्टि हो गई है। (विघ्न एवं शोर)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, एक दफा हमने बहुत प्रयास किया था। मांगे राम गुप्ता जी तब बजट पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि पढ़ा हुआ मान लिया लेकिन ये लोग उस बात को नहीं माने थे। (विघ्न एवं शोर) हमने कहा तो बहुत था लेकिन माने तो कोई नहीं (विघ्न) आप भी नहीं माने थे लेकिन हमने फिर भी मान तो लिया (विघ्न)

चौ. भजन लाल : अगली बार मान लेंगे। (विघ्न एवं शोर)

प्रो. राम भगत : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार और विशेष कर शिक्षा मंत्रालय ने जिस ढंग से मेरे रिट्रैन्च होने वाले साथियों को दूसरे कॉलेजिज में समायोजित किया है, ऐडजस्ट किया है, उसके लिए सरकार ने बहुत रहमदिली दिखाई है और अपने कर्मचारियों तथा अध्यापक हितैषी नजरिये का उन्होंने प्रदर्शन किया है उसके लिए मैं हरियाणा सरकार का और शिक्षा विभाग का धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो प्रोफैसर साहेबान समायोजित हुए हैं या जिनकी ऐडजस्टमैंट हुई है और वे दूसरे कॉलेजों में गए हैं यदि उनके अपने पेरैन्ट कॉलेज में दोबारा कोई वैकेन्सी क्रिएट होती है तो क्या उनको वापिस भेजने का कोई प्रावधान रखा गया है, इस बारे में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

चौ. बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जितने अध्यापकों को दूसरे कॉलेजिज में भेजा गया है उनकी ऑप्शन लेकर ही भेजा गया है तथा उनकी पे प्रोटैक्शन, कॉन्टिन्यूऐशन इन सर्विस जैसी सारी सहूलियतें उनको दी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय साथी ने पूछा है तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि यदि ऐसी कोई डिमान्ड आएगी तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लिया जाएगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि जो इन्होंने यह आकलन किया है कि प्राध्यापक आवश्यकता से अधिक पाए गए, इसका बेसिस क्या था। क्या उनका निर्धारण यू.जी.सी. के फार्मूले पर किया जाता है या यूनिवर्सिटी द्वारा तय किसी फार्मूले के द्वारा किया जाता है या इस का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है जिससे यह तय हो सके कि कितने काम के लिए कितने प्राध्यापकों की आवश्यकता है और किस आधार पर इनको सरप्लस किया गया है ?

चौ. बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए यूनिवर्सिटी ने नॉर्म्ज फिक्स कर रखे हैं उसके आधार पर इनको सरप्लस किया गया है। अगर यह इसका आधार जानना चाहते हैं तो काफी लम्बा चौड़ा है। अगर यह लिख कर देंगे तो मैं इसका सारा विवरण इनको बता दूंगा कि इसके लिये क्या-क्या प्रोविजन्ज हैं और क्या क्या नॉर्म्ज हैं जिनके आधार पर इन्हें सरप्लस किया गया है।

Setting up of 33KV Sub-station at Jarpur

*956. **Rao Dan Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state --

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to set up 33KV new sub-station in village Jairpur district Mahendergarh ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be set up ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : (क) एवं (ख) : हां श्रीमान्, 125.00 लाख रुपये की लागत से गांव जैरपुर जिला महेन्द्रगढ़ में 33 के.वी. उपकेन्द्र को लगाने का प्रस्ताव है। इसे, 220 के.वी. उपकेन्द्र महेन्द्रगढ़ के पूर्ण होने के बाद, वर्ष 2003 में, 132 के.वी. उपकेन्द्र महेन्द्रगढ़ की क्षमता बाधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण के लिए लिया जाएगा।

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जैरपुर मण्डोला वह जगह है जो मण्डयाली के किसानों का एजिटेशन का केन्द्र बिन्दु था और वहां पर कृषि ट्यूबवैल्ज पर आधारित है। अध्यक्ष महोदय, पहले तो वहां पर बिजली आती ही नहीं है और आती है तो ओवर लोड की वजह से ट्रांसफार्मर्ज का जलना एक आम सी बात है। जब

किसान का फसल में पानी देने का समय आता है तो वह जले हुए ट्रांसफार्मर की तरफ देखता है। वह उनको ठीक करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट-काट कर परेशान हो जाता है। अभी सी.पी.एस. महोदय, ने बताया कि यह सब-स्टेशन 2003 तक अप-ग्रेड करने का मामला प्रस्तावित है। मैं आपके माध्यम से सी.पी.एस. महोदय को बताना चाहता हूँ कि लोग और किसान जले हुए ट्रांसफार्मर्ज से परेशान हैं और उन ट्रांसफार्मर्ज को ठीक करने में एक-एक महीना लग जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, ये कहते हैं ट्रांसफार्मर्ज जल जाते हैं और इन्होंने यह भी कहा है कि वहाँ पर उसके अलावा और कोई साधन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने इनको भली-भांति आंका है और इस बात को मद्देनजर रखते हुए रिकॉर्ड तोड़ समय में बवानिया में 33 के.वी. का सब-स्टेशन 60 लाख रुपये की लागत से 6 महीने में तैयार करके चालू कर दिया है। इसी प्रकार से इन्हीं के क्षेत्र महेन्द्रगढ़ के डवलाना में 33 के.वी. का सब-स्टेशन 60 लाख की लागत से 6 महीने के रिकॉर्ड तोड़ समय में तैयार किया है। 33 के.वी. का सब स्टेशन गड़ीमासर में 70 लाख की लागत से चालू किया गया है। उनकी क्षमता इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि वे ओवर लोडिड थे और ओवर लोड होने की वजह से वे जल जाते थे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से नारनौल जिले में 220 के.वी. सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाई गई है और इस पर 60 लाख रुपये लगे हैं। 132 के.वी. के सब स्टेशन महेन्द्रगढ़ की क्षमता 60 लाख रुपए लगा कर बढ़ाई गई है। इसी प्रकार से अटाली, 132 के.वी. सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाई गई हैं। 132 के.वी. सब-स्टेशन कनीना खास की क्षमता बढ़ाई गई है। 132 के.वी. सब-स्टेशन नांगल चौधरी की क्षमता बढ़ाई गई हैं। 33 के.वी. सब-स्टेशन नीजामपुर की, 33 के.वी. सब-स्टेशन गुड़ियाखेड़ा की और 33 के.वी. सब-स्टेशन झाड़कल की क्षमता बढ़ाई गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दान सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठें अभी मंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं। वे आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, हमने पूरे जिले में जो क्षमता बढ़ाई है उसके लिए इनको सरकार का धन्यवाद करना चाहिए और ये अब इस तरह की बात कर रहे हैं। यह जो ट्रांसफार्मर्ज वाली बात इन्होंने कही है इस बारे में कहना चाहूँगा कि अभी मैंने पूरा रिप्लाई नहीं दिया है ये पहले रिप्लाई सुन लें उसके बाद अपनी बात कहें। यह लाइनों पर लोड वाली बात है तो इस बारे में हमने पूरी तरह से एग्जामिन करके लाइनों की क्षमता बढ़ाई है जो इस प्रकार से है। 33 के.वी. अटेली लाइन की, 33 के.वी. महेन्द्रगढ़ लाइन की और 33 के.वी. डवलाना लाइन की क्षमता बढ़ाई गई है। स्पीकर सर, इनकी इस बात को मद्देनजर रखते हुए और सब-स्टेशन लगाए जाएं तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने नए सब-स्टेशनों को लगाए जाने के बारे में भी एक योजना बनाई है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, दान सिंह जी हंस रहे हैं और इन्हें सब बातों का पता है। आज रिमार्केबल काम हो रहा है। बिजली के मामले में 220 के.वी. का सब-स्टेशन महेन्द्रगढ़ में बनाने जा रहे हैं। 132 के.वी. का सतनाली में, 132 के.वी. का मुड़ियाखेड़ा में और 33 के.वी. का जैरपुर में सब स्टेशन बनाने जा रहे हैं। जहां तक क्षमता बढ़ाने की बात है, तो इसमें 220 के.वी. नारनौल की, 33 के.वी. भोजावास की, 33 के.वी. धनिना की, 33 के.वी. निजामपुर की और 33 के.वी. बाडरा की क्षमता बढ़ाई गई है। इसी प्रकार से इन्होंने पूछा है कि कितने नए सब-स्टेशन बनाए जा रहे हैं और कितनों की क्षमता बढ़ाई जा रही है तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि जितने भी सब-स्टेशंज की कैपेस्टी बढ़ाई जा रही है वह इसलिए बढ़ाई जा रही है ताकि ट्रांसफार्मर्ज न जलें और किसानों को फ्रिक्वेंटली पूरी बिजली मिले। स्पीकर सर, पूरे प्रदेश में जहां पर भी ट्रांसफार्मर्ज जलने की बात आई वहां उसको तुरन्त बदला गया है हमारी सरकार की उनको तुरन्त बदलने की पॉलिसी है और वे बदले जा रहे हैं। इनके टाइम में तो ट्रांसफार्मर्ज बदलना काफी समय तक रोक दिया गया था। हमारे वक्त में तो इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है कि ट्रांसफार्मर्ज नहीं बदले गए हैं। स्पीकर सर, वे बदले जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती अनीता यादव : स्पीकर सर, सदन में भाषण देने से और आंकड़े बताने से काम नहीं चलता है। स्पीकर सर, माननीय मुख्य मंत्री जी 29-12-2001 को हमारे क्षेत्र में आए थे और कोसली के लोगों ने यह बताया था 132 के.वी. का पावर हाउस सब-स्टेशन है यह ओवर लोडिड है। इसके बारे में हमारे ग्रामीण लोगों ने और किसानों ने मुख्य मंत्री जी के सामने प्रस्ताव भी रखा था। स्पीकर सर, हमारा नाहड़ फीडर ओवर लोड चल रहा है इसकी सैटिंग बार-बार करनी पड़ती है। अगर इस ट्रांसफार्मर को 4 एम.वी.ए. से बदल कर 6.83 एम.वी.ए. किया जाएगा तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। उस समय झज्जर के ऐक्सियन लाला जी थे उन्होंने मुख्य मंत्री जी के सामने हां भी भर दी थी और कहा था कि यह दो दिन में चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, 29-12-2001 से लेकर आज तक इस बारे में न तो किसी ऐक्सियन के कान पर जू रेंगी और न किसी और के कान पर। मैं उनको बताना चाहूँगी कि इसका क्या समाधान हो सकता है। या तो गांव विशोहा के सब-स्टेशन को 4 एम.वी.ए. से 6 एम.वी.ए. कर दिया जाए या उस गांव में 33 के.वी. का एक पावर हाउस बना दिया जाए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा कर दिया जाता है तो वहां के टेल के जितने भी गांव हैं उनकी समस्या का समाधान हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, यहां केवल आश्वासनों से काम नहीं चल सकता बल्कि यह समस्या तो काम करने से ही हल हो सकती है।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, दान सिंह बाहर चले गए। जहां तक इस मेन प्रश्न का ताल्लुक है, यह केवल दान सिंह के एक गांव में एक सब-स्टेशन लगाने के बारे में था और मैंने उनको इस बारे में सारी वस्तुस्थिति बता दी है। वे यहां से संतुष्ट होकर चले गए हैं अन्यथा अगर उनके सवाल का जवाब पूरा नहीं होता तो वे सवाल बीच में ही छोड़कर न जाते। वे संतुष्ट होकर चले गए हैं। बहन जी ने कहा कि यहाँ लच्छेदार भाषण दिए जाते हैं मैं उनको कहना चाहूँगा कि हमें तो सारी दुनिया ही ऐसी लगती है। अगर वे सारी बातें सुनेंगी तो उनको मालूम हो जाएगा। सर, यह प्रश्न स्पेशली दान सिंह का था। मैंने बिजली के बारे में यहां पर पूरे प्रदेश की प्रगति रिपोर्ट बताथी थी, सब-स्टेशंज के बारे में बताया था। फीडर्ज की बायफरकेशंज के बारे में बताया था। मैंने यह भी बताया था कि किस-किस तरह से सरकार सात सौ करोड़ रुपये बिजली पर खर्च कर रही है। उस वक्त तो जय प्रकाश जी भी कहने लगे थे कि हम यह बातें नहीं सुनते इनको बंद कर दो। स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश की प्रगति का जब प्रश्न आया था तो ये उस समय सुनना नहीं चाहते थे उस समय इनके पेट में मरोड़ लगती थी। इनको केवल हरियाणा विनाश के रूप में ही याद आता है। (विघ्न) स्पीकर सर ये हरियाणा के विनाश की बात बहुत जोर से सुनते हैं लेकिन बिजली के मामले में, सड़कों के मामले में या हरियाणा के विकास के मामले की बातें ये सुनना ही नहीं चाहते। स्पीकर सर, बहन जी के प्रश्न का जहां तक संबंध है अगर ये कहेंगी और लिखकर दे देंगी तो हम उसको ऐग्जामिन करवा लेंगे। परन्तु जब यहां पर प्रदेश के विकास की आंधी की बात आती है, प्रगति की बात आती है तो यह उठकर चल देते हैं। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, ये लाइन लौसिज के बारे में भी बता दें।

श्री राम पाल माजरा : लाइन लौसिज के बारे में भी मैंने बताया था कि हमने इनको कम कर दिया और इस बारे में एक टारगेट भी रख दिया है। मैं तो इस बारे में पहले ही बता चुका हूँ लेकिन आप उस वक्त सुनना ही नहीं चाहते थे। स्पीकर सर, जब मैं इस बारे में बताता हूँ तो कैप्टन साहब लिखते रहते हैं। स्पीकर सर, यह विशेष प्रश्न तो दान सिंह जी का था और वे संतुष्ट हैं। बहन जी तो कभी लिखकर ही नहीं देती हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दान सिंह जी, अब आप बैठें।

श्री जसबीर मलौर : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सी.पी.एस. साहब को और हरियाणा सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे प्रदेश में बिजली के कार्यों की झड़ी लगाकर जितना काम किया है उसको हमारे विपक्ष के साथी लच्छेदार भाषण कहकर टाल देते हैं। जहां पूरे प्रदेश में इस बारे में विकास हुआ है

वहीं मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी नये सब स्टेशंज स्थापित किए जा रहे हैं। वह भी इससे अछूता नहीं है। मेरे हल्के में 220 के.वी. का सब-स्टेशन तेपला और 66 के.वी. का सब-स्टेशन बखेड़ी में मंजूर हुआ है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन सब स्टेशंज को जल्दी पूरा करवाया जाए। अगर वहाँ पर 33 के.वी. का सब स्टेशन लगाने की जरूरत है तो वह लगाया जाए क्योंकि वहां पर लोगों को फसलों के समय पर बड़ी दिक्कत होती है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे दुराना गांव में भी एक 33 के.वी. का सब-स्टेशन लगवाएं। जहां पूरे हरियाणा प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में सब-स्टेशंज लगाए जा रहे हैं तो वहां पर एक सब-स्टेशन मेरे हल्के में भी देने की कृपा करें।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मेरे साथी ने जो प्रश्न किया उसके बारे में उनको बताना चाहूँगा कि इसके लिए पूरी एक योजना होती है। ईयरवाइज इस बारे में शिडयूल बनाया हुआ है कि यह सब-स्टेशंज आगुमैन्ट होंगे इन की क्षमता बढ़ाई जायेगी और ये नये लगेंगे। अगर फिर भी माननीय सदस्य गांव के लोगों की तरफ से लिखकर रिप्रेजेंटेशन दे दें तो इसको भी एग्जामिन करवा लेंगे। मुझे आदरणीय चौटाला साहब ने आदेश किया है कि यह महिला सशक्तिकरण वर्ष है इसलिए जहां पार्लियामैंट में राज्य सभा में हम एक महिला मैंबर चुनकर भेजेंगे। बहन अनीता जी उठकर चली गई हैं। मैं कहना चाहूँगा उनको भी आप विश्वास दिलाओ कि कोसली का सब-स्टेशन भी हम बहुत जल्द ही ऑगमैंट करवाएंगे। वे उठकर चली गई हैं इसी बात से पता चल जाता है कि वे अपने क्वेश्चन के प्रति कितनी सीरियस हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) आपको भी सिखाना पड़ेगा, आप भी वैसे ही खड़े हो जाते हैं।

Power House, Bhora Kalan

***962. Sh. Ram Bir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the Power House of Bhora Kalan in the Pataudi Constituency is likely to be commissioned ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : जिला गुड़गांव के पटौदी निर्वाचन क्षेत्र के भौड़ाकलां में कनैक्टिंग 66 के.वी. लाइन के साथ एक नया 66 के.वी. उपकेन्द्र 2.15 करोड़ रुपए अनुमानित लागत से निर्माणाधीन है, इस उपकेन्द्र का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, वहीं प्रसार लाइन का निर्माण कार्य स्थानीय न्यायालय द्वारा रोक आदेश प्राप्त करने के कारण रोक दिया गया है। रोक आदेश हटने की तिथि के बाद यह उपकेन्द्र तीन महीने के अंदर-अंदर चालू हो जाएगा।

श्री रामबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में जिस किसान ने स्टे ऑर्डर लिया था उससे हमने बात की है और इसी महीने में इस केस को वह विदड्रा कर लेगा। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा कि गुड़गांव कॉस्टीच्यूएंसी में गढ़ीहरसरू 66 के.वी. के बिजली घर का निर्माण कब तक हो जाएगा ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मेरे साथी ने खुद ही बताया कि अभी तक केस अदालत में है। जिसकी तरफ से कंप्लेंट है, अगर वह विदड्रा कर लेगा उसके तीन महीने में यह उपकेन्द्र चालू कर दिया जाएगा। जहां एक इनके दूसरे सवाल की बात है, गढ़ीहरसरू सब-स्टेशन अंडर कंसीड्रेशन है हम इसको ऐग्जामिन कर रहे हैं। जहां तक इनके मेन सवाल की बात है वह 100 प्रतिशत पूरा हो चुका है उपकेन्द्र बन गया है, टॉवर लग गया है, पूरा काम कंप्लीट है, केवल कोर्ट के आदेश या उसके विदड्राल का इंतजार है। जिस दिन यह आ जाए, उसकी कॉपी मुझे दे दें, उसके तीन महीने के अंदर-अंदर यह उपकेन्द्र चालू हो जाएगा।

श्री रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि आप इजाजत दें तो जो बहन अनीता यादव ने सवाल किया था उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछ सकते हैं जवाब मंत्री जी देंगे।

श्री रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छी बात है कि माननीय सदस्या अपने हल्के के प्रति बहुत चिंतित हैं और हर समय अपने हल्के की समस्याओं को बड़े अच्छे ढंग से उजागर करती हैं लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि जिस दिन साल्हावास विधान सभा क्षेत्र में "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य मंत्री जी गए हुए थे उस दिन इत्तेफाक से मैं भी इनके हल्के में खानपुर गया हुआ था और माननीय मुख्य मंत्री जी जनहित की घोषणाएं कर रहे थे। मैंने अनीता जी से कहा था कि मुख्य मंत्री जी आपके हल्के में आए हैं आप यहां क्या कर रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

15-00 बजे अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी इनके हल्के साल्हावास में 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत गये थे तो मैंने माननीय सदस्या को कहा कि अपने हल्के की मांगे माननीय मुख्य मंत्री के सामने रख दो परन्तु माननीय सदस्या किसी सांस्कृतिक समारोह के देखने में व्यस्त थी और इन्होंने माननीय मुख्य मंत्री के सामने अपने हल्के की एक भी मांग नहीं रखी।

श्री अध्यक्ष : अब क्वेश्चन आवर समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Realisation from Power Utilities

*836. **Sh. Padam Singh Dahiya :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any assessment of revenue realisation and collection efficiency in the working of Power Utilities during 2000-2001 ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हाँ श्रीमान्, वर्ष 2000-2001 के दौरान राजस्व वसूली में 373 करोड़ रुपए का सुधार हुआ जोकि वर्ष 1999-2000 की तुलना में 20 प्रतिशत की एक वृद्धि है। इसी तरह, कलैक्शन क्षमता में 5 प्रतिशतता प्वाइंटों की वृद्धि हुई।

Computer centres in Districts

*897. **Shri Ramesh Kumar Khatak :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to set up Computer Centre in each district ; if so, the details thereof ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ. बहादुर सिंह) : हाँ, श्रीमान् जी, राज्य के हर जिले में कम्प्यूटर केन्द्र खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। 2001-2002 में सभी 19 जिलों के लिए एक-एक कम्प्यूटर केन्द्र खोलने हेतु 11वें वित्त आयोग ने 735 लाख रुपये की धन राशि प्रदान की है।

यह कम्प्यूटर केन्द्र विद्यार्थियों को अच्छी कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, यह केन्द्र कम्प्यूटर के प्रयोग हेतु शिक्षण सामग्री एवं सहायक के रूप में प्रशिक्षण देंगे। यह केन्द्र अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों

को भी कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और साथ ही विद्यार्थियों को विशेष व्यवसाय आधारित प्रशिक्षण देंगे। यह केन्द्र निजी वित्तीय व्यवस्था के आधार पर चलाए जाएंगे।

Repair of Roads

***850. Shri Sher Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state --

(a) whether it is a fact that the following roads in District Jind have been damaged badly :--

(i) Jind-Rohtak Road to village Buradehar ;

(ii) Gatauli to Shamlokalan ;

(iii) Kerala to Uglana ; and

(b) if so, the time by which the repair work of said roads is likely to be started/completed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : (क) तथा (ख) : प्रश्नाधीन सड़कों की मरम्मत 31 दिसम्बर, 2003 तक कर दी जाएगी।

Water works for Jhajjar City

***1002. Sh. Daryao Singh Rajora :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Water Works for Jhajjar City and any village of Jhajjar Constituency ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : जी हाँ श्रीमान्। झज्जर शहर की जलापूर्ति में बढ़ौतरी की एक योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में सम्मिलित की गई है। झज्जर निर्वाचन क्षेत्र के चार जलधरों, कासनी, खापरवास, मछरौली और खुडान, जिनमें 13 गांव सम्मिलित हैं, का कार्य प्रगति पर है।

Repairs of Roads of Rohtak City

***948. Shri Shadi Lal Batra :** Will the Minister of State for Urban Development be pleased to state --

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the damaged roads of Rohtak City ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be repaired ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) :

(अ) हाँ, श्रीमान् जी।

(ब) रोहतक नगर की विभिन्न बस्तियों में 13.472 कि.मी. सड़कों/गलियों की मरम्मत चालू वित्त वर्ष के दौरान पहले ही पूरी की जा चुकी है। अन्य 10 कि.मी. सड़कों की मरम्मत का कार्य 31 मार्च, 2002 तक पूर्ण किये जाने की संभावना है।

Setting up of New Power Sub-station

***1012. Sh. Ranbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state --

[श्री रणबीर सिंह]

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to set up a new Power sub-station in Badhra constituency ;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to replace the iron poles and obsolete wires in Badhra constituency ; and

(c) the quantum of electricity is being supplied to the Badhra constituency at present together with the break up since 1996, year wise ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) नहीं श्रीमान्, बाढ़डा, अटेलाकलां तथा झोजू में तीन 132 के.वी. उपकेन्द्र तथा बेरला, रुद्रोल, कादमा, मांढ़ी तथा लाड में पांच 33 के.वी. उपकेन्द्र पहले ही हैं जो बाढ़डा निर्वाचन क्षेत्र में गांव की बिजली आपूर्ति को पूरी कर रहे हैं।

(ख) लोहे के खम्बे, सीमेंट के खम्बों के साथ बदले जा रहे हैं तथा घिसे-पिटे तारों को एक चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है।

(ग) बाढ़डा निर्वाचन क्षेत्र में 1996 से लेकर अब तक आपूर्ति की गई बिजली की मात्रा का विवरण निम्न प्रकार से है —

वित्तीय वर्ष	आपूर्ति की गई बिजली की यूनिट/लाखों में/	वर्ष 1996-97 से आगे वृद्धि का प्रतिशत
1996-97	1466	--
1997-98	1259	-14.12 प्रतिशत
1998-99	1423	-2.93 प्रतिशत
1999-2000	2057	40.31 प्रतिशत
2000-2001	2151	46.73 प्रतिशत
2001-2002 /फरवरी 2002 तक/	2104 /फरवरी 2002 तक/	57.72 प्रतिशत /1996-1997, फरवरी 1997 तक के साथ तुलना करके/

Construction of Stud on Yamuna

***958. Sh. Udai Bhan :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to erect any stud on the Yamuna River to check the soil erosion of the villages of Distt. Faridabad adjacent to the said River ; and

(b) if so, the time by which the work of the said stud is likely to be started ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) हाँ श्रीमान् जी।

(ख) ठोकर (स्टड) का कार्य मई, 2002 में शुरू करने की सम्भावना है।

Repair/Construction of Roads

***1031. Sh. Ram Kumar Nagura :** Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) whether there is any proposal under consideration for the construction of the following Roads of Rajaund constituency :–

(i) Dhatrarh to Aleva ;

(ii) Tidhana Bus Stand to Ritoli ; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the road from Pegga to Katwal ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : (क) तथा (ख) : नहीं, श्रीमान् जी। ये सड़कें पहले ही निर्मित हैं।

Death occured in Police custody

***1049. Shri Krishan Pal :** Will the Chief Minister be pleased to state -- The number of death, if any, occurred in police custody in the State during the year 2000-2001 and 2001-2002.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : राज्य में वर्ष 2000-2001 के दौरान 4 व्यक्तियों की व 2001-2002 के दौरान भी 4 व्यक्तियों की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई।

Selection Grade for School Lecturers

***910. Sh. Balwant Singh :** Will the Minister of State for Education be pleased to state whether the Lecturers of School cadre, who fall in the ambit of 20% quota, have given selection grade, if not, the reason there of ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ. बहादुर सिंह) : जी हाँ, सरकार ने उनके पत्र क्रमांक 2/8/98-शि.-iii(1), दिनांक 12-12-2000 के अन्तर्गत प्राध्यापकों के कुल पदों पर 20 प्रतिशत प्राध्यापकों को रुपये 7500-12000 का प्रवरण वेतनमान देने की स्वीकृति दी है।

इन कर्मचारियों को प्रवरण वेतनमान देने के सम्बन्ध में उनका सेवारिकॉर्ड पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों/ संस्थाओं को लिखा हुआ है। इनमें से 712 वरिष्ठतम अध्यापकों को यह लाभ दिया जा चुका है शेष का रिकॉर्ड पूर्ण होने पर प्रवरण वेतनमान का लाभ दे दिया जायेगा।

Building of Mewat Model School, Boraka

***982. Shri Bhagwan Sahai Rawat :** Will the Minister for Town and Country Planning be pleased to state whether the Government is aware of the fact that the construction

[श्री भगवान सहाय रावत]
work of the building of Mewat Model School, Boraka in Hathin constituency is lying incomplete ; if so, the time by which the aforesaid building is likely to be completed ?

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : इस इमारत का कार्य चल रहा है तथा जून 30, 2002 तक पूरा होने की सम्भावना है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Upgradation of G.H.S. Urlana

100. Sh. Padam Singh Dahiya : Will the Minister of State for Education be pleased to state--

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government High School, Urlana Kalan, District Panipat which fulfil all the norms and announcement for the purpose has been made in the second phase of "Sarkar Aap Ke Dawar Programme" ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid School is likely to be upgraded ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ. बहादुर सिंह) :

(क) राजकीय उच्च विद्यालय उरलाना कलां जिला पानीपत को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विद्यालय दर्जा बढ़ाने हेतु वांछित मापदण्ड पूरे नहीं करता।

(ख) ऊपर 'क' के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उठता।

Salary of the Employees of Government Aided Colleges

103. Sh. Anil Vij : Will the Minister of State for Education be pleased to state whether it is a fact that large number of employees of the Govt. Aided Colleges in the State are not getting their salaries in time ; if so, the name of such colleges ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ. बहादुर सिंह) : नहीं श्रीमान् जी।

Installation of Traffic Light

104. Shri Anil Vij : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whethter there is any proposal under consideration of the Government to instal traffic light on crossing of National Highways No. 1, Staff Road Crossing near Railway Station, Shastri Colony, Ambala Cantt and Model Town Crossing, Ambala City; and

(b) if so, by what time aforesaid proposal is likely to be materialized ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत, प्रश्न ही नहीं उठता।

Shortage of Drinking Wate in Village Gothra

105. Ch. Jagjit Singh : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that there is a shortage of drinking water in village, Gothra, Tehsil Dadri; if so, the reasons thereof togetherwith the time by which the aforesaid shortage of drinking water is likely to be met out ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : गांव गोठड़ा के लिए नहरी पानी पर आधारित जलघर वर्ष 1997 में स्वीकृत तथा वर्ष 1999 में पूरा हुआ था। गांव गोठड़ा, गोठड़ा माईनर के अन्तिम छोर पर स्थित है। इस नहर के अन्तिम छोर पर नहरी पानी की अनिश्चितता के कारण गांव गोठड़ा में पेयजल की कमी है। नहरी पानी की सुनिश्चितता के साथ ही यह कमी दूर हो जाएगी। परन्तु नहरी पानी की सुनिश्चितता की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

Organi System of Farming

106 Ch. Jagjit Singh : Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether the Organic system of Farming is being adopted in the State; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धु) : कुछ किसानों ने बहुत ही सीमित स्तर पर कृषि की जैविक प्रणाली से खेती आरम्भ की है। कृषि विभाग ने किसानों को इस बारे जानकारी प्रदान करने के लिए हाल ही में एक दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित किया। फिर भी कृषि की जैविक प्रणाली का प्रचलन अभी तक सीमित ही है।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक शोक प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब भी सदन में कोई शोक प्रस्ताव पढ़ा जाता है तो दुःख भी होता है और गौरव भी अनुभव होता है। कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाता जिस दिन सजग प्रहरी के रूप में हमारे हरियाणा प्रदेश का कोई न कोई जवान भारत माता की रक्षा हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर नहीं करता हो। 20 वर्ष से 25 वर्ष की आयु के जवान जाते हैं। पूरे प्रदेश को उनकी मृत्यु से इसलिए भी दुःख होता है कि वे देश के उज्ज्वल भविष्य हैं। लेकिन गर्व और गौरव इस बात का है कि उन्होंने देश के सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किये हैं। अध्यक्ष महोदय, एक 10 मार्च को और एक 16 मार्च को, दो जवान शहीद हुये हैं। 10 मार्च,

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

2002 को गांव हुड़िया कलां जिला रेवाड़ी का शहीद हनुमान और 16 मार्च, 2002 को गांव लोआ माजरा जिला झज्जर के राकेश शहीद हुये उनके लिये यह सदन अपने अश्रुपूर्ण नमन् करता है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की एकता और अखण्डता के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुये अपने मूल्यवान जीवन का बलिदान दिया। यह सदन इन वीर सिपाहियों की शहादत पर उन्हें शत्-शत् नमन् करता है और उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

चौ. भजन लाल (आदमपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो शोक प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है, मैं और मेरी पार्टी इससे पूरी तरह से सहमत हैं और इन शहीदों को जिन्होंने शहादत दी है उनको जितनी भी श्रद्धांजलि दी जाये उतनी मैं समझता हूँ कम है।

श्री कृष्णपाल (मेवला महाराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखा है, उसमें मैं अपने को और अपनी पार्टी को सम्मिलित करता हूँ और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण शोकाकुल परिवारों को सदन की संवेदना पहुंचा दी जायेगी और अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी सदस्यों को खड़ा होने के लिए अनुरोध करूँगा।

(इस समय सदन ने दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

नियम 64 के अधीन वक्तव्य -

Mr. Speaker : Hon'le Members, now the Chief Minister will make a statement towards the matter of public importance under Rule 64 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस पूरे सदन का ध्यान 17 मार्च को लोहारू में हुई साम्प्रदायिक घटना की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में गुजरात के गोधरा कस्बे में रेल यात्रियों को जिन्दा जलाने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुँचाने की कई प्रकार के शरारती तत्वों ने कोशिश की है। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक देश के विभिन्न हिस्सों में साम्प्रदायिक हिंसा का दौर जारी है और यह अत्यन्त खेद एवं चिन्ता का विषय है। इसी स्थिति का नाजायज फायदा उठाकर कुछ शरारती तत्वों ने 16/17 मार्च, 2002 की रात को लोहारू कस्बे में यह अफवाह फैला दी कि लोहारू कस्बे में स्थित एक पुरानी मस्जिद में गोहत्या की गई है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मौके का निरीक्षण किया और पूरी खोजबीन करके इस अफवाह को निर्मूल साबित करते हुए लोगों को समझा-बुझाकर उनके घर भेज दिया। जिस गाय की हत्या का जिकर करके अफवाह फैलाई गई थी वह गाय भी लोगों ने अपनी आंखों से देखी और लोग सन्तुष्ट होकर अपने घरों को चले गये। 17 मार्च, 2002 को सुबह लगभग 9 बजे जब नजदीक के गांवों से लोग लोहारू कस्बे आना शुरू हुए तो इन शरारती तत्वों ने फिर उन लोगों के बीच गोहत्या की अफवाह फैलानी शुरू कर दी और बाजार को बंद करवा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस फिर मौके पर पहुँची और इन लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की। देखते ही देखते इन शरारती तत्वों के साथ आस-पास के गांवों और कस्बे के लगभग 2000/2500 लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म स्थलों, दुकानों और घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पुलिस ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पर पत्थराव किया और इस पत्थराव में कई पुलिस कर्मचारी घायल हुए। पुलिस ने चेतावनी देते हुए इन लोगों पर पहले हल्का लाठी चार्ज किया और फिर हवा में गोलियां चलाकर इन्हें खदेड़ दिया। लेकिन इस दौरान भीड़ में

शामिल शरारती तत्वों ने एक मस्जिद के गुम्बद को कुछ नुकसान पहुँचाया और एक अन्य मस्जिद में आगजनी की। अल्पसंख्यक समुदाय की 10 दुकानों एवं 7 घरों को नुकसान पहुँचाया व आगजनी की। घटना की सूचना मिलते ही उपायुक्त, भिवानी तथा पुलिस अधीक्षक, भिवानी अतिरिक्त पुलिस बल और फायर ब्रिगेड के साथ लोहारू पहुँचे और उन्होंने स्थिति का निरीक्षण किया। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया और किसी को भी किसी प्रकार का कोई जिस्मानी या जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इस सम्बन्ध में 30 लोगों के विरुद्ध नामजद व अन्य लोगों के विरुद्ध आगजनी, लूटपाट, साम्प्रदायिक बलवा, सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारियों पर हमला जैसे आरोपों से सम्बन्धित 4 मुकदमे थाना लोहारू में दर्ज किए गए। अभी तक इस सम्बन्ध में पुलिस ने 30 नामित व्यक्तियों में से 14 को गिरफ्तार कर लिया है और कुल मिलाकर 21 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। बाकी लोगों को भी शीघ्र गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ समाचार पत्रों में पुलिस की गोली से घायल कुछ लोगों के नाम छापे गये हैं लेकिन पुलिस को इस सम्बन्ध में अभी तक दो लोगों के पत्थराव में घायल होने की सूचना अधिकारिक तौर पर प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 18 मार्च, 2002 को लोहारू का पूरा बाजार खुला है। जिस मस्जिद को नुकसान पहुँचाया गया था लोगों ने साम्प्रदायिक सद्‌भाव का अनूठा उदाहरण पेश करते हुए प्रबुद्ध सामाजिक लोगों की निगरानी में उसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया है।

सरकार प्रदेश में हर कीमत पर साम्प्रदायिक सद्‌भाव बनाने के लिए बचनबद्ध है तथा शरारती तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्‌भाव बिगाड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। इस घटना के मद्देनजर सभी जिलों के उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को सतर्क कर दिया गया है तथा अफवाह फैलाने वालों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्ती से निपटने के आदेश प्रशासन को दिए गए है। मैं इस नाजुक मसले पर सदन में सभी पार्टियों से सम्बन्धित विधायकों से अनुरोध करूँगा कि वे सभी लोग इस संवेदनशील मसले पर सरकार का सहयोग करें और प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्‌भाव, सद्‌चार और भाईचारा बनाए रखने में मदद करें।

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जीरो आवर पर बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठें, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है।

राज्यपाल से संदेश

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a communication from His Excellency, Babu Parmanand, Governor of Haryana on 16th March, 2002 which reads as under :--

"Dear Shri Kadian Ji"

I have received your demi-official communication date 11th March, 2002, No. HVS-LA-51/2002 / 3756, alongwith which a copy of "Motion of Thanks" passed by the Haryana Vidhan Sabha on my Address on 11th March, 2002 has been sent to me.

Please do convey my profound appreciation and acknowledgement regarding the same to all the esteemed members of the Haryana Vidhan Sabha.

With regards,

Yours sincerely,
Sd/-
(Babu Parmanand)"

On behalf of His Excellency, the Governor of Haryana, I thank all the Hon'ble Members of this House.

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the Motion under Rule-121, regarding nominations of various Committees.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move-

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the -

(i) Committee on Public Accounts ;

(ii) Committee on Estimates ;

(iii) Committee on Public Undertakings ; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes,

for the year 2002-2003 be suspended.

Sir, I also move -

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Saha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2002-2003, keeping in view the proportionate strength of various parties / groups in the House.

Mr. Speaker : Motion moved -

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in so-far-as they relate to the constitution of the -

(i) Committee on Public Accounts ;

(ii) Committee on Estimates ;

(iii) Committee on Public Undertakings ; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes,

for the year 2002-2003 be suspended

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid committees for the year 2002-2003, keeping in view the proportionate strength of various parties / groups in the House.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह जी जो यह प्रस्ताव रूल-231 और दूसरे रूल्ज के तहत कमेटीज के गठन करने के बारे में लाये हैं इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन के मुताबिक और हरियाणा विधान सभा के रूल्ज के मुताबिक सही बात तो यह है कि इन चारों कमेटीज के सदस्यों का चयन चुनाव प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रदेश के लोगों के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं या सरकार के अधिकारियों की जो कमियां होती हैं उनके बारे इन कमेटीज में चर्चा होती है और उसके बाद कमेटीज की रिपोर्ट यहां पेश की जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह जी प्रस्ताव लाना चाहते हैं कि इन कमेटीज के मैंबर चुनने का अधिकार आपको दे दिया जाए। इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करता हूं और इस बारे में सभी विपक्ष के सदस्यों ने बड़ी लम्बी चर्चा की है और आपको यह लिखकर भी दिया हुआ है कि इन कमेटीज के मैंबरों का गठन सदन में चुनाव प्रक्रिया द्वारा किया जाये। 1989 में चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी उस समय इस प्रथा को बदला गया था।

श्री अध्यक्ष : यह बात 1989 की नहीं 1986 की होगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मेरी जानकारी के मुताबिक तो यह बात 1989 की है लेकिन आपके द्वारा सभी कमेटीज के मैंबरों का चयन किया जाये यह अच्छी प्रथा नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन कमेटीज के मैंबर उन विधायकों को चुना जाये जो वरिष्ठ हैं और कई दफा विधायक बन चुके हैं और वे सरकार की कारगुजारियों और अधिकारियों से अच्छी तरह परिचित होते हैं। वरिष्ठ सदस्य इन कमेटीज के मैंबर तभी बन सकते हैं जब चुनाव प्रक्रिया के तहत इन कमेटी के मैंबरों का चयन किया जाए। मैं आपको Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly के रूल 231(3) पढ़कर सुनाता हूं जिसमें लिखा है-

"The Committee on Public Accounts shall consist of not more than nine members who shall be elected by the Assembly....."

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप अपनी बात कह चुके हैं, प्लीज आप बैठ जायें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। कमेटीज के सदस्यों का चयन चुनाव द्वारा होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, हम इन कमेटीज को कांस्टीच्यूट के बारे में जो रूल है उसे सस्पैंड कर रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन कमेटीज के सदस्यों का चयन लोगों की भावनाओं को देखते हुए सदन में चुनाव प्रक्रिया से किया जाए और यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, प्लीज आप बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी पूरी बात कहने दें। मैं कोई अनपार्लियामैंट्री बात नहीं कर रहा।

श्री अध्यक्ष : दलाल सहब, प्लीज आप बैठें। (विघ्न) चौधरी भजन लाल जी, आप बोलिये। आप क्या कहना चाहते हैं ?

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे 2-3 बातें कहनी हैं।

श्री अध्यक्ष : आप पहले इसी सबजैक्ट पर ही बोलें।

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आपको कमेटी के सदस्य नोमिनेट करने के बारे में आया है इसमें हम सब को इतना ही संशय है कि आपसे हमको इन्साफ की उम्मीद *******

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी जो कह रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाये।

चौ. भजन लाल : आप क्या इन्साफ की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : हाँ, मैं बिल्कुल इन्साफ की बात करता हूँ।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : चौधरी भजन लाल जी, आप स्पीकर साहब की अथोरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते।

चौ. भजन लाल : इसमें चैलेंज करने की क्या बात है। मैं कौन सा कोर्ट में जाऊंगा। (विघ्न) बात जो मैंने कहनी थी वह कह दी। आप मानें या न मानें आपकी मर्जी है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में लोहारू में हुई हिंसा के बारे में सरकार की तरफ से जो कहा गया है उसके बारे में सरकार की तरफ से ठीक कहा गया है और हम इस मामले में पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। (विघ्न) मुझे अभी और भी कहना है। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। (विघ्न)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, रूल 64 के तहत जब मिनिस्टर कोई स्टेटमैंट देता है तो उसके बाद उस पर कोई सप्लीमेंटरी नहीं हो सकती और न कोई डिस्कशन हो सकती। गवर्नमैंट ने जवाब दे दिया है। अगर आप रूल पढ़ना चाहते हैं तो मैं हिन्दी की किताब आपको भिजवा देता हूँ।

चौ. भजन लाल : स्पीकर साहब, आपने जो कहा है उसको हमने मान लिया है।

श्री अध्यक्ष : अगर आपने मेरी बात मान ली है तो फिर इस पर और डिस्कशन की जरूरत नहीं है।

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सीरियस मैटर है। (विघ्न)

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह) : चौधरी साहब, जो कर्ण सिंह दलाल जी ने कहा है उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

चौ. भजन लाल : जो बात मैं कहना चाहता हूँ, उसको आप पहले सुनो। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, अभी जो मैटर चल रहा है वह दूसरा चल रहा है। इस पर आपने जो कहना है वह कहें। (विघ्न)

प्रो. सम्पत सिंह : चौधरी साहब, इस बारे में आपकी क्या राय है ?

चौ. भजन लाल : अगर कमेटी के मैम्बरों का गठन इलैक्शन द्वारा हो जाए तो क्या बुरी बात है ? (विघ्न)

प्रो. सम्पत सिंह : चौधरी साहब, आप यही चाहते हैं कि कमेटियों का गठन इलैक्शन द्वारा हो जाए।

चौ. भजन लाल : हम तो चाहते हैं कि इन कमेटियों के इलैक्शन हो जाएं।

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह) : स्पीकर साहब, अब मैं इस बारे में बताता हूँ। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जब खुद चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला पार्लियामेन्टरी अफेयर्ज मिनिस्टर थे और तब मुख्य मंत्री शायद चौधरी बंसी लाल जी थे। उन दिनों 10-3-1987 को यह प्रस्ताव पार्लियामेन्टरी अफेयर्ज मिनिस्टर की तरफ से आया था कि यह रूल सस्पेंड करके इन चारों कमेटीज को बनाने के लिए स्पीकर साहब को एथोराइज्ड किया जाये और तब से लेकर आज तक यानी पिछले 15 सालों से यही चला आ रहा है। इस बारे में आज दलाल साहब ने भी अपनी बात रखी है और विपक्ष के नेता भी यही कह रहे हैं कि इन कमेटीज के चुनाव हों। ये जो कह रहे हैं, अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं फिर यही कहूंगा कि अच्छा तो यही रहेगा कि आपको यह अधिकार दे दिया जाये ताकि आप पार्टी मैम्बर्ज की संख्या के आधार पर इन कमेटियों में मैम्बर्ज को नोमिनेट कर सकें क्योंकि जिन पार्टियों के सदस्यों की संख्या कम है वे चुनाव के दौरान इन कमेटियों में नहीं आ पायेंगे। अगर आप इन कमेटियों को नोमिनेट करते हैं तो फिर सभी पार्टीज के मैम्बरों को उनमें नोमिनेशन मिल जाता है। यह परम्परा इसीलिए चलाई गई थी ताकि सभी पार्टीज को इन महत्वपूर्ण कमेटीज में नोमिनेशन मिल सके वरना संख्या के आधार पर तो वे इन कमेटीज में नहीं आ सकते क्योंकि किसी पार्टी के 5 मैम्बर्ज हैं। यदि इन कमेटीज के चुनाव करवायेंगे तो एक भी मैम्बर इन 4 कमेटीज में नहीं आ सकता। अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव तो अपोजीशन के हित के लिए ही रखा था ताकि अपोजीशन जो माईनोरिटी में भी हो तो भी इनके मैम्बर्ज इन कमेटीज में आप के द्वारा नोमिनेशन के माध्यम से आ सकें। लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि चुनाव हो तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। इसके बावजूद भी हम तो इसी बात के पक्षधर हैं कि यह अधिकार आपको मिले। इस बारे में सरकारी पक्ष की ज्यादा

जिम्मेवारी बनती है। मैं यही चाहता हूँ कि सभी मैम्बर्ज विशेषकर विपक्ष के मैम्बर्ज किसी न किसी कमेटी में जरूर आ जाएं। स्पीकर साहब, यह आपकी दरियादिली रही है कि कई बार आपने एज़ ए स्पेशल इन्वाईटी के रूप में भी कमेटीज में एम.एल.एज. को नोमिनेट किया है ताकि सभी कमेटीज में सभी पार्टीज के मैम्बर्ज आ सकें और वे मीटिंग में आयें और वे उस मीटिंग में कन्ट्रीब्यूट कर सकें। उनका कन्ट्रीब्यूशन लेने के लिए उनकी मदद लेने के लिए उनका सहयोग लेने के लिए ही आपको यह अधिकार देने की बात है। यदि इनके अनुसार हम इन कमेटीज के चुनाव करवायेंगे तो पार्टी संख्या के आधार पर कई मैम्बर्ज चुनाव के माध्यम से कमेटीज में आने से रह जायेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह प्रस्ताव अपोजीशन के हित में ही है। यदि हम यह प्रस्ताव पास नहीं करेंगे तो फिर यह अपोजीशन के हित में नहीं होगा। इन कमेटीज के चुनाव करवाने में सरकारी पक्ष की तरफ से कोई एतराज नहीं है। अगर ये चुनाव करवाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं लेकिन चुनाव करवाना इनके हित में नहीं होगा। हम यह नहीं चाहेंगे कि इनका हित न हो। अध्यक्ष महोदय, चाहे सत्ता पक्ष हो या अपोजीशन पक्ष हो सब के मैम्बर्ज को आप इन कमेटीज में नोमिनेशन कर पाएंगे यही इस प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य था और यही इस बारे में मेरा निवेदन था।

श्री अध्यक्ष : अब तक की जो पास्ट प्रैक्टिस रही है उसके मुताबिक विपक्ष के नेता अपने मैम्बर्ज के नोमिनीज की लिस्ट देते हैं कि हमारे फलां-फलां मैम्बर्ज को फलां-फलां कमेटीज में कन्सीडर किया जाये और इसी हिसाब से अब तक विपक्ष द्वारा दी गई लिस्ट कन्सीडर होती रही है। चौधरी भजन लाल जी द्वारा दिए हुए नाम भी कन्सीडर होते रहे हैं। चाहे इनके लड़के हों या चाहे कोई इनका एम.एल.ए. हो हमने उनको कमेटीज में नोमिनेट किया है और फिर चाहे वे उस मीटिंग में आयें या न आयें लेकिन हमने इनकी लिस्ट को कन्सीडर अवश्य किया है।

चौ. भजन लाल : हमने जो कहा है वह आपने नोमिनेट नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : हमने वही किया है।

चौ. भजन लाल : आपने वह नहीं किये।

श्री अध्यक्ष : चलो खैर यह बहस का मुद्दा नहीं है। आप लोगों की मर्जी है। जैसा हाउस चाहेगा वैसा होगा। हमने अपनी बुद्धिमता से काबिल आदमियों को अच्छी कमेटीज में स्थान दिया है। (विघ्न)

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये आप बताएं। कोई मैम्बर कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा इससे कोई फायदा नहीं होगा। (विघ्न)

चौ. भजन लाल : स्पीकर साहब, मैं ऐसी बात नहीं कहता कि कोई कन्ट्रोवर्सी हो, जिससे किसी को तकलीफ हो। मैं नाम दे दूंगा उसके मुताबिक चाहे किसी भी पार्टी का मैम्बर हो, उसको नोमिनेट आप कर दें ताकि किसी को तकलीफ न हो। (विघ्न)

प्रो. सम्पत्त सिंह : स्पीकर साहब, एकोमोडेट तो कर सकते हैं लेकिन हू-ब-हू तो कर नहीं सकते। वर बैटम नहीं कर सकते स्पीकर साहब, मैक्सिमम एकोमोडेट कर सकते हैं, वह करते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जो जिस कमेटी के काबिल है, उसको उसी कमेटी में रखा जाएगा। (विघ्न एवं शोर)

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हम लोग आपको नाम लिख कर देंगे। (विघ्न एवं शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : चौधरी साहब, आपकी लिखी हुई बात को ज्यों का त्यों मानना स्पीकर साहब के लिए जरूरी नहीं है वे आपकी बात को मानने के लिए पाबन्द नहीं हैं। यह उनकी पावर में है कि किसे रखें किसे न रखें। आप नाम लिख कर दे दें वे इनमें से नाम चयन करेंगे। दो ही तरीके हैं या तो आप नोमिनेशन पर आएं या इलैक्शन पर आएं तीसरा कोई आल्टरनेटिव तरीका है ही नहीं।

चौ. भजन लाल : यही तो हमने कहा है। (विघ्न एवं शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : फिर भी हम चाहते हैं कि हर जगह 2-2 या 3-3 नाम मांगे जाएं उनमें से जितने आ जाते हैं जितनी भी संख्या होगी आप नाम भेज दीजिए, यह स्पीकर की मर्जी की बात है कि वे किसको नामजद करते हैं।

चौ. भजन लाल : हम आपको नाम देंगे। संख्या के मुताबिक और सीनियोरिटी के हिसाब से आप उन्हें कर सकते हैं। (विघ्न एवं शोर) दूसरे अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहने जा रहा था। (विघ्न)

Mr. Speaker : Question is —

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in so-far-as they relate to the constituion of the --

(i) Committee on Public Accounts ;

(ii) Committee on Estimates ;

(iii) Committee on Public Undertakings ; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes,

for the year 2002-2003 be suspended.

That this House authorises the Speaker, Haryana Vidhan Sabha, to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2002-2003, keeping in view the proportionate strength of various parties / groups in the House.

The motion was carried.

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठिये। (विघ्न एवं शोर) इनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाए। (विघ्न) इस बारे में चौधरी भजन लाल जी को आपसे ज्यादा पता है और वे सैटिसफाईड हैं इसलिए आप बैठें। (विघ्न एवं शोर)

अति विशिष्ट व्यक्तियों का स्वागत

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण। हरियाणा विधान सभा से राज्यसभा के लिए नये निर्वाचित सदस्य श्रीमती सुषित्रा महाजन और श्री हरेन्द्र सिंह मलिक वी.आई.पीज गैलरी में उपस्थित हैं, मैं हाउस की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। (इस समय मेजें थपथपाई गई)

चौ. भजन लाल : स्पीकर साहब, मैं इतनी देर से अपनी सीट पर खड़ा हुआ हूं। आप मेहरबानी करके मेरी बात सुनिये। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप अभी बैठें (विघ्न एवं शोर) यह रिपोर्ट आप प्रस्तुत हो लेने दें उसके बाद आप बोल लेना। (विघ्न एवं शोर)

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

समितियों की रिपोर्टस प्रस्तुत करना

(1) लोक लेखा समिति की 52वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Bhagi Ram, Chairperson, Committee on Public Accounts will present the Fifty Second Report of the Committee on Public Accounts for the year 2001-2002, on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st, March 1997 (Civil and Revenue Receipts). (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भागी राम जी, पहले आप रिपोर्ट पेश करें उसके बाद आप बोलें। (शोर एवं व्यवधान) भजन लाल जी, आप अपने मैम्बर्ज को बिठाएं। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे विपक्ष के नेता की विपक्ष के सदस्यों के सामने या तो कोई मजबूरी है, या इनकी कोई पोजीशन नहीं है। इनकी पार्टी के विधायक इनके कंट्रोल से बाहर हैं या ये उनको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है या वे उनसे अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) सबसे बड़ी दिक्कत और कठिनाई यह है कि जब यहां पर दो नेता हों और दोनों एक दूसरे को नेता मानने के लिए तैयार नहीं हों। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अनुशासनहीनता की वजह से सदन का समय खराब हो जाता है। (शोर एवं व्यवधान) आपको विपक्ष के नेता होने के कारण जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपकी कोई बात नहीं मानता है तो आप उनके खिलाफ सख्ती करके उनको बर्खास्त कर सकते हैं। आपको इस बात का ज्ञान नहीं है इसलिए मैं आपको यह बात बता रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी आप उनको रिपोर्ट पढ़ने दें।

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह जीरो ऑवर है और आप हमें बोलने दें।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऑफिशियल बिजनैस शुरू हो गया है। अब जीरो ऑवर कहां से रह गया है ?

चौ. भजन लाल : स्पीकर सर, आप हमें यह बताएं कि यह जीरो ऑवर है कि नहीं है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जीरो ऑवर खत्म हो चुका है। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, जो लिस्टिड बिजनैस है वह टेक-अप हो रहा है, उसके बाद जीरो ऑवर कहां से रह जाता है ? अध्यक्ष महोदय, अनफारचुनेटली ये रूल्स पढ़कर आते नहीं हैं, मोशन मूव हो चुकी है तो जीरो ऑवर कहां से रह गया है ? मुख्यमंत्री जी ने जब स्टेटमैंट दी थी उस समय जीरो ऑवर था। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल : ********

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। भागी राम जी, आप रिपोर्ट पेश क्यों नहीं करते ? (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल : *********

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, गर्म न हों आप तो बड़े ठण्डे आदमी हैं, गर्म कैसे हो रहे हो।

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही जरूरी मामला है। *****

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। भागी राम जी, आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीटों पर बैठ जाएं। ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए।

श्री भागी राम (चेयरपर्सन, लोक लेखा समिति) : महोदय, मैं 31 मार्च 1997 को समाप्त हुए वर्ष (सिविल तथा राजस्व प्राप्तियां) के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर वर्ष 2001-2002 के लिए लोक लेखा समिति की 52वीं रिपोर्ट सादर सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप क्या कहना चाहते हैं।

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह कहना है कि देश के अखबारों में भी और आडिटर जनरल ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बारे में बताया है।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आपका इस बारे में एडजर्नमैंट मोशन दोपहर 1.51 बजे पर आया है। यह मोशन अंडर कंसीड्रेशन है। अभी आप बैठें। इस तरह का मोशन एक घंटा पहले आना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनने की कृपा करें क्योंकि यह कोई छोटी बात नहीं है यह बहुत बड़ी बात है इसलिए आप हमारी बात तो सुनें।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप हरियाणा असैम्बली की रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडैक्ट ऑफ बिजनैस की किताब में से रूल 67 पढ़कर देखें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकारी बिजनैस आने के बाद जीरो ऑवर अपने आप ही समाप्त हो जाता है और चौधरी भजन लाल जी इस बात को समझते भी हैं इसलिए वे मान जाते हैं और बैठ जाते हैं। लेकिन उनके जो दूसरे साथी हैं वे उनसे बार-बार कहते हैं कि ऐसा करें ऐसा करें। अध्यक्ष महोदय, जब ये आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे उस वक्त भी इन्होंने ऐसा ही प्रयास किया था। भजन लाल जी की भी मजबूरी है। इन्होंने उस समय भी पूरी कोशिश की थी।

चौ. भजन लाल : नहीं-नहीं, अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं थी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनको किसी ने समझा दिया और इनकी समझ में आ गया। इनकी मजबूरी है। इनको पता होना चाहिए कि अगर सरकारी बिजनैस एक बार आ जाए तो जीरो ऑवर खत्म हो जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बैठिए। आपका यह मोशन अंडर कंसीड्रेशन है।

चौ. भजन लाल : स्पीकर साहब, पहले आपने कहा था कि जब यह हमारा मोशन आ जाएगा तो उस वक्त आपको पांच मिनट बोलने के लिए दिए जाएंगे और अब आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) यह 600 करोड़ रुपये के घपले की बात है।

(ii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 49वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Balwant Singh Maina, Chairperson, Committee on Public Undertakings will present the Forty Ninth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 2001-2002, on the Report of the Comptroller & Auditor General of India for the years 1996-97 & 1998-99 (Commercial).

श्री बलवन्त सिंह मायना (चेयरपर्सन, लोक उपक्रमों संबंधित समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं 1996-97 और 1998-99 (वाणिज्यिक) के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर वर्ष

2001-2002 के लिए लोक उपक्रमों संबंधित समिति की 49वीं रिपोर्ट सादर प्रस्तुत करता हूं।

(iii) अनुसूचित जातियों, जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की समिति की 26वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now, Shri Nafe Singh Jundla, Chairperson, Committee on the Welfatre of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes will present the Twenty Sixth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2001-2002.

Shri Nafe Singh Jundla (Chairperson, Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes) : Sir, I beg to present the Twenty Sixth Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes for the year 2001-2002. (Interruptions)

(iv) सरकारी आश्वासनों समिति की 32वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now Shri Mange Ram Gupta, Chairperson of the Committee on Government Assurances will present the Thirty Second Report of the Committee on Government Assurances for the year 2001-2002.

Shri Mange Ram Gupta (Chairperson Committee on Government Assurances) : Sir, I beg to present the Thirty Second Report of the Committee on Government Assurances for the year 2001-2002.

वाक-आउट्स

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सी.ए.जी. की रिपोर्ट के बारे में मुझे कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठें। अब इनकी कोई बात रिकॉर्ड न करें। (शोर एवं व्यवधान) Please sit down.

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात तो सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात तो सुनें। ******

चौ. भजन लाल : स्पीकर साहब, आपको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। (शोर एवं व्यवधान) ***

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिए। Please sit down. आप मेरी बात सुनिये। रूल्ज में अडजर्नमैंट मोशन का नोटिस देने के लिए हाउस शुरू होने से एक घण्टा पहले देना होता है। पहले डेढ़ घण्टे पहले देना होता था। इसमें अब डेढ़ घंटे को एक घंटा किया हुआ है। आधा घंटा बाद में डिलीट किया था। ये तो वैसे ही हैं समझते ही नहीं हैं। ये तो नियम बने हुए हैं अब हम इनमें बदलाव नहीं ला सकते हैं। 1 बजकर 51 मिनट पर मुझे कैप्टन अजय सिंह स्वयं देकर गए हैं और देना एक घंटे पहले होता है। आप लोग पढ़कर कुछ आते नहीं हैं और कसूर मेरा बताते हैं, मैं क्या करूं, बताएं। मैं रूल्ज से बंधा हुआ हूं मैं इससे बाहर नहीं जा सकता। आप लोग बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल : ********

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी की कोई बात रिकॉर्ड न की जाए। आपको हाउस के प्रौसीजर का पता नहीं है। हुड्डा साहब रूल्ज़ कमेटी के मैंबर भी हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं रूल्ज़ को रैफर नहीं कर रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) *****

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब जो कह रहे हैं, वह रिकॉर्ड न किया जाए। अब बजट पर बहस शुरू है। आप बजट पर ही बोलें। (शोर एवं व्यवधान) पहले मेरी बात सुनिए। आपको यह पता नहीं है कि किस समय लिखकर देना होता है।

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सीरियस मैटर है यह 600 करोड़ रुपये का मामला है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप कृपा करके हमारी बात सुनिएं। हमें अपनी बात कहने का मौका दीजिए। यह ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है यह क्या कहती है यह सुनें। ******

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी की कोई बात रिकॉर्ड न की जाए। भजन लाल जी, यह सी.ए.जी. की रिपोर्ट जो आपके पास है वह कमेटी के सामने आती है और कमेटी इस पर ऐप्रोप्रिएट ऐक्शन लेती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये आपकी परमीशन लिए बगैर ही बोले जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, *****

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : इनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाए। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठ जाइये पहले सलाह मशविरा कर लीजिये। बैठ जाइये।

चौ. भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमें बोलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं इसलिए हम इस सदन से वाक-ऑउट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब रामबीर सिंह बोलें।

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : आप वाक-आउट कर रहे हैं या बजट पर बोल रहे हैं ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं इसलिए हम वाक-आउट कर रहे हैं।

(इस समय इन्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन से वाक-आउट कर गये)

चौ. बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन यह है कि जैसे ही क्वेश्चन ऑवर खत्म हुआ Leader of the Opposition was on his legs. मगर उस वक्त आपने उनकी बात सुनी नहीं, नीचे को गर्दन करके दूसरा काम चालू कर दिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जीरो ऑवर पर अगर कोई मैम्बर क्वैश्चन रेज करे, तो वह कैसे करें ? कहां करें, विधान सभा में करें या बाहर जाकर करें ? मैं तो यह बात समझता हूं कि लीडर ऑफ दि अपोजीशन जो कुछ कहना चाहते हैं, उसके लिए आपको उनको टाइम देना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : बंसीलाल जी, आप बैठिये।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

चौ. बंसीलाल : आप उनको ओवर रूल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बंसीलाल जी, आप बैठिये।

चौ. बंसीलाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं हम भी आपके इस एटीच्यूड के खिलाफ वाक ऑउट कर रहे हैं।

श्री रामकिशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष : जो रामकिशन फौजी बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाये।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के दोनों सदस्य सदन से वाक-आउट कर गये)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप पहले अपनी बात का जवाब तो सुनते जाइये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : जो कर्ण सिंह दलाल बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाये।

चौ. जगजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : जो जगजीत सिंह जी बोल रहे हैं वह भी रिकॉर्ड न किया जाये।

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष फिर इस बार भी गैर-जिम्मेदाराना भूमिका निभा रहा है जबकि निभानी चाहिये जिम्मेदारी की लेकिन वह नहीं निभा रहा है। स्पीकर सर, चौधरी बंसीलाल जी सीनियर मैम्बर हैं, मुख्य मंत्री भी रहे हैं। केन्द्र में मंत्री भी रहे हैं और कह रहे हैं कि लीडर ऑफ दि ओपोजीशन जिस वक्त भी बोलना चाहते हैं आप उनको टाइम दें। बोलने का टाइम होता है लेकिन स्पीकर से परमिशन की जरूरत होती है। मुख्य मंत्री जी ने सरकार की तरफ से सुओ मोटो स्टेटमैंट पढ़ी। वह स्टेटमैंट पढ़ने के तुरन्त बाद अगर माननीय विपक्ष के नेता कोई सवाल उठाना चाहते, एडजर्न मोशन का या कालिंग अटेंशन मोशन का, वह इनका अपना राईट था, उठाते। तब तो उठाया नहीं और अब बोल रहे है। फिर मैंने मोशन पढ़ दिया और वह पास हो गया और फिर लिस्टिड बिजनैस शुरू हो गया। उसके बाद जीरो ऑवर वाली बात हो गई। जीरो ऑवर की परम्परा रही है अदरवाइज जीरो ऑवर एज सच कहीं नहीं है और हम इस परम्परा को निभा भी रहे हैं। गवर्नरज एड्रैस और बजट दोनों पर हर मैम्बर को बोलने के लिए पूरा टाइम मिलता है। किसी के पास बात को कहने के लिए कोई ज्वलन्त इशू हो या फिर और कोई बात हो वह यहां कह सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक रिपोर्ट को लेकर बात उठ रही है तो आपने भी रूल्ज की बात कही। रूल्ज की बात आए तो ये लोग कहते है आप रूल्ज पढ़ लो, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं हैं। मैं कहना चाहूँगा कि यह असैम्बली है यहां कायदे कानून हैं, यह कोई धर्मशाला नहीं है या किसी जलूस की स्टेज नहीं है। यह विधानसभा का सैशन है इसे दुनिया देखती है और इस पर लाखों रूपये खर्च होते हैं और असैम्बली रूल्ज एंड रैगुलेशन से ही चलती है। At page No. 138 in the Book of Practice and Procedure of Parliament by Kaul and Shakdher, it is written--

> " The Audit Reports of the Comptroller & Auditor General stand automatically referred to the Committe on Public Accounts. These form the basis of investigation by the Committee which submits its reports thereon to Parliament. In case the House wants to have any information from Comptroller and Auditor General, it can do so through the Public Accounts Committee. But in case a Committee has not been constituted, it is for the Speaker to decide as to what should be done in the matter, provided members give a notice for raising a discussion in one form or the other."

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[प्रो. सम्पत सिंह]

तो अध्यक्ष महोदय, ये आपके राइट में है। वैसे तो ये रिपोर्ट जो पब्लिक एकाउंटस कमेटी बनी हुई है उस कमेटी को जाती है और कमेटी को यह रिपोर्ट जाने के बाद कमेटी उस पर मीटिंग्ज़ करती है। पी.ए.सी. की रिपोर्ट हाउस में पेश की जाती है। इसलिए इस बात को उठाने के लिए इनका यह कोई उचित माध्यम नहीं है। दूसरा जैसा आप ने कहा कि ऐसी बात को उठाने के लिए वन ऑवर का नोटिस चाहिए तो इस बात को भी ये नहीं मान रहे। ये हर कायदे कानून को ताक पर रखने की कोशिश करते हैं। ये चीप पब्लिसिटी प्राप्त करते हैं। ये डिस्कशन में कोई सोलेड कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी पार्लियामैंटरी बात कहना चाहता हूँ। चौधरी बंसीलाल जी ने एक छोटी सी बात आपसे कही थी कि क्वैश्चन ऑवर खत्म हुआ तो चौधरी भजनलाल जी जीरो ऑवर के लिए खड़े हो गए और सम्पत सिंह जी अपना मोशन पढ़ने के लिए खड़े हो गए। (शोर एवं व्यवधान) वे तो केवल यह जानना चाहते थे कि कोई जीरो ऑवर है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, अब आप बैठें।

वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Hon'ble members, now general discussion on the Budget for the year 2002-2003 will be resumed. Now Shri Rambir Singh may speak.

श्री रामबीर सिंह (पटौदी, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे वर्ष 2002-2003 के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं हरियाणा के वित्त मंत्री प्रो. सम्पत सिंह का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया, संतुलित और कर रहित बजट हरियाणा की जनता के लिए दिया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के कारण ही इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी को यमुनानगर में बहुत भारी जीत मिली है और यह जीत माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की जनकल्याणकारी नीतियों की जीत है। इस जीत पर यमुनानगर की जनता ने इनैलो के प्रत्याशी को जिता कर अपनी मोहर लगाई है। अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने साम्प्रदायिक सद्भावना के लिए एक वक्तव्य पढ़ा। पूरे हरियाणा प्रदेश में इस समय साम्प्रदायिक सद्भावना है। कुछ जगहों पर असाम्प्रदायिक तत्त्व किन्हीं आतंकवादी संगठनों या दूसरी ताकतों के इशारे पर साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं उनको सख्ती से निपटने के लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय और हरियाणा सरकार को आग्रह करूँगा। अध्यक्ष महोदय, इससे अच्छी साम्प्रदायिक सद्भावना की अनूठी मिसाल कहां मिलेगी कि मेरे हल्के पाटोदी में लगभग पांच हज़ार की आबादी मुसलमानों की है और पिछले दिनों दशहरा के समय पर रामलीलाओं का आयोजन हुआ था। उस समय हमारे वहां कम से कम पांच मुसलमान लड़कों ने रामलीला में हनुमान और लक्ष्मण का रोल किया था। अध्यक्ष महोदय, इससे अच्छी साम्प्रदायिक सद्भावना की मिसाल पूरे हरियाणा में और कहीं नहीं मिल सकती। यह ठीक है कि पिछले कुछ दिनों से पूरे संसार को आतंकवाद के झटकों से गुजरना पड़ा है और इससे पूरे संसार की अर्थव्यवस्था पर भी चोट लगी है। 13 दिसम्बर, 2001 को हमारी पार्लियामैंट पर आतंकवादी हमला हुआ, 11 सितम्बर, 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सैंटर पर आतंकवादी हमला हुआ और अभी पिछले सप्ताह उड़ीसा की विधान सभा पर भी आतंकवादी हमला हुआ। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरा संसार इस बारे में सोचता है कि इन आतंकवादी गतिविधियों को जड़ से उखाड़ने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास किये जायें और किए भी जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है और कुछ दिनों में आतंकवाद समाप्त हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, अब

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से सर्वोच्च न्यायालय ने एस.वाई.एल. का फैसला 15 जनवरी, 2002 को हमारे हक में किया। एस.वाई.एल. का मामला पिछले कई सालों से लटका हुआ था लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसका फैसला हरियाणा के हक में कर दिया है और पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं कि जो नहर पंजाब में बननी है, एक साल के अन्दर पंजाब सरकार बनवाये। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन का आभार प्रकट करता हूँ कि सभी सदस्यों ने अपनी पार्टी की नीतियों से ऊपर उठ कर आपसी मतभेद को भुलाकर माननीय मुख्य मंत्री महोदय एस.वाई.एल. के बारे जो प्रस्ताव लाये थे उसको सर्वसम्मति से समर्थन दिया। अध्यक्ष महोदय, यह नहर विशेष रूप से दक्षिणी हरियाणा के लोगों के लिए जीवन रेखा है। दक्षिणी हरियाणा में ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा चुका है और वहां सिंचाई में बहुत दिक्कत होती है। वहां कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जहां पीने का पानी भी दूर-दूर से लाना पड़ता है। लेकिन जब यह नहर बन जायेगी तो दक्षिणी हरियाणा निश्चित तौर पर विकास प्राप्त करेगा और वहां के किसानों को सिंचाई करने में कोई दिक्कत नहीं आयेगी जिससे उनकी फसल अच्छी होगी। जहां पीने का पानी दूर से लाना पड़ता है वहां भी पीने का पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिलने लगेगा। स्पीकर सर, वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2002-2003 के लिए जो कर मुक्त बजट पेश किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। बजट में उन्होंने कुल योजना की परिव्यय का 42.13 प्रतिशत पैसा बिजली, सिंचाई, सड़क और परिवहन पर खर्च के लिए प्रावधान किया है। **(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी जब जन हित की बात होती है तो वाक-आउट कर जाते हैं। उनमें से कुछ कह रहे थे कि कृषि के लिए बजट में कम पैसा रखा गया है लेकिन उनको यह नहीं मालूम कि बिजली और सिंचाई पर जो पैसा खर्च किया जायेगा उसका असर भी किसान की खेती पर ही पड़ता है। बिजली अच्छी मिलेगी और सिंचाई व्यवस्था अच्छी होगी तो किसान की फसल भी अच्छी होगी। लेकिन मेरे विपक्ष के भाई इन बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि बिजली और सिंचाई भी किसानों के ही काम आती है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका 42.13 प्रतिशत हिस्सा बिजली, सिंचाई, सड़कें, परिवहन आदि के लिए रखा गया है। इसमें से सिंचाई क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रुपये, सड़कों के लिए 335.20 करोड़ रुपये, बिजली के लिए 166.67 करोड़ रुपये और सामाजिक सेवाओं के लिए 710 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने पिछले दो अढ़ाई साल से, विशेषकर बिजली के क्षेत्र में विशेष प्रयास किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आभार प्रकट करूँगा। इन्होंने बिजली की सप्लाई को ठीक करने के लिए और किसानों को बिजली देने के लिए जो कार्य किए हैं उसके लिए ये वाकई बधाई के पात्र हैं। इनके अथक प्रयासों के कारण ही वर्ष 2001-2002 में हमारे यहां पर बिजली का उत्पादन 481 लाख यूनिट प्रतिदिन हो गया है। इसके अलावा जो हमारे पुराने पावर हाउस बंद पड़े थे और जिनकी रिपेयर नहीं की गई थी यानी जिनका वर्षों से काम लम्बित पड़ा था, उन सब को ठीक करवाया गया है ताकि बिजली की सप्लाई ठीक हो सके। इसी से हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के व्यापारियों को और आम नागरिकों को पूरी बिजली उपलब्ध हुई है। इसके लिए मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी और बिजली विभाग के अधिकारियों का आभार प्रकट करता हूँ।

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक किसानों को टयूबवैल्ज के कनैक्शंज देने की बात है उसमें भी बहुत प्रगति हुई है। हरियाणा की मौजूदा सरकार ने 2000-2001 में पिछले 10 सालों से ऐसे पैण्डिग पड़े टयूबवैल्ज के घरेलू तथा गैर घरेलू कनैक्शन दिए। आज हरियाणा प्रान्त की स्थिति यह है कि किसी का भी कनैक्शन यानी किसी की एप्लीकेशन कनैक्शन लेने के लिए पैण्डिग नहीं है। सब को पता है कि पिछली सरकारों के समय में वर्षों तक लोग नए कनैक्शन्ज के लिए भागते रहते थे और चक्कर काटते रहते थे लेकिन अब लोगों को बिजली के कनैक्शंज लेने में कोई दिक्कत नहीं आती।

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई की जहां तक बात है, मैं यह अवश्य कहूंगा कि एस.वाई.एल. का मुद्दा

[श्री रामबीर सिंह]

हमारे लिए बहुत ही अहम् मुद्दा है। रिवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन पर भी बहुत जोरों से निर्माण कार्य चालू है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि रिवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के चालू होने पर दक्षिण हरियाणा की लगभग 20 हजार एकड़ भूमि को पानी मिलेगा जिससे हमारे दक्षिणी हरियाणा के किसानों को विशेषतौर पर फायदा होगा। जैसा कि मैंने बताया है कि अब इस का निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है लेकिन पिछले दिनों कुछ आदमियों की वजह से उसके निर्माण कार्य में बाधा आई थी। जब हमने यह बात मुख्य मंत्री जी के नोटिस में लाई तो उन्होंने तुरंत हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए उस बाधा को दूर करवाया और जिन 20-22 आदमियों की वजह से काम रुका हुआ था मुख्य मंत्री जी ने उनको बुलवाया और उनसे बात की जिसके परिणामस्वरूप आज रिवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन का काम जोरों पर चल रहा है। मुझे उम्मीद है, और जैसा कि सरकार ने भी सदन में आश्वासन दिया है, कि रिवाड़ी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम 31 मार्च 2003 तक पूरी हो जायेगी जिससे वहां के किसानों को खेती के लिए एक नई दिशा मिल सकेगी।

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़कों और पुलों की बात है, इस बारे में सभी को पता है कि हरियाणा की सड़कों पर पिछले दो अढ़ाई सालों में बहुत अधिक काम हुआ है। आज हमारा ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती हो। जबकि इस सरकार के आने से पहले सड़कों की वह हालत थी जो आज से 20-30 साल पहले थी। कच्चे रास्तों पर जहां पर लीक पड़ जाती है, उस पर से जाना पड़ता था। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी ने सत्ता सम्भालते ही पूरे हरियाणा प्रदेश की सड़कों को इतना बढ़िया कर दिया कि आप अपनी गाड़ी के अन्दर चाय पानी पीते हुए भी जा सकते हैं। अब गाड़ियों में चलते समय आपका चाय-पानी छलकेगा नहीं और न ही झटके लगेंगे। मैं लालू प्रसाद यादव जी की वह बात तो नहीं कहना चाहूँगा कि हरियाणा की सड़कें कैसी हैं लेकिन निश्चित् रूप से हम यह कहना चाहेंगे कि पूरे देश में अगर सबसे बढ़िया कहीं सड़कें हैं तो वह हरियाणा प्रदेश के अन्दर हैं और उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा.

श्री उपाध्यक्ष : रामबीर जी, आप प्लीज कन्कलूड करें।

16.00 बजे

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के मामले में मैं मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पूरे प्रदेश के अन्दर नई सड़कों का जाल बिछाया है। जो सड़कें किन्हीं राजनीतिक कारणों से छोड़ दी गई थी उन को बनाकर गांवों से जोड़ दिया गया है। मान्यवर, मैं एक बात यहां पर विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट के 24वें पैरे में लिखा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत सड़कों के विकास के लिए पांच करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। मैं एक बात माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो छोटे कस्बे पड़ते हैं उनका भी ध्यान रखा जाए क्योंकि विकास तो उनको भी चाहिए क्योंकि वे भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही पड़ते हैं जिनके विकास के लिए राशि मिलती है उनका हिस्सा भी उनको दिया जाना चाहिए। मान्यवर, परिवहन के मामले में अगर मैं चर्चा नहीं करूंगा तो यह हरियाणा की जनता के साथ ज्यादती होगी। हरियाणा सरकार ने परिवहन के मामले में जो सुधार किया है वह निःसन्देह अनूठी मिसाल है। 1100 नई बसें हरियाणा सरकार ने पुरानी से बदल कर, हरियाणा की सड़कों पर दौड़ाई हैं। चालू वित्त वर्ष में भी 407 नई बसें इसमें और ऐड की जाएगी। मैं माननीय परिवहन मंत्री जी का इस बारे में धन्यवाद करूंगा। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हरियाणा की बसें इस समय सबसे अच्छी हैं। मैं सरकार का आभार भी प्रकट करता हूँ कि इन्होंने डीलक्स बसों की सेवा भी चालू की है जो कि चण्डीगढ़ से हरियाणा के विभिन्न शहरों के लिए हैं। निःसन्देह ये बसें भी बहुत ही अच्छी हैं। मान्यवर, इस मामले में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पटौदी में एक बस स्टैंड के निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है और उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। एक डीलक्स बस चण्डीगढ़ से गुड़गांव के लिए तो जाती है लेकिन नारनौल, महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी लिए कोई डीलक्स बस नहीं जाती है। परिवहन मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि चण्डीगढ़ से जयपुर के लिए भी डीलक्स बस

लगाई जाए। मान्यवर, अब मैं जन-स्वास्थ्य विभाग के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने सत्ता सम्भाली थी उस समय गांवों में पीने के पानी की बहुत कमी थी। आमतौर पर जनता को पानी के लिए बहुत दिक्कत थी और हमारी बहनों को सिर पर घड़े रख कर गांव से 2-2 या 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने गांव-गांव में टयूब्वैल तथा कैनाल बेस्ड डिग्गियां बनवा कर पूरे हरियाणा के अन्दर पेयजल की समस्या को हल करने के लिए निःसन्देह सराहनीय कार्य किया है। इस योजना में मुख्य मंत्री जी से मैं मांग करना चाहूँगा कि पटौदी में हेलीमण्डी में सीवरेज सिस्टम को भी ठीक किया जाए क्योंकि ये काफी बड़े गांव हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि पेयजल में अवैध कनैक्शन बहुत से गांवों में लगे हुए हैं। मैं सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन पेयजल के कनैक्शनों को जो गांवों में घरों के अन्दर अवैध कनैक्शन लोगों ने लगाए हुए हैं उन्हें रैगुलराईज किया जाए और उनसे कोई राशि महीने वाईज ले ली जाए जिससे सरकार को आर्थिक फायदा हो सके और लोगों को घरों में रैगुलर कनैक्शन मिल सकें। अवैध कनैक्शन तो अब भी चल रहे हैं अगर सरकार ऐसा करती है तो वे कनैक्शन वैध हो जायेंगे जिससे सरकार को आर्थिक फायदा होगा और विभाग को अपनी जन सुविधा को ठीक करने में सहायता मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद करूंगा और मुख्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा कि मेरे पटौदी विधान सभा क्षेत्र में 3 कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई की स्कीमें और उपाध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र को जोड़ कर 4 कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीमें मंजूर की गई हैं। इसमें माकड़ौला, इकाबलपुर खालिया वास, मुशेदपुर और बीरेड़ा शामिल हैं। इस स्कीम से लगभग 50 गांवों में जहां खारा पानी है वहां फायदा होगा। जहाँ पीने के पानी के लिए त्राही-त्राही मची हुई थी वहाँ पर मुख्य मंत्री जी ने कैनाल बेस्ड पानी और डिग्गियों की मंजूरी देकर उन लोगों के लिए बहुत सुविधा दी है। इसके लिए मैं एक बार फिर से मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट में अपनी बात कहें।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेष बात कहना चाहूँगा कि पिछले साल सरकार ने एक नई खनन नीति बनाई थी जिसके अन्तर्गत खुली बोली का प्रावधान किया गया था। इस बारे में इस सदन में लगभग 5-6 बार बहुत जोर-शोर से विचार-विमर्श किया गया था। विपक्ष के सदस्यों ने इस बारे में अनर्गल बातें भी की कि इस सरकार ने यह कर दिया, वह कर दिया। मेरे वे माननीय साथी सदन में नहीं हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि और यह कहना चाहूँगा कि इस सरकार से पहले पिछली सरकारों ने क्या-क्या बेकायदगियां की थी। मैं आपकी अनुमति से दो मिनट में उसके बारे में सदन को डिटेल में बताना चाहूँगा। चौधरी भजन लाल जी के राज में फरीदाबाद जिले में जो खाने इन्टरव्यू के माध्यम से और सिफारिश के माध्यम से जिसको अलाट की गई थी उनका नाम श्री रामचन्द्र बैंदा था जो आजकल बी.जे.पी. के फरीदाबाद से एम.पी. हैं उनको मोफताबाद की खान दी गई थी। मैसर्ज राम किशन पूर्णि देवी के लाल कृष्ण कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर होते थे उनको 346 हैक्टेयर बड़खल की खान दी गई थी। एक मैसर्ज पतराम माईन्ज एण्ड मिनरलज, प्राईवेट लिमिटेड, सराय जुलाना को दी गई। यह पतराम चौधरी भजन लाल जी का रिश्तेदार है इसको मानर की 126.725 हैक्टेयर की खान दी गई थी। एक मैसर्ज टी.एन. एन्टरप्राईजिज, सैक्टर 43, सोनीपत को दी गई। यह श्री धर्मपाल जी के रिश्तेदार हैं और श्री बचन सिंह आर्य इसमें पार्टनर हैं इन्हें कोट में 125 हैक्टेयर की खान 2-2-1995 को दी गई थी। यह फरीदाबाद की थी। उपाध्यक्ष महोदय, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की एक खान श्री रामचन्द्र बैंदा जो कि आजकल बी.जे.पी. के एम.पी. है उनको दी गई। उनको बंधवाड़ी की 314 हैक्टेयर की खान 16-3-1984 को दी गई थी। श्री मनी राम, 152, सराय जुलाना, न्यू दिल्ली, यह भजन लाल जी का रिश्तेदार है इनको मोहम्मदपुर अहीर की 93 हैक्टेयर की खान दी गई थी। एक मैसर्ज रवीन्द्र मक्कड़ एण्ड कम्पनी, वार्ड-6 हांसी, ये श्री अमीर चन्द मक्कड़ जो हांसी के एम.एल.ए. होते थे, उनके बेटे को दी गई थी। एक बरवाला के एक्स-मिनिस्टर थे उनको 143 हैक्टेयर की खान खारक सोहना में दी गयी है। इसी तरह से

[श्री रामबीर सिंह]

लाल चन्द, 312, आपका बाजार, गुड़गांव को जलालपुर सोहना में 91 हैक्टेयर की खान दी गयी है ये चौधरी भजन लाल जी के छोटे पुत्र कुलदीप बिश्नोई के साले साहब हैं। इसी तरह से मैसर्ज अब्दुल रज्जाक एंड एसोशिएट्स, वी.पी.ओ. पधानी, जिला गुड़गांव, को 70 हैक्टेयर की खान दी गयी है इसमें हमारे साथी जाकिर हुसैन की वाइफ पार्टनर हैं। इसी तरह से मैसर्ज तेजबीर सिंह एंड कम्पनी यू-24 रोड, टाउन हाउस डी.एल.एफ. फेज 3, गुड़गांव की बंधवाड़ी-11 में 91 हैक्टेयर की खान दी गयी है। ये हमारे साथी कैप्टन अजय सिंह यादव, जो कांग्रेस के हैं, कृष्ण मूर्ति हुड्डा एवं फुल चन्द मुलाना के क्लोज रिलेटिव हैं। इसी तरह से मैसर्ज सुभाष यादव एंड कम्पनी, यादव निवास अपोजिट एस.पी. आफिस, गुड़गांव को घमरोज में 106 हैक्टेयर खान दी गयी है ये हमारे साथी राव धर्मपाल जी के रिश्तेदार हैं। इसी तरह से मैसर्ज अरावली माईंज एंड सिल्का सैंड, हाउस नं. 1, राजेन्द्र कालोनी, लिंक रोड, सैक्टर 28 फरीदाबाद को रोजका गुज्जर में 29, हैक्टेयर की माईंज दी गयी है ये एक्स मिनिस्टर सरदार हरपाल सिंह के पुत्र की हैं।

राव इन्द्रजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अभी हरपाल सिंह जी का नाम लिया है जबकि वे तो इस समय हाउस में नहीं है इसलिए उनका नाम हाउस की कार्यवाही से निकलवाया जाना चाहिए।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, इनको शायद पता नहीं है कि रामबीर किस इशु पर बोल रहे हैं। मैं इनको बताना चाहूँगा कि जो खानें अलॉट की गयी हैं उस इशु पर रामबीर बोल रहे हैं।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो खाने चौधरी भजन लाल जी के समय में अलॉट की गयी थी मैं उनके नाम पढ़कर सदन में सुना रहा हूँ। ये खाने बगैर ऑक्शन किए या बगैर नोर्म्ज को अपनाए अलॉट की गयी थी। अगर आप चाहें तो मैं इस लिस्ट को दोबारा पढ़कर सुना सकता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : अगर ये कहें तो ही आप पढ़कर सुना सकते हैं। (विघ्न)

राव इन्द्रजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि खानें अनियमितता से अलॉट की गयी हैं लेकिन जो अपने आपको यहां पर डिफेंड ही नहीं कर सकता तो उसका नाम हाउस की कार्यवाही से निकलवा दिया जाना चाहिए क्योंकि वह तो नहीं बता सकता कि अनियमितता बरती गयी या नहीं बरती गयी। इसलिए उसका नाम कार्यवाही में नहीं आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : रामबीर जी तो इस बारे में लिस्ट दे रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, राव साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि सम्मानित सदस्य अपने भाषण में उन माईंज का जिक्र कर रहे हैं जो माईंज जिस-जिस के नाम से अलॉट हुई है और जो बेनामी सौदे हुए हैं। यह किसी पर आक्षेप नहीं हैं कि वे यहां आकर इस बारे में साबित करें। यह तो वह लिस्ट है जो सरकारी लिस्ट है इसलिए वे ये नाम तो गिनाएंगे ही। इनका तो इसमें नाम नहीं है लेकिन इनका घी सा जब घलेगा जब कैप्टन का नाम इसमें आयेगा।

राव इन्द्रजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ये चाहें तो इनको मंत्री बना दें। हम तब मान लेंगे कि ये सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। आज तो केवल वे एम.एल.ए. ही हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह लिस्ट दोबारा दोहरा दी जाए तो ठीक रहेगा।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की खनन नीति पर जो बजट में सरकार ने पैरा 9.7 में पेश की है, उसके विषय में बोल रहा हूँ। सरकार ने उस पुरानी नीति को बदलकर साफ और स्पष्ट नीति जो पेश की है मैं उसके बारे में बता रहा हूं। जो पिछली सरकार ने इस बारे में बेकायदगियां की थीं मैं उनका कच्चा चिट्ठा पढ़ रहा था। माननीय सदस्य को इसमें ऐतराज किस बात पर है यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं इस लिस्ट को दोबारा से पढ़कर सुना देता हूँ। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, कई साथी बाद में आए हैं इसलिए आप इजाजत दें तो मैं इसे दोबारा से पढ़ देता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दोबारा से पढ़ना कोई जरूरी नहीं है।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इसके आगे बताना चाहूँगा कि चौधरी भजन लाल जी ने कैसे बेकायदगियां करके, सिफारिश से और बगैर किसी नोर्म्स के खानें अलॉट की थी जिससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हुई। जिन लोगों के द्वारा करोड़ों रुपये के राजस्व की सरकार को चपत लगाई गई उनके नाम मैं पढ़ रहा हूँ। शिवकुमार, तुलसी राम, भादों कॉटन मिल्स, मंडी आदमपुर, डिस्ट्रिक्ट हिसार के हैं और चौधरी भजन लाल जी के क्लोज रिलेटिव हैं इनको रोजका गुज्जर में 28.25 हैक्टेयर की खान दी गई। इसके अलावा मैसर्ज प्रदीप एंड कंपनी, 59, मंडी आदमपुर, हिसार, को दी गई व ये श्री पोकर मल जी के पुत्र के पार्टनर हैं। पोकर मल जी चौधरी भजन लाल जी के धर्मभाई हैं।

चौ. भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। सारे हरियाणा की जनता मेरे भाई बहन हैं हमने बेईमानी नहीं की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक श्रीमती शिक्षा पूहाल वाइफ ऑफ श्री राजकुमार ऐक्स एम.एल.ए. 874, सेक्टर 12 पंचकूला की हैं, उन्हें बलोला-4 में 36.20 हैक्टेयर की खान 13.5.96 को अलॉट की गई थी। इसी प्रकार महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की कुछ खानें हैं श्री सुनील यादव, पुत्र श्री शेर सिंह, विलेज एंड पी.ओ. दुलोठ अहीर, डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़, ये राव नरेन्द्र सिंह एम.एल.ए. के रिलेटिव हैं। (शोर एवं व्यवधान) इनको भेदान्ती में 32.01 हैक्टेयर की खान अलॉट की गई थी।

चौ. भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है ये किस विषय पर बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

पशुपालन राज्य मंत्री (चौधरी मोहम्मद इलियास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता देता हूँ। ये इस बात पर बोल रहे हैं कि आदरणीय चौधरी बंसी लाल जी 4 दिन से यहां हाउस को गुमराह कर रहे हैं। जहां उनके राज में खानों से मात्र लाखों रुपये मिलते थे उसकी बजाय आज करोड़ों रुपये का रैवेन्यू सरकार को आ रहा है। भजन लाल जी, मैं भी आपकी सरकार में मंत्री था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपने भी किस तरह से खानों का बंटवारा किया था। मैं आदरणीय सदस्य भाई रामबीर जी से अनुरोध करूंगा कि इस लिस्ट को दोबारा से पढ़ दें।

चौ. भजन लाल : इलियास जी, हमने तो आपको भी खान दी हुई है। आपको नहीं मिली क्या ?

चौ. मोहम्मद इलियास : आपने अपने चहेतों को खानें अलॉट की थीं। मुझमें तो आप को विश्वास ही नहीं था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामबीर सिंह : आप लोगों ने लूट मचाई हुई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राम किशन फौजी, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान) आपको भी मौका मिलेगा अभी आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय ******* (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय ******** (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जायें।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मोहताबाद में 5.8.83 को 296 हैक्टेयर की खान रामचन्द्र बैंदा को दी गई जो आजकल बी.जे.पी. के फरीदाबाद से एम.पी. हैं इनको ये खान चौधरी भजनलाल जी ने अलॉट की। एक खान मैसर्ज रामकिशन पूर्णी देवी, 408, सैक्टर 16ए, फरीदाबाद को दी। रामकिशन पुत्र चौधरी लाल सिंह एक्स मिनिस्टर को बड़खल में 346.50 हैक्टेयर की खान 30.1.84 को दी। एक मांगर की खान पतराम माईंज एण्ड मिनरलंज प्राइवेट लिमिटिड, सरायजुलाना श्री पतराम जोकि माननीय भजनलाल जी के रिलेटिव हैं को मांगर की

[श्री रामबीर सिंह]

126.725 हैक्टेयर की खान 27.7.84 को दी गई। मैसर्ज पी.एम. इंटरप्राइजिज, 43 सैक्टर 15, सोनीपत, जो श्री धर्मपाल मलिक और श्री बच्चन सिंह आर्य की कम्पनी है उसको 125 हैक्टेयर की खान कोट गांव फरीदाबाद में दी गई। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. बंसीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो आदमी सदन में मौजूद नहीं है और जो जवाब नहीं दे सकता क्या उसका नाम सदन में लिया जा सकता है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी बंसीलाल जी आप बैठिये।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसीलाल जी जैसे सीजन्ड पोलिटिशियन जो लम्बे समय तक इस सदन के सदस्य रहे हों, मैं उनको बताना चाहूँगा कि बजट के मुताबिक उन लोगों के नाम जिन लोगों को खानें दी गई हैं और जो लिस्टिड नाम हैं वो लिस्टिड नाम पढ़े जा सकते हैं। इस महान सदन का कोई ऐसा सदस्य जिसके प्रति कोई आब्जैक्शन किये जा रहे हैं उनके नाम नहीं हैं ये तो लीज होल्डर्ज हैं। अभी तो आपके लीज होल्डर्ज के नाम आ रहे हैं।

चौ. बंसीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्राइवेट मैम्बर नाम नहीं ले सकता। सरकार सदन के पटल पर कोई कागज रखना चाहे तो रख सकती है लेकिन पढ़ नहीं सकती और प्राइवेट मैम्बर तो बिल्कुल नहीं कह सकता।

श्री उपाध्यक्ष : रामबीर सिंह जी आप जल्दी कंक्ल्यूड करें।

चौ. भजनलाल जी : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई बजट स्पीच है ये सुबह से असत्य बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजनलाल जी आप सुनने की क्षमता रखें।

राव इन्द्रजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में रूलिंग दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : इन्द्रजीत जी आप बैठ जाइये।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, गुड़गांव जिले में बंधवाड़ी खान श्री रामचन्द बैंदा, 1492, सैक्टर 14, फरीदाबाद, जो आजकल बी.जे.पी. के एम.पी. हैं, उनको 314 हैक्टेयर की खान चौधरी भजनलाल जी ने 16.3.84 को दी।

श्री उपाध्यक्ष : रामबीर सिंह जी आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर कुछ नाम दे दीजिये।

श्री रामबीर सिंह : मनीराम सराय जुलाना को, मोहम्मदपुर अहीर को, 92 हैक्टेयर की खान जोकि चौधरी भजन लाल जी के रिश्तेदार हैं को दी।

श्री उपाध्यक्ष : रामबीर सिंह जी आप कंक्ल्यूड कीजिये।

श्री रामबीर सिंह : जलालपुर की खान .... (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये क्या बोल रहे हैं इनको बैठाइये।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी आप बैठिये, आपसे पूछकर थोड़े ही बैठाउंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, लालचन्द, आपका बाजार, गुड़गांव में जलालपुर, सोहना की 91 हैक्टेयर की खान कुलदीप बिश्नोई, जो चौधरी भजनलाल जी के छोटे बेटे हैं, इनके साले को दी गई। हांसी के रविन्द्र मक्कड़ को खरक सोहना की 143.32 हैक्टेयर की खान दी गई। तेजबीर सिंह एण्ड कम्पनी, स्माल वर्ड नर्सरी स्कूल

फेस-3, गुड़गांव को बंधवारी-II की 91.20 हैक्टेयर की खान दी गई जिसके पार्टनर कैप्टन अजय सिंह यादव, कृष्ण मूर्ति हुड्डा और फूलचन्द मुलाना के नजदीकी रिश्तेदार हैं।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

कैप्टन अजय सिंह यादव एम.एल.ए. द्वारा

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : कैप्टन साहब, जिस पार्टनरशिप का नाम रामबीर जी ने लिया है, आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन में बताएं कि क्या वह गलत है।

Capt. Ajay Singh Yadav : *Sir, it is my right. It is my personal explanation. They named me.* (Interruptions)

श्री उपाध्यक्ष : कोई मैम्बर दूसरे मैम्बर को नेम नहीं कर सकता, नेम तो चेयर करती है, हाँ आपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन देनी है तो दो। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे माननीय साथी रामबीर जी कह रहे हैं मैं इनको बताना चाहूँगा कि जो भी खान हमें गवर्नमेंट ने दी है वह नॉर्म्स के मुताबिक ही दी है, बाकायदा उसके लिये इंटरव्यू लिए गए हैं। इनकी पार्टी के एम.एल.ए. तेजबीर सिंह उसमें मैम्बर हैं, इसके लिए हम सेल्ज टैक्स भर रहे हैं, रॉयल्टी भर रहे हैं इनकी तरह कोई डकैती नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठें।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो इनको यह बताना चाहिए कि इनकी पार्टनरशिप है या नहीं। मैं और कैप्टन साहब जब एस्टीमेट कमेटी के मैम्बर थे तो एक बार जिक्र हो गया और इन्होंने कहा था कि मैं भजनलाल का बहुत अहसानमंद हूँ कि उन्होंने ऑउट ऑफ नॉर्म्स जाकर मुझे माइंज दी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नेता और उप नेता दोनों खड़े हैं आप डिसाइड कर लो कि किसने बोलना है।

चौ. भजनलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिजनैस करता है वह अपने हिसाब से करता है, फ्री नहीं करता और न ही कोई फ्री देता है। कायदे कानून के हिसाब से जो पैसा देना चाहिए वह इन्होंने दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : भजनलाल जी, आप बैठें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी ने एक बात कही है कि कोई फ्री नहीं दी तो इसका मतलब कुछ लेकर दी है क्या। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यही कहा है कि गवर्नमेंट पैसा लेती है और नार्म्स के मुताबिक ही खानें दी गई हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : नॉर्म्स के मुताबिक ही दी जाती हैं तभी तो उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि नेता और उप नेता दोनों खड़े हो गए। लेकिन यह रिश्ता नेता और उप नेता का नहीं है बल्कि यह रिश्ता लेने वाले और देने वाले का है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये बातें इनको याद रहती हैं, हमारे दिमाग में ये बातें नहीं रहती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप बिना परमीशन बोल रहे हैं इसलिए आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन साहब, आप बैठें। आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया था। धर्मबीर जी आप भी बैठें। रामबीर जी आप बोलें। (शोर एवं व्यवधान) धर्मबीर जी प्लीज आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन साहब आप बार-बार न उठें। (शोर एवं व्यवधान)

वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि जो बजट का पैरा 97 है मैं उस पर बोल रहा हूं। मैं गुड़गांव का रहने वाला हूं और मैंने इस बारे में जो भी जानकारी ली है वह अपने सोर्सिज से एकत्रित की है, सरकार से नहीं ली। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब प्लीज आप बैठें। रामबीर जी सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि पहले और आज के सिस्टम में क्या अंतर है। (शोर एवं व्यवधान) जय प्रकाश जी, प्लीज आप भी बैठें।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ के दोस्तपुर गांव में एक खान, 4.90 हैक्टेयर की भूपेन्द्र सिंह सपुत्र श्री मदन पाल सिंह जो कि बापोड़ा गांव का है, उसको दी गई और वह हमारे एक्स स्पीकर श्री छत्रपाल चौहान का रिलेटिव है। यह खान चौधरी बंसी लाल जी ने दी थी। इसी तरह से कैलाश चन्द्र शर्मा जो कि योजना बोर्ड के एक्स उपाध्यक्ष थे उनके रिश्तेदार ओम प्रकाश शर्मा, जो कि नारनौल का रहने वाला है, को भी एक खान दोस्तपुर गांव में 4.92 हैक्टेयर की दी गई। यह भी चौधरी बंसी लाल जी ने दी थी। इसी तरह से रमाकांत भारद्वाज सपुत्र श्री नित्यानंद भारद्वाज वी.पी.ओ. कुण्ड, जिला रेवाड़ी, जो कि राम बिलास शर्मा, एक्स मिनिस्टर का रिलेटिव है, उसको भी दोस्तपुर गांव में 4.932 हैक्टेयर की खान दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. के भाई कृष्णपाल गुर्जर आज यहां बैठे नहीं हैं वे बजट पर बोलते हुए कह रहे थे खानों में ये किया गया, वो किया गया, माननीय बंसी लाल जी भी ऐसा ही कह रहे थे। अगर कृष्ण पाल जी आज यहां बैठे होते तो पता लग जाता कि उनके समय क्या किया गया था।

श्री उपाध्यक्ष : रामबीर जी आप एक मिनट में वाइंड अप करें। (विघ्न)

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि कृष्ण पाल जी यदि आज यहां बैठे होते तो उनको पता लग जाता कि उनके समय में क्या हुआ था। रामचन्द्र बैंदा जो कि बी.जे.पी. के लोक सभा सदस्य हैं, उनको खान चौधरी भजन लाल जी ने दी। इनकी मिली भगत से साफ जाहिर है कि हमारे जो बी.जे.पी. के नेता कृष्ण पाल जी हैं उनके दिल में क्या दर्द था। उपाध्यक्ष महोदय, जिन खानों का मैंने जिक्र किया है और जिनको मैंने यहां पढ़कर सुनाया है उनसे पहले 17.22 करोड़ रुपये का रैवेन्यू आता था और हमारी सरकार ने इन खानों को खुली बोली पर दिया है तथा अब इन खानों से 65.86 करोड़ रुपये का सरकार को रैवेन्यू प्राप्त हुआ है। सेल्ज टैक्स इसमें शामिल नहीं है वह अतिरिक्त है। आप समझ सकते हैं कि 17.22 और 65.86 करोड़ में कितना अंतर है। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के समय में खानों की बोली में किसी तरह की पेचीदगी नहीं हुई जिसका नतीजा है कि सरकार को पहले से अधिक रैवेन्यू मिल रहा है और मैं पूरे सदन को बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने खानों की नीलामी में पूरी पारदर्शिता बरती है।

श्री धर्मबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, *******

श्री उपाध्यक्ष : धर्मबीर जी की कोई बात रिकॉर्ड न की जाए।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री रामबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जहां इतने अच्छे-अच्छे कार्य किए, जन हित के कार्य किए वहीं मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि हमारे इलाके में सरसों और फूलों की खेती बहुत ज्यादा होती है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कृषि उत्पादन के लिए प्रोसैसिंग यूनिट लगाने के लिए कुछ छूट दी जाये या कुछ सबसिडी दी जाये। कृषि को लघु उद्योग का दर्जा देते हुए जो लोग कृषि उद्योग लगाना चाहते हैं उनको सबसिडी दी जाए। जो कृषि पर आधारित उद्योग लगाना चाहते हैं उनको कृषि यूनिट लगाने पर छूट दी जाये।

श्री उपाध्यक्ष : रामबीर जी, वाईंड अप कीजिए।

श्री रामबीर सिंह : अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रोफैसर सम्पत सिंह जी ने हरियाणा का जो बजट इस सदन में पेश किया है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। आज 21वीं सदी चल रही है और आज का युग एक स्पेशलाईजेशन का युग माना जाता है। हरियाणा प्रदेश के लोग और यह सदन प्रोफैसर सम्पत सिंह जी से यह उम्मीद करता था कि ये अपनी बजट स्पीच तैयार करने से पहले हरियाणा में या देश में जो बहुत अच्छे इकोनोमिस्टस हैं, जो फाईनैंस और अच्छी नीतियों को जानते हैं, उनसे सलाह लेंगे या जिन अच्छे लोगों के अखबारों के माध्यम से लेख आते हैं या सैमीनारों के माध्यम से जो इकोनोमिस्टस अपने विचार देते हैं उनसे विचार-विमर्श करके ये अपना बजट तैयार करते तो मैं समझता हूं कि ये हरियाणा प्रदेश की अच्छी सेवा कर सकते थे। उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी सत्ता का, पार्टी का या दूसरी पार्टी का मुद्दा नहीं है। आज हमारे को आजाद हुए 52 साल हो गए। हमारा प्रदेश देश की राजधानी दिल्ली के किनारों को तीन तरफ से छूता है। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी सरकार यदि इस प्रदेश की समस्याओं को गम्भीरता से लेकर के चले तो वह दिन दूर नहीं जब यह हरियाणा प्रदेश हिन्दुस्तान के सभी प्रदेशों में नम्बर एक का प्रदेश माना जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने जो बजट स्पीच तैयार की है उस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बजट से संबंधित जो मैग्जीन आती है उसको मैं एक दिन पढ़ते हुए आ रहा था। उस मैग्जीन में मैंने पढ़ा कि जो एफ.डी.आई. है (फौरन डायरेक्ट इन्वैस्टमेंट) वह इस देश की अर्थ-व्यवस्था का एक मुख्य क्षेत्र है। एफ.डी.आई. का आज हिन्दुस्तान में यदि सबसे ज्यादा प्रभाव है तो वह महाराष्ट्र में है उसके बाद फिर कर्नाटक में, तमिलनाडु में और आन्ध्रप्रदेश में है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम दिल्ली के इतने नजदीक भी हैं और हमारे हरियाणा के लोग बहुत मेहनतकश भी हैं। आज हरियाणा का नौजवान काम करना चाहता है। इस बारे में मेरा कहना है कि इस सदन में हम सभी सदस्यों को इस बात की चिन्ता करनी चाहिए कि एफ.डी.आई. का प्रभाव साऊथ के उन प्रदेशों में क्यों जा रहा है जबकि हम दिल्ली के इतने नजदीक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी का बहुत लम्बा अनुभव है। अब ये बजट पेश कर चुके हैं। इस बारे में मेरा सुझाव है कि आप इस बारे में देश के अच्छे-अच्छे इकनोमिस्टस को बुलावें और उनसे सलाह लें। चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के जो प्रतिनिधि हैं उनको आप बुला लें और उनसे सुझाव भी ले लें तो अच्छा होगा। सम्पत सिंह जी, अच्छा यह होता कि हरियाणा में जो पढ़े लिखे अच्छे लड़के हैं और जो इकोनोमी के बारे में जानते हैं, या जो हरियाणा प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम के माध्यम से जो चेयरमैन हैं या ब्लाक समिति के जो चेयरमैन हैं, उनकी भी सलाह लेते। मैं तो इसमें भी बुरा नहीं मानता कि अगर आप विपक्ष के उन सदस्यों से जो इस विधान सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं, और जो कई दफा जीत कर आ चुके हैं उनसे सलाह लेते तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर आप इन वरिष्ठ साथियों से सलाह मश्विरा करते और उनसे परामर्श मांगते तो ये हरियाणा के लोगों की एक बहुत बड़ी सेवा होती। इन्होंने ऐसा न करके जो गलती की है, उसको ये सुधार सकते हैं। अब भी ये उनसे सलाह - मश्विरा लेकर अपनी गलती को सुधार सकते हैं क्योंकि अब भी ये कोई ज्यादा लेट नहीं हुए हैं। इसी तरीके से इन्होंने बजट में जिन भी स्कीमों को दिखाया है उनमें इन्होंने यह बताने की कोशिश नहीं की कि जो इतना पैसा कर्ज लेते जा रहे हैं उसकी भरपाई ये लोग कहां से करेंगे। पहले ही

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

हरियाणा में 15,000 करोड़ के कर्जे लोगों के सिर पर हैं अभी तक तो वह कर्जा ऐसे ही खड़ा है। (विघ्न) 15,000 करोड़ रुपये का कर्जा तो पिछले साल था अब हो सकता है और भी ज्यादा हो रहा होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो इतना कर्जा ये लोग ले रहे हैं उसकी भरपाई आखिर कहां से करेंगे। इस कर्जे के लिए जो ब्याज है उसमें हरियाणा की जनता के खून पसीने की कमाई लगाते जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं कि शहरों के विकास के लिए आज भी कई बिल आ रहे हैं और बजट में भी इन्होंने इसकी चर्चा की है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का बहुत दु:ख होता है कि गांवों में रहने वाले लोगों के प्रति यह सरकार क्या विचार रखती है और गांवों में रहने वाले लोगों को यह सरकार कौन सी सुविधाएं देना चाहती है। आज गांवों में जो भी व्यक्ति कुछ अच्छा खाना कमाना सीखता है तो उसकी पहली कोशिश होती है कि वह शहर की तरफ आए। हमारे गांवों की सभ्यता खत्म होने जा रही है। यह क्यों खत्म होने लग रही है। आप भी गांव के रहने वाले हैं आप भी जानते हैं। गांवों की सभ्यता खत्म होने का कारण है कि कोई भी सरकार गांवों में रहने वाले लोगों के प्रति जागरुक नहीं है। आज गांवों में रहने वाले लोगों की हालत देखिये। हमारी बहन बेटियां जो कि बड़े-बड़े गांवों में रहती हैं उन्हें 4-4 या 5-5 किलोमीटर चल कर शौचालय के लिए जाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण और नई गलत प्रणाली की वजह से हमारे हरियाणा में यह प्रथा चल पड़ी है कि बड़े-बड़े गांवों और छोटे-छोटे गांवों के किसानों ने गांवों के अन्दर अपने मकान छोड़ कर खेतों में अपने मकान बनाने शुरू कर दिए हैं जिस के कारण खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण यही है कि वहां पर लोगों को जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वे नहीं मिल पाती हैं इसलिए वे या तो शहरों की तरफ भाग रहे हैं और यदि शहरों में नहीं जा सकते तो वह खेतों में ढाणी बना रहे हैं और वहां पर पक्के घर बना रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सम्पत सिंह जी से यह कहना चाहूंगा कि गांवों की तरफ ध्यान दें। खासकर जो बड़े-बड़े गांव हैं उनमें हरिजन परिवार, बैकवर्ड परिवार और जोकि गरीब हैं उनके लिए प्लाटों की व्यवस्था करनी चाहिए। गांवों में अच्छे स्कूल होने चाहिएं। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने शिक्षा के बारे में बजट में जो प्रस्ताव दिए हैं उनके बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय प्रो. सम्पत सिंह जी से तथा हमारे माननीय शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वह अच्छी शिक्षा की है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप वाईण्ड अप करें। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूं आप मुझे जब भी कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : दलाल साहब, आपका समय 6 मिनट था लेकिन आपको बोलते हुए 8 मिनट हो चुके हैं इसलिए 5 मिनट के अन्दर आप अपनी स्पीच को कंकल्यूड करें। (विघ्न) इसमें गलत और ठीक की कोई बात नहीं है। टाईम एलोकेशन की बात है वह मैं आपको बता रहा हूं। आप विद इन फाईव मिनटस अपनी बात समाप्त करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा की बात कह रहा था। आज हरियाणा सरकार गांवों और शहरों में शिक्षा पर इतना पैसा खर्च कर रही है लेकिन आज हालात क्या हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकारी स्कूल हैं चाहे वे हाई स्कूल हैं चाहे वे प्राईमरी स्कूल हैं वहां पर बच्चे नजर नहीं आते हैं। उनके मन में यह विश्वास नहीं रहा है कि सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई होगी। आज गांवों और शहरों में 3-3 या 4-4 बड़े मकान लेकर हाई स्कूल और 10 जमा 2 के स्कूल लोगों ने खोले हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के मामले में हरियाणा के लोगों में इतनी ज्यादा असमानता आ रही है जिसके कारण लोगों का सरकारी स्कूलों में कोई विश्वास नहीं रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों यह चर्चा थी कि सरकार ने कॉलेजों के लेक्चरर्ज़ पर टयूशन के लिए बैन लगाया है। इन्हें टयूशन्ज़ पर बैन लगाने की बजाए इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो गांवों के लोग हैं या शहरों के गरीब

तबकों के लोग हैं और जिनकी पिछली पढ़ाई कमजोर रही है वे अपनी कमजोरी ट्यूशन पढ़ कर ही दूर कर सकते हैं। अगर सरकार इसे ठीक नहीं समझती तो सरकार को इसका कोई और इन्तजाम भी करना चाहिए। जैसे कॉलेजों में और गांवों के स्कूलों में अतिरिक्त अध्यापक नियुक्त करें जो ट्यूशन के तौर पर अतिरिक्त पढ़ाई उनको करवा सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जो हैल्थ का डिपार्टमैंट है उसके बारे में इन्होंने कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हैं कि हर शहर के जो डॉक्टर्ज हैं उन्होंने अपने प्राईवेट क्लीनिक खोले हुए हैं। अगर बहन बेटियों का जापा होना हो तो उनको गुमराह करके जो जापा सीधे तौर पर भी हो सकता है वह अनाप शनाप तरीके से होता है। उसके लिए प्राईवेट क्लीनिक वाले काफी पैसा लेते हैं। इसके लिए सरकारी अस्पतालों में सरकार को पूरी सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। पिछले दिनों सरकार ने अस्पतालों में जाने वाले हर आदमी को 5 रुपये की पर्ची कटवाना अनिवार्य किया है इसके साथ यह भी किया है कि पोस्टमार्टम के लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1986 में इंग्लैंड गया था। मैंने देखा कि वहां पर सरकार ही व्यवस्था करती है कि वहां के हर नागरिक का मैडीकल सर्टिफिकेट जरूर बनें। वे लोगों की सेहत पर इतना ध्यान देते हैं और उस पर जो भी खर्चा होता है उसको सरकार वहन करती है। हमारे यहां पर पहले लोगों के मन में सरकारी अस्पतालों पर विश्वास नहीं था और अब जो इस सरकार ने लोगों से और पैसा वसूलने की कोशिश की है इससे उनके मन से सरकारी अस्पतालों पर से बिल्कुल विश्वास उठ गया है इसलिए सरकार इस फीस को फौरन वापिस ले। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों का सरकारी अस्पतालों के ऊपर विश्वास बढ़े।

श्री उपाध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, आप कन्कल्यूड करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिला फरीदाबाद में और आपके जिला गुड़गांव में सबसे बड़ी समस्या खेती के पानी की है। पिछले दिनों मुख्य मंत्री जी यहां पर एस.वाई.एल. के नाम पर प्रस्ताव लाए उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। उस वक्त मैंने तो केवल एक निवेदन किया था कि अगर हरियाणा में एस.वाई.एल. का पानी आता है तो जिला फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, अहीरवाल और रोहतक के इलाके, जिनका उस पानी पर हक है, उनको वह पानी मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हरियाणा में पानी आया था और उस वक्त के मुख्य मंत्री जी उस पानी को अपने जिलों में लेकर चले गए थे और हमारे इलाके के लोग पानी के लिए तरसते रह गए थे। आज हमारा किसान बेबसों की तरह ताकता रहता है। तरसता रहता है लेकिन पानी नहीं आता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अभी भी वही अनुरोध करूंगा कि एस.वाई.एल. के पानी के बंटवारे के मुद्दे पर सभी दलों की एक कमेटी गठित की जाए और वह नहर के निर्माण की निगरानी करे, साथ में जो पानी आएगा, वह किन-किन जिलों में कितना कितना जाना चाहिए इस बारे में भी देखें।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज कन्कल्यूड करें कर्ण सिंह जी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कन्कल्यूड ही कर रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों इस सरकार ने जो राई में बहुत बड़ी हार्टिकल्चर की इन्टरनैशनल मण्डी बनानी थी उस मण्डी को एच.एस.आई.डी.सी. के हवाले कर दिया है जोकि इस सरकार ने बहुत गलत काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने बजट स्पीच में कहा है कि यह सरकार हरियाणा में शूगर मिल्ज़ लगाने जा रही है। मेरा आपके माध्यम से चौधरी सम्पत सिंह जी से और मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि हरियाणा शूगर मिल के मामले में बहुत अच्छा प्रदेश साबित हो सकता है, इस देश का मार्गदर्शक हो सकता है अगर प्रदेश में टिस्सू कल्चर्ड बेस्ड लैबोरेट्री बन जाए। आज देश में अगर टिस्सू कल्चर्ड लैबोरेट्री कहीं है तो शायद वह बंगलौर में है। अगर आज हरियाणा में गन्ने के उत्पादन के लिए टिस्सू कल्चर्ड बेस्ड लैबोरेट्री अगर कहीं एग्रोकल्चर डिपार्टमैंट बना देता है तो उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में जिस किस्म का गन्ना पैदा होगा वैसा गन्ना हिन्दुस्तान में कहीं नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल जी, आप बैठ जाएं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, मैं कन्कल्यूड कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट में कन्कल्यूड करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक इन्होंने लोन रिकवरी के बारे में कहा है। मैंने प्रश्न काल में देखा कि इन्होंने कहा कि बिलों की अदायगी बहुत अच्छी है। यह बड़ी अच्छी बात है कि बिलों की अदायगी होनी चाहिए। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण लोगों से ही यह क्यों होती है। जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं जिनकी तरफ करोड़ों रुपए बिजली बोर्ड के बकाया हैं उनके बारे में सदन में कभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। (विघ्न) गांवों में ही लोगों से सरकार जबरदस्ती से बकाया वसूली करती है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी हमारे पलवल में गए थे। हमारा इलाका उत्तर प्रदेश से लगता हुआ है वहां पर अलीगढ़ रोड है। उस रोड से हजारों की संख्या में लोग और वाहन रोज गुजरते हैं। क्या उस रोड पर कोई पुल बनाए जाने का सरकार का कोई प्रावधान है अगर सरकार यह प्रावधान कर देती है, चाहे इसका प्रावधान टोल टैक्स से ही कर दें, तो उससे हरियाणा प्रदेश को भी फायदा होगा और हमारे इलाके के लोगों को भी फायदा होगा। इसके साथ ही वहां पर आने जाने वाले हजारों लोगों को भी सुविधा मिल जाएगी। दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में बिजली की तारें लोगों के खेतों में और उनकी घर की छतों पर लटकती रहती हैं। यह सरकार कम से कम यह व्यवस्था तो कर सकती है कि उन तारों को खिंचवा लें। इसमें तो सरकार के पैसे नहीं लगेंगे। इसके अलावा पलवल शहर और वहां के गांवों में पीने का पानी और खेती का पानी बिल्कुल न के बराबर है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज कन्कल्यूड करें कर्ण सिंह जी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मैंने कोई गलत बात नहीं की है।

श्री उपाध्यक्ष : कर्ण सिंह जी बात गलत बात की नहीं है आपका 5 मिनट का समय था और आपको बोलते हुए 15 मिनट हो गए हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सुझावों को यह सरकार मान ले तो हरियाणा की जनता का बहुत भला हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपके सुझाव मंत्री जी लिख रहे हैं अब आप बैठें। अब श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्यगण, कांग्रेस का जो समय था उससे ज्यादा समय उनको बोलने के लिए मिल चुका है लेकिन फिर भी श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को बोलने का समय दिया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : भूपेन्द्र सिंह हुड्डा आपकी पार्टी के नेता हैं इसलिए उपाध्यक्ष इनको आउट आफ दि वे जाकर टाईम दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप ये बताएँ कि ये आपकी पार्टी के नेता है कि नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (किलोई) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सभी साथियों ने, हर पार्टी ने अपने-अपने विचार यहां पर बजट के बारे में रखे। वित्त मंत्री जी ने यहां पर इस साल का बजट पेश किया और हर साल ये बजट पेश करते हैं। जितने इनके पास साधन थे इन्होंने उनका प्रयोग किया और इसको ठीक ठाक रखने की इन्होंने काफी मेहनत की और ये हर साल करते रहेंगे। लेकिन अब की बार जो इनका बजट आया है वह पूरे प्रदेश के लिए चिंता की बात है। बजट में जिस प्रकार से घाटा बढ़ा हुआ दिखाया गया है बीस हजार करोड़ रुपये के करीब प्रदेश पर कर्ज है मैं समझता हूँ कि जो टोटल असैट्स हरियाणा गवर्नमैंट के हैं, जितनी सम्पदा है, उससे भी डेढ़ हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने अपना मकान ही गिरवी रख दिया तो आगे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। डैट बढ़े हैं। इसी तरह जो पिछले साल ये बजट

लेकर आए थे उसके बाद बजट ऐस्टीमेटस और रैवेन्यू ऐस्टीमेटस में साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये कम हुए थे क्योंकि पिछली बार पब्लिक डैटस जो पिछली बार 37 परसैंट थे जो बढ़कर 39 परसैंट हो रहे हैं। जैसे जब हम अपने घर में पैसा लाते हैं तो देखते हैं कि किधर-किधर पैसा खर्च करना है इसी तरह से जब बजट लाया जाता है तो देखा जाता है कि भावना किधर है और किस दिशा में प्रदेश को ले जाना है। बजट बनाते वक्त हमारा क्या नजरिया होना चाहिए। हमारा नजरिया यह होना चाहिए कि जो भी बजट आप ला रहे हैं उसमें आप देखें कि उससे गरीब से गरीब आदमी को फायदा पहुँच रहा है या नहीं। वित्त मंत्री जी ने जो बजट दिया है मैं समझता हूँ कि उससे मध्यम वर्गीय लोग और गरीब वर्ग के लोग कुछ भी उम्मीद नहीं रख सकता। वह इससे यह सोच ही नहीं सकता कि आने वाले समय में उसके हित में कुछ होगा। यह बिल्कुल निरस्त बजट है। इस बजट का जो 202 करोड़ रुपये का घाटा बढ़ रहा है उसको कैसे वित्त मंत्री जी पूरा करेंगे। वित्त मंत्री जी ने इस बारे में इंडीकेशन भी नहीं दिया है इसका मतलब क्या है कि जैसा पिछली बार यहां पर वायदा किया गया था कि हम कोई नया कर नहीं लगाएंगे लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कर, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे भट्ठी टैक्स हो या चाहे प्रोफैशनल टैक्स हो, लगाए गए थे। इसी तरह से जिस तरह बिजली के मीटर्ज लगाने में धांधलेबाजी की गयी है वह भी देखने वाली बात है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो व्यक्ति हरियाणा में रहता है, पंचकूला में रहता है, उसको डेढ़ रुपये प्रति यूनिट चंडीगढ़ या मोहाली के रेट से ज्यादा देना पड़ता है। इसी तरह से टयूबवैल्ज़ की बात कही गयी कि सरकार ने बिजली के इतने कनैक्शंज दिए हैं लेकिन यह नहीं बताया कि कितने कनैक्शंज काटे गए हैं। अगर आज हरियाणा में एक टयूबवैल की एवरेज लागत लें तो चार एकड़ पर एक टयूबवैल लगता है जिससे खेती की लागत बढ़ती ही जा रही है। किसी भी टयूबवैल का 12 हजार रुपये से कम साल का खर्चा नहीं होता है तीन हजार प्रति एकड़ टयूबवैल का खर्चा एवं बिजली का खर्चा किसान को देना पड़ रहा है। आज जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, एस.टीज़ तो हमारे प्रदेश में नहीं हैं लेकिन हमारे प्रदेश में बीस परसैंट शिडयूल्ड कास्टस एवं इतने ही बैकवर्ड क्लासिज के लोग हैं, उनके लिए बजट में क्या प्रावधान है? उनके साथ इस बजट में एक किस्म का मजाक किया गया है बजट में कहा गया है कि एस.सीज. के 12,500 लोगों को मदद दी जाएगी, फाईनैंशियल इंस्टीच्यूशंज उनको मदद करेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनसंख्या दो करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है जिसमें से बीस परसैंट इनकी जनसंख्या है। केवल 12,500 एस.सीज़. के लोगों की मदद की जाएगी और इसके लिए केवल 46.96 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से बैकवर्ड क्लासिज के केवल 2500 लोगों को ही मदद दी जाएगी और इसके लिए पैसा केवल नौ करोड़ रुपये ही रखा गया है। अब इस प्रदेश का गरीब आदमी, शिडयूल्ड कास्टस एवं बैकवर्ड क्लासिज के लोग इस बजट से क्या लेकर जाएंगे? किसान तो पहले ही बुरी तरह से पिट चुका है। आज किसान चाहे कोई भी फसल पैदा करता हो, चाहे वह धान पैदा करता हो, चाहे गेहूं पैदा करता हो या चाहे वह कोई और फसल पैदा करता हो, उसकी लागत बहुत बढ़ गयी है। जो किसान धान की खेती करता है उसका प्रति एकड़ 11,200 रुपये खर्चा आता है जबकि उसकी आमदनी कम है। बढ़िया से बढ़िया बासमती धान यदि वह पैदा करे और 25 मन अगर एक एकड़ में फसल हो तो दस हजार रुपये उसको मैक्सीमम मिलता है। इसी तरह से मोटा धान यदि वह पैदा करे तो उसमें उसकी लागत 10,800 रुपये आती है और गेहूं की लागत 11,750 रुपये प्रति एकड़ आती है जबकि उसको आमदनी 10,800 रुपये प्रति एकड़ की ही होती है। आज किसान की कोई भी खेती लाभदायक नहीं रही है। मक्की और बाजरे की खेती में भी ढाई हजार रुपये या तीन हजार रुपये की लागत प्रति एकड़ आती है जबकि इतनी आमदनी किसान को नहीं हो पाती है। जब उसको आमदनी नहीं हो पाती है तो किसान कहां जाएगा? ये बातें आपको देखनी हैं। अब सवाल यह आता है कि इन बातों का क्या किया जाए। सुझाव क्या हों और इस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है। आज सबके सामने अंधकार ही नजर आ रहा है। इन्होंने बजट में कई बातें कह दीं। इन्होंने एलीमैंट्री एजुकेशन के बारे में यह भी कह दिया कि 'Earn While You Learn' लेकिन कोई रास्ता तो नहीं दिखाया कि जो पढ़ रहे हैं कैसे उनकी मदद करेंगे। यह बात ठीक है कि those who reads they lead लेकिन आप क्या सुविधा देंगे। शिडयूल्ड कास्ट्स की बात होगी तो

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

छात्रवृत्ति आप उनको देंगे ? वह तो पहले से ही चल रही है। कितने और व्यक्तियों को आप देंगे। ऑन मेरिट तो सब जगह मिलती है लेकिन आम आदमी इस बजट से क्या उम्मीद लेकर जाएगा ? यह मेरी समझ से बाहर की बात है जैसा मैंने कहा है घर तो गिरवी रख दिया गया है अब बर्तन बेचने की नौबत आ गई है। (विघ्न) जायदादें बिक रही हैं और उससे घाटा पूरा किया जा रहा है। आपने देखा कल के अखबार में खबर थी कि जमीन बादल साहब को सस्ते दामों पर दी गई। मेरे को इस बात का ऐतराज नहीं है कि बादल साहब को दी या किसको दी ? ऐतराज इस बात पर है कि मार्किट वैल्यू से कम दाम पर जमीन बेचकर सरकारी खजाने को जो नुकसान हुआ वह किसका नुकसान हुआ हर गरीब आदमी का हुआ। जैसे नहर की सिंचाई का मामला है मैं पिछली बार देख रहा था कि इरीगेशन डिपार्टमैंट का एस्टैब्लिशमैंट पर खर्च 64 परसेंट था जो अब करोड़ 94 परसेंट पर पहुंच गया है। कहां तक टेल पर पानी पहुंचेगा। 570 करोड़ रुपया अकेले नहर विभाग के एस्टैब्लिशमैंट पर खर्चा है। इसी तरह से सरकार की पंचायती राज में आस्था होती है। पंचायती राज आया, संविधान बना, डायरैक्टिव प्रिंसिपल डाले गए और महात्मा गांधी की भी यही सोच थी। पंचायती राज का मकसद सत्ता को विकेन्द्रीयकरण करने की होती है ताकि नीचे तक आदमी फैसले करे लेकिन जिस प्रकार से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है उससे सत्ता का केन्द्रीयकरण होता जा रहा है। आज पंचायतों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप वाइंड अप करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : पंचायती राज संस्थाओं में अनुदान राशि 46 करोड़ से घटाकर 18 करोड़ रुपये कर दी है इससे सरकार की नीयत साफ झलकती है कि सरकार का पंचायती राज संस्थाओं में विश्वास नहीं है। दो अहम मुद्दे जो आए हैं जिन पर दलगत भावना से ऊपर उठकर फैसले लिए गए हैं (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, आप जल्दी कर रहे हैं इसलिए मैं थोड़ी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग इस बार मुनाफे में गई है इसमें हमें बड़ी खुशी है लेकिन सरकार का काम लोगों को नौकरी या काम धंधा देना है। जो लोग टैक्सी या मैक्सी कैब चला रहे थे उस पर इस सरकार ने पाबंदी लगा दी कि छह साल बाद उनको इसका लाइसेंस नहीं देंगे। रोडवेज पर भी आप इस तरह की पाबंदी लगा दो कि छह साल बाद बस नहीं चलेगी। लोगों के धंधे बंद हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट में इस तरह मुनाफा दिखाकर क्या होगा ? आम आदमी जिस किसी व्यवसाय में है यदि उसका व्यवसाय बंद हो जाए तो वह क्या करे ?

वित्त मंत्री (प्रो. संपत्त सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, बाकी तो मैं जवाब के समय बता दूँगा लेकिन मैं हुड्डा साहब की इतलाह के लिए यह प्वॉइंट क्लीयर करना चाहता हूँ। जहां मैक्सी कैब की लाइफ सात साल कर दी है वहीं रोडवेज की भी सात साल लाइफ कर दी है और राज्यों में 15-16 साल लाइफ है लेकिन यहां हमने मैक्सी कैब के बराबर 7 साल की कर दी है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, आप बजट एट ए ग्लांस देखें। नौवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है और दसवीं पंचवर्षीय योजना शुरु हो रही है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : आप वाइंड अप करें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, उसमें भी हर चीज में कम किया है चाहे एग्रीकल्चर हो उसमें भी इस साल कम किया है, चाहे पंचायती राज संस्थाओं की बात है, चाहे नहर विभाग की बात है, चाहे शिक्षा में हो या दसवें प्लॉन की बात हो इसमें बजट में कमी की गई है यह कमी चिंता का विषय है। सबसे अहम मुद्दा एस.वाई.एल. का है उस पर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। उसके लिए मुझे आपसे दो मिनट का समय चाहिए। एस.वाई.एल. के बारे में इस हाउस में रैजोल्यूशन पास हुआ है। इसके अलावा कर्ण सिंह दलाल की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि

एस.वाई.एल. के लिए तो हम सब एक हैं ही लेकिन जितना पानी हरियाणा में उपलब्ध है क्या आपने उसके बारे में सोचा है। जो आलरेडी स्कीम हैं जैसे दादूपुर नलवी के बारे में बजट में पैसा रखा या भाखड़ा और यमुना में मेल हो और जहां फालतू पानी हो और जिसको पानी चाहिए उसके लिए क्या कोई प्रावधान किया है ताकि कैरिंग कैपिसिटी बढ़ सके ?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज कन्कल्यूड करें।

प्रो. संपत सिंह : एम.बी.के. आलरेडी लिंक है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : एम.बी.के. और उसकी कैपेसिटी का भी मेरे को मालूम है लेकिन जितना हिस्सा बनता है उसका पूरा हिस्सा दिया जाता है और कोई नहर, चैनल या कैरिंग कैपेसिटी खोदने की सोच रहे हैं, मेरा यह कहना है कि यह सबका अधिकार है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं 42 दिन के बाद चार दिन पानी आता है।

17.00 बजे **श्री उपाध्यक्ष :** हुड्डा साहब आप बैठिये और शशि रंजन परमार बोलेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कन्कल्यूड करने दें।

नगर एवम् ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब चौधर तो करते हैं रोहतक की और बात करते हैं दादूपुर नलवी के पानी की। हुड्डा साहब आप अपने हल्के किलोई और रोहतक के गांवों में जाकर देखें पानी का तीसरा हफ्ता चल रहा है। पिछली बार दो हफते पानी आया था अब की बार तीसरा हफ्ता चल रहा है अब आप यह 42 दिन की बात पता नहीं कहां से उठा लेते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात पूरी तो करने दें।

श्री उपाध्यक्ष : हुड्डा साहब आप बैठिये और अब शशि रंजन परमार बोलेंगे।

श्री शशि परमार (मुंढाल खुर्द) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री श्री सम्पत सिंह जी ने जो वर्ष 2002-2003 का बजट पेश किया है वह बहुत ही शानदार और संतुलित बजट है। उसमें जो 1922.50 करोड़ की जो 4.5 प्रतिशत की इसमें ग्रोथ दिखाई है वह बड़ा सराहनीय है। मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हरियाणा सरकार ने 'सरकार आपके द्वार' प्रोग्राम के माध्यम से विकास करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस बजट में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है और हर हैड को सही छुआ है। उसमें चाहे रोड्ज की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, आज पूरे प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं। जहां पिछली बार 852 करोड़ रुपये प्रथम चरण में विकास करने पर लगाये और इस बार 370 करोड़ रुपये के करीब के काम हरियाणा प्रदेश की सरकार ने करवाये हैं। सिंचाई के बारे में जहां पिछली बार भाखड़ा नहर का वाटर लैवल काफी कम था उसके बावजूद सरकार प्रयासरत रही कि पानी टेल तक पहुंचे। इस कार्य का रिजल्ट है जो ओटू वीयर पर 35 करोड़ रुपये खर्च किये गये। पथराला डैम के लिए 26 करोड़ रुपये खर्च किये गये। एम.आई.टी.सी. डिपार्टमैंट के माध्यम से 50 करोड़ रुपये लगाकर 305 खाले बनवाये हैं। चौधरी बंसीलाल जी के समय में एम.आई.टी.सी. डिपार्टमैंट का भट्ठा बैठ गया था इस सरकार ने उन खालों को बनवाया है। 100-125 खाले 14 करोड़ रुपये की लागत से भी बनाये गये हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हरियाणा प्रदेश में एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी का दिया है जिसमें पंजाब सरकार को निर्देश दिये हैं कि एक साल के अन्दर एस.वाई.एल. नहर को पूरा करके दे। जिससे दक्षिणी हरियाणा को बड़ा फायदा होगा। हरियाणा प्रदेश की सरकार की पैरवी की वजह से और माननीय मुख्य मंत्री जी की पैरवी की वजह से यह मामला सिरे चढ़ा है। विशेषकर हमारे क्षेत्र भिवानी को इसका काफी फायदा होगा। यह सरकार का बड़ा सराहनीय कदम है इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की जनरेशन में भी पिछले साल के मुकाबले 36 परसैंट ग्रोथ इस बार हुई है और लाइन लोसिज भी काफी कम हुए हैं। जो सरकार ने साढ़े 7 हजार ट्रांसफार्मर लगाए हैं वह किसानों की एक बड़ी

[श्री शशि परमार]

डिमांड थी उस डिमांड को भी पूरा किया है। 7700 किलोमीटर की तारें भी बदली गई हैं। हमारे भिवानी जिले के बारे में लोगों में यह बात थी कि बिजली के मामले में यहां क्या हुआ है। यह सामने ही है कि सतनाली गांव में 132 के.वी. के बिजली घर की मुख्य मंत्री महोदय ने आधार शिला रखी थी। बहल में 132 के.वी. का बिजली घर मंजूर किया गया है और भिवानी में 132 के.वी. के बिजली घर की आधार शिला रखी गई है। मेरे अपने गांव में भी 33 के.वी. का बिजली घर सरकार बनाने जा रही है। ये बड़े सराहनीय कदम सरकार के हैं। पिछली सरकारों में लाठी चार्ज और गोलियां चलीं फिर भी बिजली के बिलों की रिकवरी नहीं हुई वहीं अब मुख्य मंत्री के निर्देश से और इनकी गाइडलाइंस से किसानों को समझा बुझा कर हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 800 करोड़ रुपये की बिजली के बिलों की रिकवरी की है और यह बड़ा ही सराहनीय कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह इस सरकार ने 3 परसैंट रिजर्वेशन खिलाड़ियों के लिए सर्विसज में की है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए अम्बाला और गुड़गांव में स्पोर्टस सैन्टर्ज भी डिवैल्प किए जा रहे हैं। अभी पीछे जो हिसार में नैशनल लैवल पर गेम्स हुए हैं उसमें बहुत बड़ी अचीवमैंट सरकार की रही है। ओपन खेल विश्वविद्यालय बनाने का जो फैसला हिसार में लिया गया है वह बहुत सराहनीय कदम है।

श्री उपाध्यक्ष : शशि परमार जी, आप वाइंड अप करें।

श्री शशि परमार : उपाध्यक्ष महोदय, ओलम्पिक में स्वर्ण पदक लाने वाले को एक करोड़ रुपये, सिल्वर पदक लाने वाले को 50 लाख रुपये और 25 लाख रुपये कांस्य पदक लाने वाले को इनाम के रूप में देने की घोषणा इस सरकार द्वारा की गई है जो कि एक सराहनीय कदम है। इस बजट में भी इसको रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हरियाणा प्रदेश में उद्योगों की बात है, इन्फोर्मेशन टैक्नोलोजी को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार काफी प्रयासरत है। शिक्षा के मामले में भी नई शिक्षा नीति बनाई गई है। पहली कक्षा में जहां अंग्रेजी लागू की गई है और पांचवी कक्षा से कम्प्यूटर शिक्षा भी शुरू की गई है इससे विशेष तौर से हमारे देहात के बच्चों की हौसला अफजाई होगी। आई.टी. के मामले में हरियाणा प्रदेश पूरे देश में तीसरे नम्बर पर है इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह से ई.गवर्नैंस सैन्टर यहां चण्डीगढ़ में बनाया गया है, उसमें अधिकारियों को और विधायकों को कम्प्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस सैशन में सभी विधायकों को कम्प्यूटर देने का फैसला लिया गया है इससे बहुत फायदा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में अमन और शान्ति है और इसका रिजल्ट यह है कि पिछले दिनों मुख्य मंत्री महोदय कई देशों की औद्योगिक नीति देखने के लिए बाहर गए थे और मुझ जैसे छोटे वर्कर को भी बाहर जाने का मौका मिला है। काफी इंडस्ट्रीज दिल्ली से उजड़कर यहां हरियाणा में आई है। उद्योगों के मामले में हरियाणा में 7 हजार करोड़ रुपये का निर्यात पिछले साल हुआ है, 3 हजार करोड़ रुपये का निर्यात सोफ्ट वेयर के मामले में हुआ है और गुड़गांव में अर्थ सेन्टर बनाने का इनीशिएटिव लिया गया है। सोफ्ट वेयर को विकसित करने के लिए काफी फैक्ट्रियां लगाई गई हैं। यह एक बड़ा अच्छा और शानदार बजट है इसमें कोई शक नहीं है। यह बजट प्रति व्यक्ति आय 13709 रुपये से बढ़कर 14331 रुपये दर्शाता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था सही दिशा की तरफ अग्रसर है। यह बहुत शानदार बजट माननीय सम्पत सिंह जी ने रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक दो बातें अपने हल्के के बारे में और कहना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : परमार जी आप एक मिनट में वाइंडअप करें। दूसरे सदस्यों ने भी बोलना है।

श्री शशि परमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि मैं अपने हल्के की एक दो बातें कहना चाहूँगा कि वैसे तो पूरे हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेरे हल्के में बिजली घर भी मंजूर किए हैं तथा सिंचाई के रजवाहे भी बनाये जा रहे हैं। जैसे बामला माईनर, ढाणी हरि सिंह माईनर और मुण्डाल माईनर। ये माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मंजूर कर दिये हैं, जिससे कम से कम 15-20 हजार एकड़

भूमि सिंचित होगी। इनके अतिरिक्त मैं दो-तीन दूसरे रजबाहों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि न्यू बड़ेसरा माईनर और जटाई माईनर भी बनवाये जायें। इन रजबाहों को बनाने बारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा भी की थी तथा इनको बनाने में जो आब्जैक्शन थे उनको भी हमने दूर करवाया है इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ये रजबाहे जल्दी बनाये जायें। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मेरे हल्के में सड़कें भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी बनवाई हैं। जो सड़कें पिछले 20-25 सालों से नहीं बनी थी उनको हमारे मुख्य मंत्री जी ने बनवाया है। जैसे चांग से खरक, भाथबास से बामला, चांग से मिताथल, जटाई से सुखपुरा और मढ़ाणा से तिगड़ाना आदि सड़कें मेरे हल्के में बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि दो-तीन सड़कें जो टूट गई हैं वे बनानी बहुत जरूरी है क्योंकि उन सड़कों पर आम आदमी का और किसान का बहुत वास्ता पड़ता है। वे रोड्ज़ हैं सांवड़ से बड़ाला और सूई से खरकड़ी। माननीय मुख्य मंत्री कृपा करके ये सड़कें भी जल्दी बनवायें। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि परचेज सैंटर अधिक से अधिक बनाये जायेंगे ताकि किसान को अपनी फसल 6 से 8 कि.मी. से ज्यादा दूर बेचने न जाना पड़े। इस बारे में मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि चांग, बौंद और धनाना में परचेज सैंटर इसी सीजन में बनाये जायें क्योंकि यहां के किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए भिवानी और महम जाना पड़ता है और ये दोनों ही परचेज सैंटर इन गांवों से लगभग 15 कि.मी. दूर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृषि मंत्री जी आप परमार साहब के इन गांवों के नाम नोट कर लें और वहां पर परचेज सैंटर बनाने बारे विचार करें। परमार जी, अब आप वाईंड अप करें। आपकी बात कृषि मंत्री जी ने नोट कर ली है।

श्री शशि परमार : उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और माननीय सम्पत सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अच्छा और संतुलित बजट पेश किया तथा मैं बजट का समर्थन करता हूं।

चौधरी जगजीत सिंह (दादरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय वित्त मंत्री प्रो. सम्पत सिंह जी ने 13 मार्च को सदन में जो बजट पेश किया उस पर दो-तीन दिन से चर्चा हो रही है। बहुत से साथियों ने कहा कि यह बड़ा अच्छा, प्रदेश को सही दिशा में ले जाने वाला विकासशील बजट है। लेकिन आंकड़ों को देखा जाये तो पता लगता है कि यह बजट मात्र आंकड़ों का ही खेल साबित होता है। यह बजट पिछले दो-तीन सालों के बजट से 30-35 प्रतिशत कम है। इसके अंदर मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, सड़कें और सिंचाई के लिए मात्र 42.13 प्रतिशत पैसा रखा गया है जबकि विगत वर्ष इन कार्यों के लिए 54.6 प्रतिशत पैसा रखा गया था और उससे पिछले वर्ष यानि 2000-2001 के बजट में इन कार्यों के लिए 64.5 प्रतिशत पैसा रखा गया था। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार अपने आपको आम आदमी और किसान हितैषी सरकार बताती है जबकि किसान और आम आदमी इसी हैड में कवर हो जाते हैं जो कि 50 प्रतिशत से कम है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो पिछले तीन वर्ष से बजट पेश करना शुरू किया है तब से इनकी वार्षिक योजनाओं के आकार के पैसे में भी निरंतर कमी होती जा रही है। वर्ष 2000-2001 के बजट में 2530 करोड़ रुपये, वर्ष 2001-2002 के लिए 2150 करोड़ रुपये और इस वर्ष के बजट में 1900 करोड़ के लगभग का प्रावधान वार्षिक योजनाओं के लिए किया गया है। इसमें केन्द्रीय सहायता का जो आंकड़ा दिखाया गया है वह 23.7 परसेंट है जो 456.06 करोड़ रुपये बनता है। मैं समझता हूं कि केन्द्र के साथ मौजूदा हरियाणा सरकार के उतार-चढ़ाव वाले रिश्तों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि 456.06 करोड़ रुपये की जो राशि दिखाई है वह ये पूरी तरह से उनसे ले लेंगे और बजट के अनुसार ही खर्चा कर देंगे या प्रदेश के हितों के लिए ये कुछ कर पाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा बजट के अन्दर गांवों के विकास के लिए पिछले बजट के मुताबिक बहुत कम राशि ग्रामीण विकास के हैड में दिखाई है, यानि यह 67.81 करोड़ रुपये दिखाई गई है जबकि शहरों के लिए कई बार ये दूसरे प्रस्ताव भी

[चौधरी जगजीत सिंह]

पास करके पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। इसके अलावा शहरों के अन्दर पड़ी जमीन को बेच कर या गृहकर लगा करके भी बहुत सी स्कीमों के माध्यम से शहरों के लिए पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। सरकार समय समय पर ऐसा करती रहती है। आज के दिन तो बजट में कोई टैक्स दिखाई नहीं देता लेकिन बाद में पूरा साल भर किसी न किसी प्रकार के नये टैक्स लगते रहेंगे और कोई न कोई नई स्कीम लागू करके पैसा लेते रहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, गांवों के अन्दर पिछले साल की निस्बत इस साल 140.29 करोड़ रुपये दिखाए गए हैं जबकि पिछले साल 67.7 करोड़ रुपये इस बजट के आर्थिक सर्वेक्षण बुक में दिखाए गये थे। इसी प्रकार से जो कृषि से सम्बन्धी कार्यों के बारे में बताया है उनमें भी इन सब हैडों में कमी आई है। गांवों के लोगों की कहलाने वाली सरकार का यह हाल है जो इस बजट के पेश होने पर और इनकी पोल खुलने पर पता लगता है। अब इस वक्त माननीय वित्त मंत्री जी सदन में बैठे हुए नहीं हैं। हमारे बहुत से माननीय साथियों ने बजट पर जो सुझाव दिए हैं उन के बारे इनको विचार करना चाहिए। वहां पर पूर्व वित्त मंत्री जी श्री मांगे राम गुप्ता जी बैठे हैं, इन्होंने भी बजट के बारे में काफी अच्छे सुझाव सरकार के सामने रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सांगवान साहब, आप भी अपने सुझाव दें। अब आपके पास सुझाव देने का समय है।

चौधरी जगजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी को मेरा इस बारे में अब भी यही कहना है कि जो हमारे सीनियर साथी हैं उनको वे बुलाकर उनके सुझाव इस बजट के लिए ले लें तो बहुत अच्छी बात होगी जिससे इस बजट को अच्छा बनाया जा सकता है। मुझे पता है कि बाद में अफरा-तफरी मचेगी और फिर आप मुझे बैठने के लिए कहोगे। इसलिए मैं पहले अपने हल्के के संबंध में 2-4 बातें कहना चाहूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन क्योंकि आप बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं और मुझे बोलने के लिए भी आपने सिर्फ 6 मिनट का ही समय दिया है, इसलिए मैं अपनी बात जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में बहुत सी ऐसी बातें थी जिनको वित्त मंत्री जी ने छुआ तक नहीं। खासकर मेरे हल्के दादरी को तो बजट में छुआ ही नहीं गया। मुख्य मंत्री जी ने भी दादरी को जिला बनाये जाने बारे कोई सार्थक जवाब नहीं दिया। इन्होंने दादरी को जिला बनाने की बात नहीं कही। (विघ्न) मैं दादरी को जिला बनाने की बात कर रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि यह सरकार इस बजट में दादरी को जिला बनाने के लिए कुछ प्रावधान करती तो इससे बहुत से लोगों को राहत मिलती। (विघ्न) दादरी जिला बनाये जाने पर वहां पर बहुत से विकास कार्य भी होते जिससे उस क्षेत्र का विकास होता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दादरी शहर बहुत बड़ा शहर है। आज उस शहर के अन्दर सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। खास कर जो गरीब बस्तियां हैं, जैसे रविदास बस्ती, बाल्मीकि बस्ती, धानक बस्ती आदि बस्तियों में सीवरेज की बहुत भारी समस्या है। इसी प्रकार से प्रेमनगर, दयानन्द नगर, बिहार नगर आदि जगहों पर भी यह समस्या बनी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, वार्ड नं. 1 एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सीवरेज की निकासी की बहुत अधिक आवश्यकता है। आज के दिन दादरी शहर में बहुत थोड़ी जगह में सीवरेज डला हुआ है। जब इस शहर में यह सीवरेज डाला गया था उस वक्त दादरी शहर की आबादी तकरीबन 35 हजार थी जो आज बढ़ कर 70 हजार से भी ऊपर है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार को आपके माध्यम से अनुरोध है कि दादरी शहर में सीवरेज की बहुत अधिक आवश्यकता को देखते हुए वहां पर सरकार सीवरेज डालने की तुरन्त व्यवस्था करे ताकि वहां के लोगों को कुछ राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, दादरी शहर के अन्दर से जो रेलवे लाइन जयपुर-हिसार जाती है वह शहर के बीचों बीच है। आधा शहर लाइन के उस पार है और आधा शहर लाईन के इस पार है। इस बारे में मेरा कहना है कि रेलवे लाइन पर जो रोड है वहां से राजस्थान, नारनौल, दिल्ली, पिलानी और रोहतक जाने वाले वाहन जाते हैं, इस सड़क पर रेलवे लाइन बीच में पड़ने पर बहुत भारी जाम रहता है। अच्छा होता कि इस बजट के अन्दर वित्त मंत्री जी वहां पर बाई-पास बनाये जाने की बात करते और ओवर ब्रिज बनाने की बात भी करते। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस

बजट में बाई पास और ओवर ब्रिज की बात होती तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुविधा होती।

श्री उपाध्यक्ष : सांगवान साहब, वाईंड अप कीजिए।

चौ. जगजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है। इस बारे में मैंने सी.पी.एस. साहब से सवाल भी किये थे। उन्होंने यहां हाउस में कहा था कि टेल पर होने की वजह से कई जल घर ऐसे हैं जिन पर पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या है। जहां पर पानी आता भी है तो वह साफ सुथरा नहीं होता। इसी वजह से दादरी शहर में खसरे का रोग और डायरिया रोग जैसी बीमारियां घर-घर में फैली हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन दादरी के अन्दर हर घर में 1-1 व 2-2 आदमी बीमार हैं और ये सब खराब पानी की वजह से ही बीमार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप वाइंड अप कीजिए।

चौ. जगजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया। आपका धन्यवाद करते हुए मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि मैंने अपने हल्के से संबंधित जो 4-5 बातें कही हैं उनका समाधान वे इस बजट में शामिल करेंगे। धन्यवाद।

श्रीमती अनिता यादव (साल्हावास) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बजट पर चर्चा करने में मुझे शामिल किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करती हूं तथा जो बात मैं कहने जा रही हूं उसको सुनने के लिए भी मैं आपसे अनुरोध करती हूं। सभी माननीय साथियों ने अपने-अपने क्षेत्र की बात कही, बजट की बात इस सदन में कही। प्रोफैसर सम्पत सिंह जी ने 13 मार्च को हाउस में जो बजट रखा है उस विषय में मैं भी अपनी बात कहना चाहती हूं। वर्ष 2002-2003 के बजट में 202.20 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया गया है। पिछले बजट अनुमान से अगर हम आकलन करें तो यह घाटा लगभग 400 करोड़ रुपये तक पहुंचेगा क्योंकि जब 2001-2002 का बजट पेश किया गया था तब भी प्रोफैसर साहब ने कोई कर नहीं लगाया था लेकिन धीरे-धीरे करके इन्होंने इतने भारी टैक्स लगा दिये कि इन्होंने जीने मरने तक के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अगर हस्पताल में जाएं तो वहां पर टैक्स लगा दिया (विघ्न) हलवाइयों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। यहां तक कि हर बात पर टैक्स लगा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझती हूं कि यह नेचुरल है कि ज्यों ज्यों साल शुरू होगा त्यों-त्यों दोबारा इस बजट का ऐसा पुलिन्दा बन्धेगा जैसा पिछले साल के बजट का पुलिन्दा बांधा था। इस साल भी जो घाटा दिखाया गया है वह कहीं 400-500 करोड़ तक न पंहुच जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन लोगों से अनुरोध करती हूँ कि जब जब भी इन्होंने बजट को पेश किया है उसके बाद इन्होंने करों के ऊपर कर लगा कर जनता का जीना दूभर किया है। हम लोगों ने धरने दिए और प्रदर्शन भी किए लेकिन सरकार अपने कारनामों से बाज नहीं आई। पहले बजट में सरकार ने 2530 करोड़ रुपये की प्लानिंग रखी थी लेकिन इसमें से 1830 करोड़ रुपये के संसाधन ही सरकार जुटा पाई और बाकी जो पैसा था जिसकी प्लानिंग थी उसमें बचा नहीं क्योंकि सरकार ने हीनपणा बरता। इतना पैसा रखने के बावजूद भी 1830 करोड़ रुपये ही सरकार जुटा पाई। इसी प्रकार से दूसरे बजट में भी 2150 करोड़ रुपये की प्लानिंग थी लेकिन सरकार 1838.68 करोड़ रुपये के संसाधन ही जुटा पाई। अब की बार सरकार ने 1922.50 करोड़ रुपये की प्लानिंग की और उसके बावजूद 1466.44 करोड़ रुपये जो आपने प्रावधान में रखा है मैं समझती हूँ कि यह राशि हरियाणा के विकास के लिए बहुत कम है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ कन्जूसी करनी चाहिए। हर बात में तर्क वितर्क के साथ साथ लाभ हानि को भी देखना चाहिए लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि बजट में तो कंजूसी चलती रहे और हरियाणा के किसानों के हक कटते रहें और हरियाणा के लोगों की अनदेखी होती रहे और सारा पैसा यू.पी. में चला जाए। यह बात हमारे लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। (विघ्न एवं शोर)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : डिप्टी स्पीकर सर, ये लोग जब भी कोई बात कहते हैं तो सारा दोष हमारा निकालते हैं और ये कहते हैं कि पहले जितने भी ओले पड़े थारे वक्त में पड़ गए, सूखा थारे वक्त में पड़ गया, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, आप मुझे इजाजत दें मैं एक मिनट में ही अपनी बात पूरी कर लूंगा। गांव में एक बूढ़ा मर गया और गांव के लोग सांत्वना देने के लिए उसकी बुढ़िया के पास चले गये और कहने लगे ताई कोई बात नहीं यह तो सब के साथ लगा हुआ है, कोई बात नहीं तू दिल समझा। उस बुढ़िया से नम्बरदार और सरपंच कहने लगे यह आना जाना तो लगा ही रहता है तू दिल को समझा। वह बुढ़िया नम्बरदार से कहने लगी थारा ताऊ जब चालया करता तो यह जो रेडियो धरा है इस पर वह खबरें सुना करता था और जब यह रेडियो देखती हूँ तो उसकी याद आ जाती है। वह नम्बरदार कहने लगा कि यह रेडियो मैं घर ले जाऊंगा ताई तू ज्यादा हरख न करै और तू इसकी तरफ न देख्या कर। (विघ्न) अनिता जी, आपको पता नहीं है लेकिन मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, आपको पता नहीं है इस बात में बहुत फर्क है, मैं तो किस की कह रहा हूँ और आप किस की ढूंढ रही हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, वह बुढ़िया कहने लगी जब मैं यह रेडियो देखती हूं तो उसकी याद आने लगती है। नम्बरदार ने कहा यह रेडियो मैं घर ले जाऊंगा और खबर मैं सुन लिया करूंगा तू इसकी चिन्ता न किया कर। बुढ़िया कहने लगी थारा ताऊ घोड़ी भी बांध गया था वह घोड़ी पर आया जाया करता था घोड़ी देख कर भी उसकी याद आ जाया करे। उपाध्यक्ष महोदय, तो बुढ़िया कहने लगी कि यह बड़ा सा कोट तेरे ताऊ का है यह भी वो पहना करता था तो नम्बरदार कहने लगा कि यह भी मैं पहन लिया करूंगा। इसके बाद बुढ़िया कहने लगी कि नम्बरदार तेरे ताऊ ने 20 हजार रुपए का कर्ज बैंक से लिया था वे भी बैंक को देने हैं तो नम्बरदार कहने लगा कि यह सारा गांव क्या यूं ही यहां बैठा है, अरे भई तुम भी हां भर लो। उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बड़े काम किए हैं और इनका यमुनानगर के इलैक्शन में क्या हुआ। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि

इन्हें साहिल हो गई मंजिल, यह हवा का रुख बदल गये।
ये हाथ-हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। अनिता जी आप बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल मात्र एक लाइन में बात कहना चाहता हूँ। यहां पर केवल चौटाला साहब का मकसद बताना चाहता हूँ।

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है,
मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए,
हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
है बहुत अंधियारा सूरज निकलना चाहिए,
जिस तरह भी हो यह मौसम बदलना चाहिए,
जो चेहरा बदलते हैं नकाबों की तरह,
अब जनाजा धूम से निकलना चाहिए।

चौ. भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोल रहे थे ? ये यूं ही बीच में बोलने लग जाते हैं आप इस बारे में बताएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : भजन लाल जी, मैंने इनको परमिशन दी थी। आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) अनिता जी बोलिए।

श्रीमती अनिता यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष के बजट में बिजली के लिए 487 करोड़

रुपए का प्रावधान था और अब कि बार इन्होंने बिजली के लिए केवल 166.56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है मैं समझती हूँ कि यह बहुत ही कम है। बिजली का मामला बहुत गम्भीर है। बिजली न मिलने की वजह से किसानों की फसल सूख जाती है। हरियाणा में यह पता नहीं रहता कि कब बिजली चली जाएगी। हमेशा यही रहता है कि बिजली अब गई अब गई। जब बिजली की ज्यादा जरूरत होती है उस समय बिजली चली जाती है। खास करके शाम के टाइम जब बच्चों ने पढ़ना होता है या औरतें रोटी बनाने लगती हैं तो बिजली चली जाती है। यह जो राशि बिजली के लिए बजट में रखी गई है यह बहुत कम है मैंने इस बारे में सुबह भी जिक्र किया था। उपाध्यक्ष महोदय, कोसली पावर हाउस स्टेशन में हमारा एक मोहड़ फीडर है वह ओवर लोडिड है। 29-12-2001को मुख्य मंत्री जी हमारे क्षेत्र में आए थे और उन्होंने उस बारे में अफसरों को कार्यवाही करने के लिए आर्डर दिया था। उस समय जो एक्सीयन साहब थे उन्होंने भी कहा था कि हम आपकी शिकायत दो दिन में पूरी कर देंगे। लेकिन आज तक वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मुझे पता नहीं कि मुख्य मंत्री जी की चलती है या आफिसर्ज की चलती है। आज उसको 2 महीने की बजाए 4 महीने हो गए हैं लेकिन आज तक किसी आफिसर ने वहां पर जाकर नहीं देखा है कि वहां पर मुख्य मंत्री जी ने उनको क्या आर्डर्ज दिए थे और वे इम्पलीमैंट हुए या नहीं। इसी तरह से मेरे क्षेत्र में बिजली की तारें भी ढीली पड़ी हुई हैं उनको भी खींचने के लिए कुछ राशि का प्रावधान किया जाए। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिए पिछले साल 367 करोड़ रुपए बजट में रखे गए थे लेकिन इस बार सिर्फ 300 करोड़ रुपए ही रखे हैं। मैं समझती हूं कि सिंचाई के लिए यह पैसा बहुत कम है। आज सभी जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां के 85 प्रतिशत लोग खेती करते हैं और उस पर ही निर्भर करते हैं। उनको बिजली पानी पूरी नहीं मिलने की वजह से उनकी खेती ठीक तरह से नहीं हो पाती है जिस वजह से उनको उचित पैसा नहीं मिल पाता है जिससे वे अपने बच्चों को सही ऐजुकेशन नहीं दे पाते हैं। मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि इसे ठीक करवाएं। जैसे कि मंत्री जी ने और मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि सिंचाई के लिए एस.वाई.एल. का पानी आ रहा है। मुझे नहीं पता कि यह पानी कब आएगा और कब नहीं आएगा। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से यह डिमांड करती हूँ कि हरियाणा में जो टोटल पानी 13 हजार क्यूसिक है उसमें से दक्षिणी हरियाणा को केवल 6 हजार क्यूसिक पानी ही मिल रहा है। दक्षिणी हरियाणा में महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद जिले आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अनिता जी, आप अपनी फिगर्ज चैक कर लें। अगर इतना पानी मिले तब कोई बात ही नहीं है।

श्रीमती अनिता यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि तीन जिलों में तो ज्यादा पानी की वजह से सेम आ रही है जबकि दक्षिणी हरियाणा में पानी न मिलने की वजह से सूखा पड़ रहा है। जब तक एस.वाई.एल. का पानी हरियाणा में नहीं आ जाता तब तक जो भी पानी हरियाणा में है, उसका उचित बंटवारा किया जाए ताकि दक्षिणी हरियाणा को पानी मिल सके और वे भी खुशहाल हो सकें तथा अपने बच्चों का जीवन स्तर सुधार सकें। यह मेरी सरकार से डिमांड है। इसी तरह से पीने के पानी की बात भी यहां पर आयी कि सरकार का 70 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति देने का प्रावधान है। जब सी.एम. साहब मातनहेल गांव गए थे तो उन्होंने वहां पर वाटर स्कीम्स का उद्‌घाटन किया था। लेकिन अभी भी वहां पर दो तीन वाटर स्कीम्ज अधूरी पड़ी हैं। अब तो गर्मियां आ चुकी हैं इसलिए मैं समझती हूँ कि अगर अभी से इस के लिए साधन नहीं जुटाए गए या ये स्कीम्ज पूरी नहीं की गयी तो जिस तरह से आज वहां पर दो रुपये प्रति मटका पानी लेना पड़ रहा है उसी तरह से बाद में भी यही हालत रहेगी। चाहे रेलवे स्टेशन कोसली की बात हो या मातनहेल की बात हो, सब जगह यही हाल है आप चाहें तो इस बारे में सर्वे करवा लें। हमें पता नहीं चलता कि सरकार के फंड्ज कहां जाते हैं। हो सकता है कि ये फंड्ज सिरसा में जाते हों, रोड़ी में जाते हों या फिर यू.पी. के इलैक्शन में चले गए हों। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि वहां पर पीने का पानी मिलना ही चाहिए। (विघ्न) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सरसों की फसल के नुक्सान का या ओलावृष्टि

[श्री अनिता यादव]

का भी बार बार जिक्र आया है। आप इस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आपका संबंध भी उस इलाके से है। मैं कहना चाहूँगी कि हमारे इलाके में पचास परसैंट तक ओले पड़े हैं। आप आज का दैनिक जागरण अखबार देखें। उसमें दिखाया गया है कि एक गांव का किसान अपनी सरसों की खड़ी फसल पर अपना ट्रैक्टर चला रहा है। हमारे एक सदस्य के पास यह पेपर है आप चाहें तो हम आपको यह दिखा सकते हैं। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि वहां के किसान को इसका मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसी तरह से अब मैं बसिज के बारे में कहना चाहूँगी कि जहां पर आपने इन बसिज के लिए इतने पैसे का प्रावधान रखा है वहीं आप इसको थोड़ा और बढ़ा दें ताकि 15 बसिज और ज्यादा खरीद लें क्योंकि हमारे क्षेत्र में रिवाड़ी से झज्जर या झज्जर से कोसली के लिए बसिज बहुत ही कम हैं। बसें न होने की वजह से यात्री घण्टों खड़े रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अनिता जी, आप बैठें।

श्रीमती अनिता यादव : सर, अब मैं नाहड़ महाविद्यालय के बारे में कहना चाहूँगी वहां पर भी बसिज का प्रावधान नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहूँगी कि वहां पर बसिज का जरूर प्रबन्ध करवाया जाए। विशेष तौर पर कॉलेज के समय पर बसें जरूर चलनी चाहिएं। उपाध्यक्ष महोदय, अंत मे मैं इस बजट का विरोध करती हुई अपनी बात समाप्त करती हूं। (विघ्न)

श्री भागी राम (ऐलनाबाद, अनुसूचित जाति) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए धन्यवाद। प्रो. सम्पत सिंह जी ने जो बजट पेश किया है में उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे तो जब से हरियाणा बना है और हरियाणा का जो भी वित्त मंत्री हुआ है वह अपना बजट पेश करता है और रूलिंग पार्टी उसका समर्थन करती है जबकि अपोजीशन पार्टी उसका विरोध करती है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा था जिस दिन प्रोफैसर साहब बजट पेश कर रहे थे, मैं भी देख रहा था उस समय हमारे विरोधी पक्ष के भाई एक दूसरे की तरफ इशारे कर रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि वे इस ताक में थे कि कहां कोई ऐसी बात आए जहां हम शोर मचाएं या वाकआउट करें या कोई और बात करें। मुझे बड़ी खुशी है कि इनको ऐसा कोई मौका नहीं मिला। मेरा ख्याल है कि यह पहला बजट सैशन है जिसमें हमारे विपक्ष के साथियों को बजट का विरोध करने के लिए कोई बात नहीं मिली और वाकआउट नहीं हुआ। (विघ्न) वैसे इस बजट में चाहे कृषि की बात हो, बार बार हमारे साथी इसकी तारीफ कर रहे थे। चाहे कांग्रेस के साथी थे, चाहे बी.जे.पी. के थे या इंडीपैंडैंट्स थे सभी ने यही कहा कि मैं बिजली के लिए धन्यवाद करता हूं। किसी ने कहा कि मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का धन्यवाद करता हूं। कोई किसी का धन्यवाद कर रहा था कोई किसी का कर रहा था। कोई इलियास जी का धन्यवाद कर रहा था कि इनका इलैक्शन कामयाब रहा। मेरे कहने का मतलब यह है कि चाहे जिस इशू को उठाएं, जिस महकमे को लें चाहे बिजली के महकमे को लें चाहे पानी के महकमे को लें, चाहे पब्लिक हैल्थ की बात हो या हैल्थ की बात हो इस बजट में सारे महकमों के काम से अच्छी झलक आती है। (विघ्न) जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार बनी है तब से इतने अच्छे काम हो रहे हैं। जब भी इस परिवार को राज करने का मौका मिला, चाहे 1977 में चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री बने, चाहे 1987 में दोबारा उनकी सरकार बनी या चाहे चौटाला साहब मुख्य मंत्री बने, इन्होंने ऐसे ही काम किए हैं। कहीं सड़कें बना दी, कहीं खाल बना दिए, कहीं गलियां बना दी, कहीं नालियां बना दीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मांगे राम जी, आप बैठे बैठे रनिंग कमैन्ट्री न करें। अगर आप ऐसे करेंगे तो भागी राम जी को भी मुकाबला करना आता है।

श्री भागी राम : चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जब भी सरकार आई है उन्होंने ऐसे काम किए जो

सारे हरियाणा प्रदेश के अंदर लागु हुए हैं। हर गांव में काम हुए, चाहे वह चौधरी भजन लाल जी का हल्का हो या चौधरी बंसी लाल जी का हलका हो। चौधरी भजन लाल या बंसी लाल जी की तरह नहीं किया। जब बात चलती है तो यही कहा जाता है कि चौधरी बंसी लाल के मुख्य मंत्री रहते उन्होंने तोशाम को चमका दिया और चौधरी भजन लाल के रहते उन्होंने मंडी आदमपुर को चमका दिया। आज हरियाणा के किसी भी गांव में चले जाएं टोटल 90 के 90 हल्कों में काम होते नजर आएंगे। कहीं धर्मशाला बन रही है, कहीं चौपाल बन रही है, कहीं सड़क बन रही है और कहीं गलियां बन रही हैं। हर गांव में कोई न कोई काम हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से लेकर आज तक जितने भी हरियाणा के मुख्य मंत्री रहे हैं चाहे वे चौधरी भजनलाल जी हों, चाहे चौधरी बंसी लाल जी हों, चाहे पं. भगवत दयाल जी हों, चाहे श्री बनारसीदास गुप्ता जी हों, जितने भी मुख्य मंत्री बने हैं, उन सभी मुख्य मंत्रियों ने इतने सालों में इतने ज्यादा काम नहीं किये हैं जितने इन पिछले दो सालों में चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी के समय में किये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज कोई कहता है कि ये खान दे दी वो खान दे दी। चौधरी भजनलाल जी ने अपने समय में अपने रिश्तेदारों को खानें दी थी और चौधरी बंसीलाल जी ने भी अपने रिश्तेदारों को खानें दी थी लेकिन आज इनको इस बात का दर्द होता है। उनके समय में तो ऐसे ही दी जाती थी लेकिन आज खानों को ऑक्शन पर दिया जा रहा है नीलामी करके दिया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, चाहे 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम चौधरी देवीलाल जी ने शुरू किया था। चौधरी देवीलाल जी ने ही ट्रैक्टर का गड्डा बनाने का काम किया था। गरीबों और हरिजनों के लिए साइकिल और रेडियो का टैक्स माफ किया था। गरीबों के लिए काम के बदले अनाज स्कीम को शुरू किया था। बेरोजगारों के लिए इंटरव्यू में आने जाने के लिए फ्री पास देने का काम, बेकारी भत्ता, बूढ़ों के लिए पैंशन और विधवा पैंशन, आदि अनेकों काम किये जो कि आज भी मिसाल बने हुये हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब आप अपनी सीट पर बैठिये। वरना मांगेराम जी फिर कुछ बोलेंगे।

श्री भागी राम : उपाध्यक्ष महोदय, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी हरिजनों के बारे में कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हरिजनों के लिए यह किया वह किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक हरिजन हूं और एक हरिजन के दुख दर्द का एक हरिजन को ही पता होता है। चौधरी भजनलाल जी को हरिजन के बारे में क्या पता है। वे तो वह समय भी भूल गये जब ओढ़नी बेचा करते थे आज उनको क्या पता कि गरीब आदमी भूख से भी मर सकता है। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा था कि आज जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने गरीब हरिजनों की कन्याओं के विवाह पर 5100/- रुपये कन्यादान के रूप में देने का काम किया है वह बहुत सराहनीय है। आज अगर कोई एक रुपया भी किसी की लड़की की शादी में कन्यादान देता है तो वह साल भर उसका अहसान जताता है कि मैंने तेरी छोरी की शादी में कन्यादान डाला था तो तू मेरे को काम पर क्यों नहीं बुलाता। आज 5100/- रुपये कन्यादान देने का काम जो माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने किया है वह बहुत बड़ा काम है। यह हरिजन के लिए बहुत बड़ी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा जो घुमन्तु परिवार हैं उनके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाया करते थे लेकिन सरकार ने गरीब हरिजन के बच्चे को एक रुपया रोज स्कूल जाने पर देने का काम किया है। उधर गरीब के बच्चे को एक रुपया का लालच होने से गरीब के बेटा बेटी भी अब स्कूल जाने लगे हैं। पहली सरकार क्या किया करती थी जब पहला चुनाव हुआ तो कहते थे कि फलां जगह पर जमीन बांट देंगे। दूसरी बार चुनाव हुये तो कहते थे कि गरीबी दूर करेंगे, तीसरी बार चुनाव हुये तो कहा कि प्लॉट काट कर देंगे और चौथी बार चुनाव हुये तो कहा कि तुम्हें कर्जा दे देंगे। चाहे भैंस का कर्जा हो, चाहे भेड़ का कर्जा हो, चाहे बकरी का कर्जा हो, चाहे मकान बनाने का कर्जा हो। आज हरिजन की हालत यह हो गई है कि वह कर्जा गरीब हरिजन लौटा नहीं सका और आज उस कर्जे का पैसा बढ़कर लाखों रुपये हो गया है और वे बैठे थारे जी न रोन लाग रहे हैं। चौटाला साहब ने हरिजनों के लिए इतना कुछ किया है तभी तो हरियाणा के हरिजनों ने भी कन्धे से कन्धे मिलाकर चौटाला साहब का साथ दिया है।

[श्री भागी राम]

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी असैम्बली में 17 हरिजन एम.एल.एज. हैं और 17 में से साढ़े 16 हमारे साथ हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं रामकिशन फौजी से माफी चाहता हूं ये भी हमारे साथ हैं यानि अब 17 के 17 एम.एल.एज. चौटाला साहब के साथ हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें कि कांग्रेस हरिजनों की हितैषी होती तो आज इनके पास कम से कम एक एम.एल.ए. हरिजन जरूर होता। ये 20 के 20 पैसे वाले हैं।

श्री राम किशन फौजी : उपाध्यक्ष महोदय, जो कांग्रेस की सरकार ने रिजर्वेशन में ए और बी क्लास बना रखी थी उसका खामियाजा भी कांग्रेस भुगत रही है और उसको भुगतना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह : अब तो पूरा सबूत आ गया है कि साढ़े 16 नहीं बल्कि 17 के 17 एम.एल.एज. हमारे साथ हैं।

श्री भागी राम : उपाध्यक्ष महोदय, फौजी ने जो बात कही ठीक कही है वाकई में ये इनकी पुरानी नीति थी कि डिवाइड एण्ड रूल यानि फूट डालो और राज करो। इनकी संख्या चाहे आज घटकर 20 हो गई हो या घटकर एक भी रह जाए तो भी इनकी डिवाइड एण्ड रूल वाली आदत जाएगी नहीं जब तक कि इसको दफना न दें। जब हरिजन सियाना हो गया, कांग्रेस से किनारा कर गया और कांग्रेस को वोट देने से मना कर गया तो इन्होंने हरिजन को हरिजन से और बैकवर्ड को बैकवर्ड से लड़वा दिया। मुझे एक बात याद आ गई। एक बुढ़िया थी उसका एक लड़का था। एक दिन लड़का मां से कहने लगा कि मां तू ये चोरी करना छोड़ दे क्योंकि सारा गांव मुझ पर यह कहकर हंसता है कि इसकी मां चोर है तो उसकी मां बोली बेटा क्या मैं ये चोरी करना छोड़ दूं ? तो बेटे ने कहा हाँ। मां ने कहा ठीक है मैंने चोरी करना छोड़ दिया है। बेटे ने पूछा तो अब मैं पंचायत में जाकर बैठ जाऊं ? मां ने कहा हाँ। जब उस लड़के की शादी हुई तो खाने पीने के समय बुढ़िया ने जूतियां एक जगह से उठाकर इधर रख दी और इधर से उठाकर उधर रख दी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकिशन फौजी : उपाध्यक्ष महोदय, ये बजट पर नहीं बोल रहे हैं ये दफनाना जैसे गलत शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं यह ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामकिशन जी, आप मेरे पुराने दोस्त हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिना परमीशन के बोलें, इसलिए आप बैठें।

श्री भागी राम : उपाध्यक्ष महोदय, जब लोग खाना खाने के बाद चलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी जूती नहीं है तो लड़के ने अपनी मां से कहा कि मां तूने अपनी चोरी करने की आदत नहीं छोड़ी तो मां ने कहा कि चोर चोरी करना छोड़े पर हेरा फेरी न छोड़े क्योंकि वह उसके खून में रच जाती है। इसलिए कांग्रेस के सदस्य जो अपनी आदत से मजबूर है वे उस आदत को नहीं छोड़ सकते। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक दो सुझाव देना चाहूँगा। एक तो जो आर.एम.पी. डाक्टर्ज की रजिस्ट्रेशन 1974 से बंद कर रखी है उसको शुरू किया जाए। इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार पांच हजार या दस हजार रुपये फीस रख दे लेकिन इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इससे सरकार को आमदनी भी होगी और नुकसान कुछ नहीं होगा। आर.एम.पी. डाक्टर्ज की रजिस्ट्रेशन से सरकार को पैसा तो मिलेगा ही साथ ही गांवों के लोगों को सुविधा भी होगी। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा सुझाव दफा 326 के बारे में देना चाहूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, किसी के ऊपर दफा 326 लगवाना बहुत आसान है। क्योंकि यदि कोई आदमी थाने में जाकर कहे कि फलाना आदमी ने गंडासे से उसकी उंगली काट दी और वह इस बारे में डाक्टर से सर्टीफिकेट ले आये तो इस तरह से छोटी सी उंगली कटने से दफा 326 लग सकती है या कभी कोई आदमी कह देता है कि उसका दांत तोड़ दिया गया इस तरह भी दफा 326 लगा दी जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत से मामलों में डाक्टर से झूठे सर्टीफिकेट बनवाकर दफा 326 का केस बनवा देते हैं इसलिए इस तरह के केसों में पूरी इन्क्वायरी करने के

बाद ही दफा 326 लगाई जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह यदि ट्रक और जीप में टक्कर होती है तो ट्रक वाले की गलती मानी जाती है, जीप और मोटर साइकिल की टक्कर होती है तो जीप वाले की गलती मानी जाती है और मोटर साइकिल और साइकिल वाले की टक्कर होती है तो मोटर साइकिल वाले की गलती मानी जाती है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि बड़े व्हिकल वाले की ही गलती हो। क्योंकि कई बार छोटे व्हिकल वाला अचानक बीच में आ जाता है और केस बड़े व्हिकल वाले पर बन जाता है। हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा समय और दिया जाये उसके बाद मैं वाइंडअप कर दूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय चौटाला साहब के हरिजन लोग हितैषी हैं और चौटाला साहब हरिजनों के हितैषी हैं। झगड़ा कुछ नहीं है और उपाध्यक्ष महोदय, हम ज्यादा भी नहीं मांग रहे कि हमें ज्यादा दिया जाये। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि जो बैकलाग है उसको पूरा किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस बात का ज्ञान भी होगा, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : भागी राम जी आप मेरे से बहुत सीनियर हैं, आपको मेरे से ज्यादा ज्ञान है।

श्री भागीराम : उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड और कारपोरेशंज में एस.सीज. को क्लास-1 में 3 प्रतिशत, क्लास-2 में 6 प्रतिशत और क्लास-3 में 13 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाता है और सरकारी आफिसिज में एस.सीज. को क्लास-1 में 6 प्रतिशत, क्लास-2 में 7 प्रतिशत और क्लास-3 में 13 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाता है। इनमें जहां शोर्टफाल है उसको पूरा करने के लिए मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी हुए हैं कि रिजर्वेशन के हिसाब से जो बैकलाग है उसको पूरा किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : भागी राम जी वाइंड अप करें।

श्री भागीराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 17 के 17 हरिजन विधायक जब मुख्य मंत्री जी के साथ हैं तो.....(विघ्न)

श्री रामकिशन फौजी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के साथ नहीं हूँ। मैं हरियाणा विकास पार्टी का विधायक हूँ। (विघ्न)

श्री भागीराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रामकिशन फौजी जी से पूछना चाहूँगा कि यदि हरिजनों के हितों की बात होगी तो क्या तब भी ये उसका समर्थन नहीं करेंगे।

श्री रामकिशन फौजी : उपाध्यक्ष महोदय, यदि हरिजनों के हितों की बात होगी तो मैं भागीराम जी के साथ हूँ और इनका समर्थन भी करूंगा।

श्री भागी राम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बैकलाग को पूरा किया जाये। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्य मंत्री बनने के बाद 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत गांव गांव जा करके लोगों की शिकायतें सुनी हैं। यह सरकार हिन्दुस्तान की पहली सरकार है जो लोगों के पास गयी। पहले लोग काम करवाने के लिए सरकार के पास चण्डीगढ़ आया करते थे और यहां पर काम करवाने के लिए अपने चक्कर काटते थे। कोई गली के लिए पैसे की मांग करने के लिए यहां पर आता था, कोई स्कूल बनवाने की बात को लेकर यहां पर आता था तो कोई सड़कें बनवाने के लिए आता था। इसी प्रकार से लोग हरिजन जाति के लिए चौपाल बनवाने, बैकवर्ड जाति के लिए चौपाल बनवाने या जनरल जाति के लिए चौपाल बनवाने के लिए यहां आकर सरकार के पास गुहार किया करते थे। चाहे लोगों का बिजली का काम हो, चाहे पीने के पानी का काम हो या वाटर वर्क्स का काम हो लोग यहीं आया करते थे। चौटाला साहब ने इसके उलट करके कहा कि लोगों को यहां पर अपने काम करवाने के लिए नहीं आना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि यहां पर आने की किसी को

[श्री भागी राम]

जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके पास आ रहा हूँ। जब से चौटाला साहब इस प्रदेश के मुख्य सेवक बने हैं, मुख्य मंत्री बने हैं इन्होंने हर गांव के अन्दर एक एक आदमी से मिल करके, चाहे वह किसी भी जाति-बिरादरी का था, हर बिरादरी के लोगों के लिए, समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। चौटाला साहब, वाकई इन सारे कामों के लिए बधाई के पात्र हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में यह बात कह कर इस बजट का समर्थन करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने के लिए समय दिया।

राव धर्मपाल (सोहना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस बजट पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वित्त मंत्री जी ने यह 2002-2003 का बजट पेश किया है। ये काफी अनुभवी मंत्री हैं। इन्होंने इस बजट को अच्छा प्रस्तुत करने की कोशिश भी की है लेकिन वास्तविकता में और इन आंकड़ों में फर्क दिखाई दे रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में बिजली, सड़कें और पुल आदि बनाने पर ज्यादा महत्व दिया है। साथ ही इन्होंने बजट के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि हमारे यहां पर 400 लाख यूनिट बिजली डेली पैदा होती है। इन्होंने यह भी बताया है कि जो बिजली इन्होंने पैदा की है उसमें से 247 लाख यूनिट बिजली गांवों के विकास के लिए लगाई है। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविकता कुछ और ही है। मैं कल अपने कांस्टीच्यूएंसी के किसी गांव में था। वहां पर मैं लोगों के बीच में बैठा हुआ था तो लोग बता रहे थे कि 6 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही। इसके अलावा एक दिन छोड़कर एक दिन बिजली आती है और दूसरे दिन एक या आध घण्टे के लिए वाटर सप्लाई के पानी के लिए आती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा कहना है कि अब गेहूं की फसल का कटाई का सीजन है। तकरीबन एक महीने में कटाई शुरू हो जायेगी। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इस अवधि के दौरान जब उनकी कटाई का सीजन शुरू हो तो उनको पूरी बिजली प्रतिदिन दी जाये ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है, वह यह है कि जब चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मंत्री थे तो इन्होंने नारा लगाया था कि जो तारें मैंने लगवाई हैं उनको मैं ही बदलूंगा। वे तो इस समय इस सदन में हैं नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो इन्होंने इस बारे में कहा था वह नहीं किया यानी कि इन्होंने सत्ता मिलने पर भी तारें नहीं बदलवाई। आज लोगों को बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि जो टेल पर ट्यूबवैल्ज हैं वहां पर बिजली पूरी नहीं पहुंचती। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि सरकार इसका भी कोई समाधान निकाले ताकि टेल पर रहने वाले लोगों को भी बिजली पूरी मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं मीटर बदले जाने के बारे में कहना चाहता हूँ। आजकल शहरों में भी और देहातों में भी बिजली के मीटर बदले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो नये मीटर लगवाने की बात कही है या जो पॉलिसी अपने बजट में इस बारे में बनाई है वह शायद इस बात को ध्यान में रख कर बनाई ताकि बिजली की चोरी रोकी जा सके, यानी चोरी रोकने की मंशा से ये मीटर बदले जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कम्प्यूटराईजड मीटर लगाने की बात है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इससे लोगों को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। कल की ही बात है मैं अपने क्षेत्र के किसी गांव में बैठा हुआ था और वहां पर 40-50 किसान भी बैठे हुए थे। उनमें से एक साथी कहने लगा कि मेरे साढ़े सात हार्स पावर की मोटर के तीन ट्यूबवैल्ज हैं। इन तीनों ट्यूबवैल्ज पर एक जैसी जमीन है किसी पर एक आध एकड़ कम बनती होगी। उसने बताया कि उसके एक ट्यूबवैल का बिजली का बिल 424 रुपये आता है और दूसरे का फ्लैट रेट 852 रुपये आता है। उसने बताया कि तीसरे ट्यूबवैल पर मीटर तो लगा हुआ है लेकिन उस मीटर का बिल रीडिंग के हिसाब से नहीं आ रहा बल्कि वह भी डायरेक्ट फ्लैट रेट आ रहा है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता जो बात है वह मैं यहां बता देना चाहता हूँ। जब वह आदमी यह बात कह रहा था तो दूसरा आदमी कहने लगा कि अरे कौन सा मीटर लगा हुआ है तेरे यहां। वह कहने लगा कि मुझे तो नहीं पता है कि किस कम्पनी का है तो दूसरा आदमी बोला कि मीटर बंसी लाल जी वाला है या चौटाला साहब वाला है। वह कहने लगा इस बात से क्या मतलब है। तो दूसरा

18.00 बजे

आदमी कहने लगा कि चौधरी बंसी लाल वाला है तो उसे टेढ़ा कर दो वह चलना बन्द हो जाएगा या यूनिट कम निकालेगा और अगर चौटाला वाला मीटर है तो उसको मूधा कर दो मीटर चलने से बन्द हो जाएगा तो एक और आदमी कहने लगा कि अब तो रिमोट चल गए हैं और रिमोट दाब दो मीटर बन्द हो जाएगा। यह बात कहने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आज हम जितना सोच रहे हैं जनता भी उतना ही बराबर आगे चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा अनुरोध है कि जो मीटर ठीक चल रहे हैं जिनके एम.सी.ओ. के हिसाब से बिल ठीक आ रहे हैं और भुगतान भी ठीक हो रहा है उसको न छेड़ा जाए तो अच्छा है बजाये इसके कि लोगों के अन्दर एक भ्रमात्मक बात पैदा हो सरकार उस बात को छोड़े। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक दूसरा सुझाव और है जो खासतौर से किसानों से ताल्लुक रखता है। ये जो फ्लैट रेट्स वाला सिस्टम हैं इनकी ओर सरकार को ध्यान दे। आजकल ज्यादातर मोटरें सात साढ़े सात हॉर्स पावर से कम नहीं हैं क्योंकि पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। फ्लैट रेट्स तो है लेकिन अगर कोई किसान लिख कर यह दे दे कि मेरा ट्यूबवैल छः महीने बन्द रहेगा तो सरकार द्वारा उसके कनैक्शन को काट देना चाहिये और फिर से जब वह किसान ट्यूबवैल को चलाना चाहे तो फिर लिख कर दे दे कि मैं ट्यूबवैल चलाना चाहता हूँ तो उसको इसकी अनुमति दे दी जाए। मैं समझता हूँ कि किसान को जो छः महीने का भुगतान करना पड़ रहा है उस पर नाजायज बोझ है और वह उससे बच सकता है। डिप्टी स्पीकर सर, इसके साथ ही साथ सड़कों की बात आती है। ठीक बात है आज आर्थिक विकास के लिए सड़कें मुख्य आधार हैं। मैं इस बात में कोई संकोच नहीं करूंगा यह कहते हुए कि इस सरकार ने कुछ रोडज बहुत अच्छे तरीके से बनवाई हैं (इस समय मेजें थपथपाई गईं) उपाध्यक्ष महोदय, बात मेजें थपथपाने की नहीं है मैंने कुछ रोड्ज कहा है विशेषतौर पर जो अपग्रेडेशन की गई हैं, मैं गुड़गांव में ज्यादा समय रहता हूँ और इसके साथ ही लगती हुई मेरी कांस्टीच्यूऐंसी है। गुड़गांव के चारों तरफ से जब निकलते हैं तो बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन जब गुड़गांव के अन्दर घुसते हैं तो मेरे भाई साथी डिप्टी स्पीकर साहब, जो इस समय चेयर पर विराजमान हैं, यह उनका हल्का है। श्री रामबीर जी ने भी इस बारे में थोड़ा सा कहा था लेकिन फिर कुछ रुक गए थे। पटौदी से गुड़गांव 28 किलोमीटर दूर है और 28 मिनट का ही रास्ता है। 28 मिनट में हीआदमी गुड़गांव पहुंचता है लेकिन जब गुड़गांव को क्रास करते हैं उसकी जो इन्टीरियर सड़कें हैं उनकी हालत बहुत ही खराब है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब, एक दो सड़कों के नाम भी बताएं। आप मेरे हल्के की पैरवी कर रहे हैं। (विघ्न)

राव धर्मपाल : डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ दिन पहले मैं वहां पर गया था। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : मैं मान रहा हूँ और रिकॉर्ड पर भी ला रहा हूँ अगर कोई खराब रोड है तो आप कोई नाम बताएं। (विघ्न)

राव धर्मपाल : शिवाजी पार्क के अन्दर की सड़क मेरे ख्याल से दिखाई नहीं देती है। दूसरे इसके साथ ही लगती हुई गांधी नगर रोड है। उसके आगे जहां मैं रहता हूँ शिवाजी नगर की रोड है।

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब, आप मेरी वकालत कर रहे हैं परन्तु मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, चौधरी भजन लाल जी बैठे हुए हैं लेकिन चौधरी बंसी लाल जी बैठे हुए नहीं हैं, एस.डी. स्कूल से आगे शिवाजी पार्क तक जितनी कॉलोनीज़ हैं उनका काम और खाण्डसा रोड का काम जो कभी नहीं हुआ था, वह अब हुआ है, यह बात आप मान लें। जो एक आध सड़क की कसर रह गई है आपकी शिवाजी नगर वाली, वह भी इसी महीने की 24 तारीख तक हो जाएगी। (विघ्न) शिवाजी नगर में इनकी रिहाईश है। (विघ्न)

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के सोहना की बात कहना चाहता हूँ। मेरे हल्के में एक बड़खेड़ा गांव है। आजकल प्रधान मंत्री सड़क योजना भी चल रही है और हरियाणा सरकार की योजना भी चल रही है। उस गांव को भी सड़क मिलनी चाहिए। इसके अलावा कुछ अप्रोच रोड्ज है, जिनकी हालत ऐसी हैं कि वहां पर

[राव धर्म पाल सिंह]

बसें भी जाना बंद हो गई हैं। उदाहरण के तौर पर भिवाड़ी अलवर रोड से गढ़ीवाजीपुर गांव है आज तक उस सड़क की सम्भाल नहीं हुई है। दूसरे अलीपुर से रायसिन्हा को रोड जाती है। खासतौर पर बादशाहपुर से सखतपुर वास जहां बसें बड़े-बड़े गड्ढे होने की वजह से जाना बंद हो गई हैं। (शोर एवं व्यवधान) मैं सरकार को सुझाव देना चाहूँगा कि ये जो भी सड़कें हैं चाहे यह नैशनल हाई-वे हो, चाहे स्टेट हाई-वे हो और चाहे वह एप्रोच रोडज़ हों इनके बर्म एक डेढ़ इंच नीचे जब तक नहीं रखे जाएंगे तब तक ये सड़कें ऐसे ही टूटती रहेंगी। बर्म सड़क से एक डेढ़ इंच नीचे होने चाहिएं इससे ज्यादा नीचे भी नहीं होने चाहिए। अगर इससे नीचे होगा तो टू-व्हीलर्ज को दिक्कत हो जाती है। बर्म सड़क से एक डेढ़ इंच नीचे होगा तो बारिश का पानी नीचे बह जाएगा। बर्म ठीक न होने के कारण पानी सड़कों पर ठहर जाता है जिससे सड़कों पर तारकोल ठीक नहीं रह पाता है और वे सड़कें टूटती रहती हैं। इस बारे में सरकार विचार करे, यही मेरी सरकार को प्रार्थना है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं जन-स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूँ कि सरकार ने 55-70 लीटर पीने के पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर देने को प्राथमिकता दी है। आज भी 40 लीटर पीने का पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से दे रहे हैं यह आंकड़ों में भी दिखाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, सोहना शहर ऊंचाई पर बसा हुआ है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां पर एक स्टोरेज टैंक बनाया जाए और वहां पानी लिफ्ट करके सोहना के लोगों को दिया जाए। वहां पर लोगों को पानी देने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात औद्योगिक विकास की है। इन्होंने बताया कि 20 बड़े और 554 लघु उद्योग लगाए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, 8469 लोगों को रोजगार दिया गया है, यह इन्होंने बताया है। उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे पड़ौस में रहते हैं मैं मानता हूँ कि वहां पर इतने लोगों को रोजगार दिया गया होगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बारे में दोबारा से सर्वे करवाएं कि वहां कितने हरियाणा के बच्चों को रोजगार मिला है। मेरे ख्याल से 25 प्रतिशत हरियाणा के बच्चों को भी रोजगार नहीं मिला होगा। हरियाणा में जो भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनके पीछे हमारे बच्चे डिग्री होल्डर या आई.टी.आई. पास बच्चे लगे रहते हैं कि हमें नौकरी दे दो। हम भी उद्योग वालों से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें नौकरी दो लेकिन उद्योग वालों के दिमाग में यह बात घुसी हुई है कि अगर वे लोकल बच्चों को नौकरी पर लगाते हैं तो वे स्ट्राईक करेंगे। हम उद्योग वालों को यह विश्वास भी दिलाते हैं कि अगर ये स्ट्राईक करते हैं तो हमें बताना हम इनको वहां से वापिस ले जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों की नौकरियों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब, आप कोई सुझाव दें। सम्पत सिंह जी, आप इस ईशू को पर्सनली देखें। राव साहब आप मंत्री रहे हैं आप भी सरकार को सुझाव दें।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इस बारे में एक कमेटी बनाई जाए। डिप्टी किमश्नर के पास तो टाइम नहीं होता है, आप ए.डी.सी. की अध्यक्षता में वहां की यूनिटस के चार-पांच सदस्यों की एक कमेटी बनाएं और वे वीकली एक जगह बैठकर बच्चों की योग्यता को देखते हुए नौकरियां दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रो. सम्पत सिंह जी, आप इसके साथ साथ यह भी देखें कि जो मारुति उद्योग वाले हैं वे हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी को कम्पीटैंट नहीं समझते। वे हरियाणा के यूनिवर्सिटी के किसी भी बच्चे को अपने यहां नौकरी देने के लिए कम्पीटैंट नहीं समझते हैं। आप इस बारे में भी देखें।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, मानेसर में चौधरी देवी लाल औद्योगिक माडल टाउनशिप है। यह बहुत बड़ी टाउनशिप है। उसमें भी आप सर्वे करवाएं कि वहां की फैक्टरियों में अगर 500 आदमी भर्ती किए जाते हैं तो हरियाणा के केवल 10 बच्चे ही उनमें से रखे जाते हैं। इस बारे में भी मंत्री जी देखें।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी, जॉब आरियंटिड कोर्स ही इसका एक समाधान है। इस बारे में मैंने मंत्री जी परसों भी आपसे गुड़गांव में रिक्वैस्ट की थी। आज हमारे गुड़गांव में हिन्दुस्तान की सबसे ज्यादा रेडीमेंट गारमैंट्स की एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं और आपके मानेसर में भी इस तरह की यूनिट्स हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के अन्दर रेडीमेंट गारमैंट्स का, फैशन डिजाइनिंग का और दूसरे इस तरह के कोर्स नहीं हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि हरियाणा में जॉब ओरियंटिड कोर्स शुरू करें और उसके अलावा जो हरियाणा में फैक्टरियां हैं उनमें लगने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए है उससे रिलेटिड कोर्स भी शुरू करने का कष्ट करें।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आपकी इस बात का समर्थन करता हूँ। इसी तरह से मानेसर में जो एम.आई.टी. के दूसरे फेज के लिए जमीन एक्वायर होने जा रही है उसके लिए मैं कहना चाहना चाहूँगा कि पिछली बार भी वहां पर थोड़ा मुआवजा किसानों को दिया गया था। पिछली बार 6 लाख 55 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा दिया गया था जबकि रोड के ऊपर वहां पर इस जमीन का रेट चालीस लाख रुपये प्रति एकड़ था। मैं चाहता हूँ कि कम से कम किसानों को 15 लाख रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। उनको फ्लैट रेट के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब, चौधरी भजनलाल जी ने तो कभी उचित मुआवजा किसानों को नहीं दिया है और अगर कभी दिया हो तो बता दें। इस बारे में मेरे पास सारे आंकड़े हैं।

चौ. भजनलाल : हमने मार्किट रेट के हिसाब से मुआवजा दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा से ज्यादा मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए, मैं भी इससे सहमत हूँ। परन्तु इसके लिए भजनलाल जी आप भी जिम्मेदार हैं।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ। सोहना कांस्टीच्यूएंसी में 114 गांव और 18 ढानियां हैं लेकिन वहां केवल सात ही 10 प्लस टू के स्कूल कॉलेज हैं वहां पर बच्चों को, खास तौर पर लड़कियों को अपने गांवों से पांच सात किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जोकि उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। सर्दियों में शाम को 6 बजे स्कूल छूटता है जिस वजह से लड़कियों को अपने घर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी का भाई किसी के पिता जी उनको लेने के लिए आते हैं। इस तरह से उनके लिए भी रोजाना उनको लाना ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब, जो आपके क्षेत्र में चार पांच स्कूल अपग्रेड किए हैं उनके लिए तो आपको धन्यवाद करना चाहिए।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से परिवहन की बात है। परिवहन विभाग द्वारा 1100 बसिज खरीदी गयी हैं और आगे भी 407 बसिज को और खरीदने की योजना है। ये बसिज रोड्ज पर भागती हुई भी दिखाई दे रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब, आपके क्षेत्र में भी आपकी आँखों के सामने ही बसिज भाग रही हैं।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री सामने ही बैठे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पहले गांव गांव में जाकर बसिज रुकती थीं लेकिन अब सरकार ने वहां पर बसिज का रुकना बंद कर दिया है इसलिए इन बसिज के रुकने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। खास तौर पर जो विद्यार्थी हैं या लड़कियाँ हैं उनके लिए बसिज चलायी जानी चाहिए क्योंकि वे स्कूल तक बिना बसिज के नहीं आ सकते। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा जो हरियाणा हाई-वे पैट्रोलिंग की स्कीम बनायी है वह बहुत अच्छी स्कीम है इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार इनकी फंक्शनिंग जरूर चैक करवाएं क्योंकि वे बजाए

[राव धर्म पाल]
यात्रियों की सुविधा के सरकार की बदनामी करवा रहे हैं। सारे दिन तो वे सोते रहते हैं और रात को पैसा बनाने में लगे रहते हैं इसलिए इस तरफ भी ध्यान दिया जाए क्योंकि यह बहुत ही दुखदायी मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब, गुड़गांव के क्षेत्र में सबसे ज्यादा एक्सीडैंट्स तो डम्पर के मिलते हैं, आप उनकी भी बात करें।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और चली थी और आपने भी मेरी तरफ इसका इशारा किया था कि राव धर्मपाल ने और चौधरी भजनलाल जी ने अपने अपने वक्त में स्टोन क्रैशर्ज जोन बनाये थे। चूंकि यह मेरा धंधा है इसलिए मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : राव साहब, आप एक मिनट में वाइंड अप करें।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, 14.1.1992 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कि दिल्ली और फरीदाबाद के स्टोन क्रैशर्ज को वहां से उठाया जाए क्योंकि वहां पर जो रैजीडैंशियल एरिया था, इनसे वहां पर धूल उड़ती थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए थे कि फरीदाबाद और दिल्ली के स्टोन क्रैशर्ज को वहां से उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय चौ. भजनलाल जी मुख्य मंत्री थे और राव इन्द्रजीत सिंह पर्यावरण मंत्री थे। इसी विषय पर उस समय की सरकार ने एक कमेटी बनायी थी। यह कमेटी गुड़गांव के कमिश्नर श्री अस्थाना जी की सुपरविजन में बनी थी और इस कमेटी के मैम्बर्ज डी.सी., बी.डी.पी.ओ., पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वहां का एक अधिकारी और तहसीलदार थे। इन सब ने फैसला करके एक जगह का चयन किया था। बाद में सरकार की तरफ से इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी हुई थी। इस कमेटी ने रायसीन रिन्ड्डी और मारसपूर तीन जगहों का चयन किया था। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टेक्नीकल कमेटी की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए इस कमेटी द्वारा कुछ नोर्म्ज रखे गए थे कि सड़कों से और गांवों से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर जोन बनाकर ये स्टोन क्रैशर्ज रखे जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ये नोर्म्ज बनाकर ही इस तरह के जोन बनाये गये थे। चौधरी बंसी लाल जी इससे इतनी नफरत करते थे कि जब क्रैशर के पास से निकलते थे तो कहते थे कि इनको बंद कर दो, इनको आग लगा दो, ऐसा बोलते थे और मुझे इस बात का ताज्जुब होता है कि उन्होंने अपने समय में एक नोटिफिकेशन 18.12.97 को निकाली उस नोटिफिकेशन के तहत गांव की दूरी 800 मीटर कर दी और सड़क से दूरी खत्म कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, सड़क पर इतना भारी ट्रैफिक चलता है और दोबारा से क्रशर सड़क पर चला दिए। पलवल, सोहना, रेवाड़ी रोड पर एक काका स्टोन क्रैशर है और एक मां संतोषी स्टोन क्रैशर है।

श्री उपाध्यक्ष : पलवल क्यों जाते हो, गुड़गांव में पिछली सरकार के दौरान क्या यह सब दो तीन साल तक नहीं चलता रहा।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि पैरामीटर्ज चेंज किए जाएं। जब हौट मिक्स प्लांट की बात आई थी तो कहा गया था कि धर्मपाल, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के भाई का हौट मिक्स प्लांट बंद कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, रोटी कमाने में कोई बुराई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : हौट मिक्स प्लांट के लिए अलग से जगह दे दें तो कैसा रहेगा।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि उस प्लांट से हालांकि इतना इमीशन नहीं होता उसमें तो केवल मिक्सिंग होती है।

श्री उपाध्यक्ष : कपड़े की फैक्ट्री से ज्यादा धुंआ हौट मिक्स प्लांट में होता है परसों आप सब आ जाओ, मैं आपको दिखा देता हूं।

राव धर्मपाल : उपाध्यक्ष महोदय, उनसे कहें कि ट्रीटमैंट प्लांट लगाएं।

श्री उपाध्यक्ष : आप टैक्नीकल आदमी हैं सम्पत सिंह जी को इस बारे में सुझाव दे दें। अब आप बैठ जाएं। अब श्री भीम सेन मेहता बोलेंगे।

श्री भीम सेन मेहता (इन्द्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने और हल्के की समस्याएं सरकार के समक्ष रखने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। 13 मार्च, 2002 को हरियाणा के वित्त मंत्री प्रोफैसर संपत सिंह जी ने हरियाणा की जनता की भलाई के लिए और आम आदमी की जरूरतों को देखते हुए बजट पेश किया। उसके हर पहलू पर मेरे सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये। इस बजट के अंदर चाहे यातायात के साधनों की बात हो, चाहे बिजली के क्षेत्र की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, इसमें हर मूलभूत जरूरत पर विशेष ध्यान दिया गया। मैं इस बजट के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। क्योंकि आप समय की पाबंदी लगाएंगे इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने हल्के की समस्याओं को आपके द्वारा सरकार के समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी मौजूदा सरकार के समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी मौजूदा सरकार की 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम की है। मुझसे पहले बोलते हुए भागी राम जी एवं दूसरे साथियों ने भी कहा कि यह पहला अवसर है कि सरकार खुद चलकर लोगों के पास लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जाती है और मौके पर ही उन समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है। कई समस्याओं का सामाधान करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी मौके पर घोषणा भी करते हैं। मेरे अपने हल्के में दो ऐसी समस्याएं थी जिनका 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में मुख्य मंत्री जी ने समाधान किया और जरूरत के मुताबिक पैसा अनुदान के रूप में दिया। मेरे हल्के की कुछ ऐसी समस्याएं हैं एक तो सड़कों की समस्या है। सड़कों की हालत बहुत खस्ता है मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे हल्के से एक सड़क गुजरती है करनाल से लाडवा। यह एक ऐसी सड़क है जो दोनो शहरों को आपस में जोड़ती है लेकिन आज उस पर चलकर देखा जाये तो पता चलेगा कि उसके अन्दर बड़े-बड़े गड्ढे पड़े हुये हैं। इसी प्रकार से नेवल से चौगांव की सड़क जो करनाल और यमुनानगर जिलों को मिलाती है। इस तरह से इन्द्री से डमरी की सड़क जो भादसों शूगर मिल को जोड़ती है इस सड़क की हालत बड़ी खराब है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब ये पहले दौरे पर आये थे उस वक्त किसानों की रिक्वैस्ट पर इस सड़क को इन्होंने बनवाया था लेकिन वह सड़क अब फिर से खराब हो चुकी है। यह सड़क इन्द्री को करनाल और कुरुक्षेत्र जिले से मिलाती है। इसी तरह रामपुर से लाडवा की सड़क जो करनाल जिले को कुरुक्षेत्र जिले से मिलाती है। इन सड़कों की हालत खराब है इनको जल्दी से जल्दी बनवाया जाये ये मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बारे में आश्वासन भी दिया है और मेरा पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन सड़कों को बनवाने के लिए आदेश जरूर देंगे और इस कार्य को पूरा भी करवायेंगे। इसके अलावा दूसरी सड़कें जो पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत बनाई जानी हैं और जिनकी 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत बनाने की घोषणा की गई है उनको जल्दी से बनवाने की कृपा करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इन्द्री में जो सी.एच.सी. है उसकी बिल्डिंग तो ठीक है परन्तु डाक्टर के लिए रहने की कोई व्यवस्था नहीं है इस वजह से हमारे वहां पर कोई डाक्टर ज्यादा दिन तक नहीं रहता। वहां पर डाक्टर को रोकने के लिए रिक्वैस्ट करनी पड़ती है और उनके रहने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करना पड़ता है तब जाकर कुछ डाक्टर साल-छः महीने रहे हैं। इसलिए वहां डाक्टर का रहने का इंतजाम जरूर किया जाये। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले सैशन में इन्द्री में सब्जी मण्डी बनाने की घोषणा की गई थी इसलिए इन्द्री में सब्जी मण्डी बनाने की व्यवस्था की जाये। इसके साथ-साथ एक और निवेदन करना चाहूँगा कि इन्द्री में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाये जिससे वहां के नौजवानों को और बच्चों को खेलने की उचित जगह मिल सके। इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना

[श्री भीम सेन मेहता]

चाहूँगा कि मेरा हल्का पैडी एरिया है वहां धान की फसल बहुत होती है इसलिए हैफेड के सेलर वहां पर लगवायें जिससे वहां के किसानों को काफी फायदा मिलेगा। इसी के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इन्द्री हल्के की तरफ भी अपना प्रेम और स्नेह बनाये रखें और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और वित्त मंत्री प्रोफैसर सम्पत सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हरियाणा के हित के लिए, हरियाणा प्रदेश की जनता की भलाई के लिए और जनता की मुलभूत जरूरतों को ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया है मैं इसका पूरजोर समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद मेहता जी।

श्री बलबीर पाल शाह (पानीपत) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मेरा ख्याल है कि समय भी इतना बना है जो आप मुझे देना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट की मेरे कई माननीय सदस्यों ने तारीफ भी की है और हमारी तरफ के कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि यह बजट ठीक नहीं है। मैं इस बजट का ठीक होना तभी मानूंगा जब मेरे ये साथी कहेंगे कि सारे हरियाणा में विकास हुआ है। जब पानीपत के अन्दर विकास होगा। मैं पानीपत की कुछ वित्त सम्बन्धी समस्याएं आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि बजट पर बोलूंगा तो समय नहीं रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहली समस्या तो यह है कि पानीपत को तो जिला बना दिया गया लेकिन सालों हो गए हमारी वहां मिनी सचिवालय बनाने की मांग पूरी नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात का प्रावधान करें कि वहां मिनी सचिवालय जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि लोगों की ख्वाहिश पूरी हो सके। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि पानीपत के अन्दर जो रिफाइनरी है लगभग वहां से एक करोड़ रुपया रेवेन्यू सरकार को आता है अब तो उस रिफाइनरी की कैपेसिटी भी डबल होने जा रही है और रेवेन्यू भी सरकार को डबल आने लगेगा। पानीपत में एक्सपोर्ट का काम है 1000 या 1200 करोड़ रुपये फोरन करेंसी के पानीपत से आते हैं और इतना रेवेन्यू आते हुए भी पानीपत जिले को इग्नोर किया जाता है। पानीपत में जो डिवैल्पमैंट होनी चाहिए वे ठीक ढंग से नहीं हो पा रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मेरे साथी फूल-फूलकर ये कहते हैं कि मुख्य मंत्री महोदय विकास के कार्य करा रहे हैं तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारे इलाके में भी विकास के ऐसे कार्य हों जिससे हम भी कहें कि मुख्य मंत्री महोदय हमारे इलाके में विकास के काम करा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पानीपत में जो पीने का पानी है वह सारा गन्दा हो चुका है। चाहे इसके लिए पी.डब्ल्यू.डी. के किसी भी टयूबवैल का पानी चैक करवा लिया जाए। वह पानी पीने योग्य नहीं रहा। उपाध्यक्ष महोदय, पहले क्लोरिनेशन की स्कीम चलाई थी लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं चली। वह स्कीम एक साल के लिए चला दी गई थी फिर बन्द कर दी गई। इसलिए अब गन्दे पानी से बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। पानीपत की जितनी आउटर कालोनियां हैं और वहां जो टयूबवैल्ज हैं उनके पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सड़कों की बात करना चाहूँगा। जब बरसात आती है या टयूबवैल्ज का पानी आता है या फैक्ट्रियों का पानी आ जाता है तो सड़कें टूट जाती हैं जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है और गड्ढों में पानी भर जाता है। मक्खी मच्छरों से बीमारियां फैलने का हर वक्त भय बना रहता है।

श्री उपाध्यक्ष : बलबीर पाल जी, आप जल्दी वाइंड अप करें।

श्री बलबीर पाल शाह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ ज्यादा लम्बी बात नहीं कहना चाहता। आपने तो मुझे बोलने के लिए टाइम दिया उसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक दो मैम्बर्ज को और एडजैस्ट करना चाहता हूँ।

श्री बलबीर पाल शाह : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं हैल्थ के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। आप चैक करवा

[श्री देवराज दीवान]

किसानों, मेहनतकशों और गरीबों के मसीहा चौधरी देवी लाल जी ने अपने शासनकाल के दौरान खुले दरबार लगा कर जनता की समस्याओं को तत्काल मौके पर ही समाधान कर देश तथा प्रदेश को एक नया रास्ता दिखाया था। उसी परम्परा को कायम रखते हुए वर्तमान मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए 'सरकार आपके द्वार' जैसा गतिशील कार्यक्रम प्रदेश की जनता को प्रदान किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी खुला दरबार लगा कर खुद ही लोगों के बीच जाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर ही करवाते हैं। उनके इस प्रयास से प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है क्योंकि हरियाणा के विकास कार्यों को इससे बहुत अधिक गति मिली है। प्रदेश के तेजी से विकास के लिए "सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी बधाई के पात्र हैं। 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे हल्के सोनीपत भी 3-6-2001 को खुला दरबार आयोजित किया था और लोगों की समस्याएं सुनी थीं। उस दरबार में मुख्य मंत्री जी ने मौके पर ही 7 करोड़ रुपये की लागत से विकास के काम करवाने के आदेश दिए थे। आज विपक्ष के भाई कहते हैं कि विकास के कोई काम नहीं हो रहे। मैं अपने विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूँ कि यदि इन्होंने विकास के कार्य देखने हैं तो वे सोनीपत आकर देखें कि विकास के कार्य कैसे हुये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्य मंत्री बने हैं तब से सोनीपत जिले की कायाकल्प हो गयी है। आप लोगों ने सोनीपत शहर को पहले भी देखा होगा और अब भी आप जाकर उसे देख लें तो पता लग जायेगा कि विकास के काम कैसे होते हैं। जिन लोगों ने सोनीपत शहर को पहले देखा होगा और अब वे इसे जाकर देखेंगे तो वे सोचेंगे कि वे सोनीपत में नहीं बल्कि चण्डीगढ़ में हैं। मैं जो बात बता रहा हूँ वह किए गए कार्यों के बारे में ही बता रहा हूँ। मैं केवल मुख्य मंत्री जी की प्रशंसा के लिए ही नहीं कह रहा बल्कि जो विकास के कार्य असलियत में हुए हैं वे ही बता रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इस के साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि मुख्य मंत्री जी खुले दरबार में जो योजनाएं मंजूर करके आये थे उनमें से आज तकरीबन 80 प्रतिशत योजनाओं पर काम हो चुका है। बाकी जो काम बचे हैं उनकी भी मैं एक लिस्ट बना कर भेज दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बलबीर पाल शाह जी भी बजट पर बोलते हुए सड़कों के बारे में कुछ कह रहे थे। इस बारे में मैं उनको बताना चाहूँगा कि सोनीपत शहर की कोई भी मेन सड़क हो वे सभी की सभी नई बनाई गई हैं। चाहे सोनीपत से रोहतक जाने वाली सड़क हो, चाहे सोनीपत से गोहाना जाने वाली सड़क हो चाहे सोनीपत से मेरठ जाने वाली सड़क हो, और चाहे सोनीपत से चण्डीगढ़ जाने वाली सड़क हो, सभी की सभी सड़कें बहुत अच्छी तरह से बनाई गई हैं। ये सभी सड़कें इतनी शानदार बनी हैं कि इतनी शानदार सड़कें सोनीपत में आज से पहले कभी नहीं बनी थीं। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि शहर की जो अन्दर की छोटी सड़कें हैं, चाहे वे सैक्टरों की हैं या कॉलोनीज की हैं, उनको भी तुरन्त ठीक करवाया जाये ताकि लोगों को आने-जाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। वैसे तो मुख्य मंत्री जी ने इन सभी सड़कों को भी बनाये जाने का वायदा किया है और कहा है कि इनको भी जल्दी ही बनवा दिया जायेगा। जैसे ही ये छोटी सड़कें भी नई बन जायेंगी तो फिर सोनीपत शहर की कोई ऐसी सड़क नहीं होगी जो नई न बनी हो। इन छोटी सड़कों के बन जाने के बाद फिर सब लोग कहेंगे कि सोनीपत शहर चमक गया है। इसके बाद लोग सोनीपत का मुकाबला चण्डीगढ़ से कर सकते हैं। **(विघ्न)**

अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली से संबंधित एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या इनको नहीं पता कि पहले कितने घंटे बिजली आती थी और अब कितने घंटे बिजली आ रही है। क्या इनको कोई फर्क नजर नहीं आता। (विघ्न) मैंने आप लोगों की सरकार के भी काम देखे हैं। मैं तो केवल वही सच्चाई कह रहा हूँ जो मेरे साथ बीत रही है। अध्यक्ष महोदय, जब पीछे चौधरी बंसी लाल जी डेढ़ साल मुख्य मंत्री थे तो उस वक्त में भी इनके साथ था। जब भी मैं कहता कि आपने सोनीपत हल्के के विकास का वायदा किया

कर देख लें देश में 50 परसेंट लोग टी.बी. से पीड़ित हैं। पानीपत में जो कालोनियों में लोग बसे हुए हैं उनमें 90 परसेंट लोग टी.बी. से पीड़ित हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पानीपत को विकास के कार्यों में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो मजदूर हमारे लिए काम करके लाखों करोड़ों रुपये देते हैं वे अगर बीमारी से पीड़ित होते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम मरीज का ध्यान रखें और उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हैल्थ सर्विसिज का प्रावधान करें। पानीपत में जी.टी रोड है, वहां पर जो थाने हैं वहां अगर कोई एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के लिए जाता है तो कहा जाता है कि स्टाफ वी.आई.पी. डयूटी पर है और जब वह स्टॉफ आ जाएगा तब आपकी कम्पलेंट लिखी जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वहां पर कुछ एक्स्ट्रा पुलिस की फोर्स लगा दी जाए जो कि वी.आई.पीज. को रिसीव करने और सी ऑफ करने का काम करें ताकि हमें यह सुनने को न मिले कि स्टाफ वी.आई.पी. डयूटी पर है। कई बार 4-4 दिन तक हमारी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती। इस वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि ग़रीब व्यक्ति के साथ इन्साफ नहीं हो पाता।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है, जी।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है बैठक का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री बलबीर पाल शाह : उपाध्यक्ष महोदय, ये जितने भी मामले हैं ये सारे वित्त से संबंधित हैं और जब तक वित्त नहीं होगा तो कोई भी काम सिरे चढ़ने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि पानीपत में तीन चीजों की कमी है। एक तो वहाँ लड़कियों का कॉलेज नहीं है दूसरा वहां बाई-पास नहीं है और तीसरा वहाँ बिजली का तामझाम बिगड़ा हुआ है। वहाँ बिजली की तारें नीचे लटकी हुई हैं जिनसे करंट लगने से काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा उनको बिजली विभाग से किसी किस्म का मुआवजा भी नहीं मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त पानीपत अस्पताल में प्राइवेट वार्डज और कुछ कमरों की हालत ठीक नहीं है इसलिए वहाँ भी सुविधाएं बढ़ा दी जायें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। (विघ्न)

श्री देवराज दीवान (सोनीपत) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने माननीय वित्त मंत्री प्रो. सम्पत सिंह जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने के लिए मुझे समय दिया। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने दिनांक 13-3-2002 को हाउस में बजट प्रस्तुत करके एक मिसाल कायम की है। मुझे समझ नहीं आता कि विपक्षी साथी इसमें नुक्स कहाँ से ढूंढते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बजट में कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। यह बजट ग़रीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि हर वर्ग के लिए यह विकासशील बजट है और मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इतने अच्छे बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ तथा इसके लिए हमारे मुख्य मंत्री महोदय भी बधाई के पात्र हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं राज्य की जीवन रेखा कही जाने वाली एस.वाई.एल. परियोजना का जिक्र करना चाहूँगा। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय और वर्तमान सरकार ने इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निर्धारित अवधि में लागू करवाने सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

हुआ था तो आप उसको पूरा करें। मैं कहता था कि मैंने इसी बात पर आपका साथ दिया है कि आप सोनीपत जिले का विकास करेंगे। उस वक्त बंसी लाल जी कहते कि ईब की बार पैसा आयेगा ईब की बार करवाऊँगा। चौधरी बंसी लाल जी ने डेढ़ साल के अन्दर सोनीपत जिले में एक पैसा भी नहीं लगाया। अब इस सरकार को बने हुए केवल दो साल हुए हैं और इन दो सालों में सोनीपत में इतने कार्य हुए हैं जो पिछले 50 सालों में भी नहीं हुए थे।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो सदन का समय पांच मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय पांच मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट की बात मत करो, मुझे बोलने दो। आप टाइम की बात मत करो, मुझे 5 मिनट लगे या 10 मिनट लगे, मुझे बोलने दें।

वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में 25 गांव हैं, शहर के 31 वार्डज हैं और दो सेक्टरज हैं, इनमें कोई जगह ऐसी नहीं है जहां विकास का कोई काम चल नहीं रहा हो। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, जहां विकास कार्य नहीं हुए हों। गांव का हर आदमी यह मानता है कि विकास हुआ है तो अब की बार हुआ है। बल्कि बुजुर्ग तो यहां तक कहते हैं कि भाई अब के तुमने मुख्य मंत्री को क्या कर दिया है तो मैं उनको कहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने तो सभी जगह ऐसे ही काम करवाए हैं। यहां पर हमें भी विकास मिल रहा है हर जगह विकास के कार्य हो रहे हैं मैंने मुख्य मंत्री जी को कुछ नहीं किया है। आज लोग मुख्य मंत्री जी को इतना सराहते हैं कि जिसका जिक्र मैं नहीं कर सकता। इन्होंने सोनीपत हल्के पर जितना ध्यान दिया है इससे पहले किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया (विघ्न)। अध्यक्ष महोदय, सोनीपत की कॉलोनियों में सीवरेज नहीं था और जो छोटे-छोटे सीवरेज थे वे भी कई सालों से बंद पड़े हुये थे। आज कई कॉलोनियों में करोड़ों रुपयों का सीवरेज का काम चल रहा है। किसी कॉलोनी में 6 करोड़ का और किसी कॉलोनी में 7 करोड़ के सीवरेज के काम चल रहे हैं। जो सीवरेज पहले बंद थे वे भी खुलवा दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि जो एक-आध कॉलोनी रह जाएगी। उसमें भी इस प्लॉन में सीवरेज डल जाएगा। (विघ्न) गुप्ता जी, ये सब बातें मैं इनको नहीं आपको बता रहा हूं कि ये काम करने वाले मुख्य मंत्री हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी वह शख्स है जिनको हम दोस्त भी समझते हैं, भाई भी समझते हैं, नेता भी मानते हैं और बुजुर्ग भी मानते हैं। वे मुख्य मंत्री की तरह बात नहीं करते, बल्कि दोस्त की तरह बात करते हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गईं) हम पहले भी देख चुके हैं और हम इनको भी देख चुके हैं कि ये मुख्य मंत्री जी से कैसे बात करते थे वह भी हमने देखा हुआ है। आज हरियाणा राज्य की जनता भी इस बात को देखती है (विघ्न) स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को भी और मुख्य मंत्री जी को भी फिर यह रिक्वैस्ट करता हूं कि जिस कॉलोनी में सीवरेज डलना बाकी है उसके लिए भी जल्दी से जल्दी बजट में प्रावधान करें ताकि इस प्लान से शहर में कहीं भी कोई सीवरेज का काम बाकी न रह जाए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं पीने के पानी की बात कहता हूं। मेरे हल्के सोनीपत में कई करोड़ रुपये की लागत से अभी एक वाटर वर्क्स ट्रीटमैंट प्लांट तैयार हुआ है और शायद 8-10 दिन में उसका उद्घाटन होने वाला है। मैं यह चाहूँगा कि माननीय वित्त मंत्री जी उस वाटर प्लांट का जो थोड़ा बहुत काम रह गया है तो उसे भी पूरा करवाया जाए, वैसे वह प्लांट बिल्कुल तैयार है। स्पीकर सर, इसी प्रकार से खेतों में पानी की थोड़ी बहुत समस्या तो है। मेरे हल्के के कुछ गांव हैं जहां छोर तक पानी नहीं पहुँचता है और उनके जोहड़ भी सूखे पड़े हुए हैं और वहां पर पानी नहीं पहुँच रहा है। ये गांव हैं

[श्री देव राज दीवान]

नैनातातारपुर, बोहला, थरिया, ठरू, उल्देपुर, शहजादपुर, सांदलकला, पिनाना, खिजरपुर माजरा, किलोड़द, जाहरी हुल्लाखेड़ी, दिटाना, माहरा, भटाना, जफराबाद और जुआं। इन गांवों में पीने के पानी की समस्या है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वे मेरे इन गांवों के खेतों के पानी की तरफ तथा पीने के पानी की तरफ भी ध्यान देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : दीवान साहब, अब आप वाइंड अप करिये।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 5 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री देव राज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी कुछ बातें लिख कर दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे बिजली का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, पानी का मामला हो, वह चाहे पीने का पानी हो या सिंचाई का पानी हो, उस बारे में यह जो 36 पेज का बजट पेश किया गया है इसमें कहीं पर कोई कमी नहीं है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ और वित्त मंत्री जी को तथा मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया और मुझे सुना इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : राव नरेन्द्र सिंह जी आप बोलें। आपको बोलने के लिए पांच मिनट का समय दिया जाता है। आप शीघ्रता से अपनी बातें पूरी करें।

राव नरेन्द्र सिंह (अटेली) : स्पीकर सर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमंत्री जी ने इस वर्ष का जो बजट सदन में पेश किया है, उसमें लगभग 200 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित दिखाया गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों के बजटों के देखते हुए मैं यह बात निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि यह जो 200 करोड़ का घाटा दिखाया गया है यह इससे भी ज्यादा जाने की संभावना है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, पिछले वर्ष वाटर सप्लाई का अनुमान 3.27 प्रतिशत था, इस बार उसको घटाकर 3 प्रतिशत ही कर दिया गया है। इसी तरह से सोशल वैल्फेयर के लिए 3.38 प्रतिशत पिछले वर्ष दिखाया गया था और इस वर्ष उसको घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा पावर, पुलिस और इरिगेशन के अन्दर भारी कटौती की गई है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इतनी कटौती करने के बाद सरकार यह जो कह रही है कि हम हरियाणा में विकास के काम करवाएंगे और हरियाणा को अधिक बिजली देंगे, यह कैसे होगा। अब की बार बजट में बिजली के अन्दर भारी कटौती की गई है। स्पीकर साहब, जहां बिजली के लिए पिछली बार 487 करोड़ रुपए अलाट किए गए थे वहां अब की बार केवल 166.56 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया है। स्पीकर सर, मुख्य चीजें जो कि इस बार के बजट में बिजली के बारे में दर्शाई गई हैं कि 481 लाख यूनिट्स बिजली प्रतिदिन हरियाणा अपनी पैदा कर रहा है और इसमें से 247 लाख यूनिट्स बिजली गांवों को दे रहा है। स्पीकर सर मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि वास्तविकता में देहातों की बिजली की समस्या ज्यों की त्यों ही बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी यह चर्चा थी कि ग्रामीणों को 35 प्रतिशत बिजली अधिक दी जा रही है। लेकिन जब छात्रों की पढ़ाई का समय होता है, शाम को खाना खाने का समय होता है या किसानों को जब बिजली खेत में चाहिए होती है, तो उस मौके पर बिजली नहीं होती है। अब मैं नहीं समझ पाता

है कि वह बिजली कहां पर रह जाती है। आज देहातों में बिजली की बहुत कमी है। मैं सदन में यह कहना चाहूँगा कि आज आपके सर्वेक्षण के अनुसार बिजली के कन्ज़्यूमर्ज की संख्या कम हुई है। मैं इस बारे में यह समझता हूँ कि लोगों ने दुखी होकर अपने कनैक्शन कटवा लिए हैं चाहे वे नलकूपों के हों, चाहे घरेलू हों और चाहे औद्योगिक हों। इलैक्ट्रोनिक मीटर्ज को लेकर भी आज हरियाणा की जनता में काफी रोष है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि इस बारे में पुनर्विचार करें। अगर हरियाणा की जनता उन मीटर्ज को लगवाना नहीं चाहती है तो निश्चित रूप से आपको उनको नहीं लगाना चाहिए। स्पीकर सर, आज देश को आजाद हुए 55 वर्ष हो गए हैं लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज भी हरियाणा में ऐसे क्षेत्र जहां पीने का पानी भी नहीं है। आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग चुनावों का बहिष्कार करते हैं। सन् 2000 में जो मौजूदा चुनाव हुए थे उसमें नारनौल के 25 गांवों ने चुनावों का बहिष्कार किया था क्योंकि वे कहते हैं कि हमारे पास पीने का पानी भी नहीं है। जिला महेन्द्रगढ़ के जो गांव टेल पर हैं वहां पर किसी भी गांव में नहर का पानी उपलब्ध नहीं होता है। वहाँ का किसान आज पलायन करने को मजबूर है। स्पीकर सर, आप जानते हैं कि एस.वाई.एल. कैनाल के बनने से अगर सबसे ज्यादा किसी जिले को फायदा होगा तो महेन्द्रगढ़ को होना है क्योंकि वह नहर हमारी जीवन रेखा है। स्पीकर सर, उसके न बनने से हमारे किसान हर मामले में और खेती में पिछड़ जाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर छोटा किसान है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज, यदि सदन की सहमति हो तो सदन का समय पांच मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन का समय पांच मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2002-2003 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

राव नरेन्द्र सिंह : वह बैंक का कर्जदार है और इस अवस्था में वह अपनी बहन या बेटी की शादी के लिए केवल अपनी खेती पर ही निर्भर करता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर जो भाखड़ा का या यमुना कैनाल का मौजूदा पानी है उसमें जिलेवाइज बराबर हिस्सा होना चाहिए। हमारी तरफ के जिलों को पानी का कम हिस्सा मिलता है। अध्यक्ष महोदय, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जिलों के अंदर सेम की वजह से जहाँ हजारों एकड़ जमीन खराब है वहीं हमारे इलाके के अंदर पानी न मिलने की वजह से हजारों एकड़ जमीन सूखी रहती है जिससे किसान खेती नहीं कर पाता। मैं चाहूँगा कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाये। इसी तरह से राजस्थान सरकार ने कृष्णावती, दोहन और साहबी नदियों पर जो बांध बना रखे हैं उसमें भी हमें अपना पानी का हिस्सा मिलना चाहिये। सरकार को उस सरकार से बातचीत करके यह हिस्सा दिलवाना चाहिए ताकि उस इलाके में पानी आ सके। अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. कैनाल की चर्चा बजट में जरूर है लेकिन बजट में यह नहीं बताया गया है कि इसको बनाने या मरम्मत के लिए कितने फंडज रखे गये हैं या इसको चालू करने के लिए कितने फंडज की जरूरत पड़ेगी। बजट में कृषि की भी चर्चा है। मैंने कालिंग अटेंशन मोशन के माध्यम से अपने इलाके के किसानों की सरसों की फसल के नुकसान के बारे में सरकार से पूछा था और सरकार की तरफ से चौधरी धीरपाल सिंह जी ने इसका जवाब भी दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं एक अखबार आपके पास भिजवा रहा हूँ जिसमें स्पष्ट रूप से छपा हुआ दिखाया गया है कि सरसों की खड़ी फसल पर एक किसान अपना ट्रैक्टर चला रहा है क्योंकि उसकी वह फसल बर्बाद हो चुकी है। चाहे वह फसल पाले की वजह से खराब हुई हो या किसी और रोग की वजह से खराब हुई हो लेकिन वहां पर किसान को नुक्सान जरूर हुआ है लेकिन हमारी सरकार यह बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि वहां पर नुक्सान हुआ है। इसी

[राव नरेन्द्र सिंह]

तरह से बेरोजगारी के बारे में बजट में चर्चा की गयी है। आर्थिक सर्वेक्षण के पेज 85 पर आप देखेंगे कि 31 दिसम्बर, 2000 तक बेरोजगारों की संख्या 7,85,408 थी जबकि एक साल के अंदर ही यह संख्या घटकर 6 लाख 62 हजार हो गयी है। यह किस कारण से ऐसा हुआ ? यह इसलिए हुआ क्योंकि मौजूदा हरियाणा सरकार ने चुनाव से पहले जो वायदा किया था कि हम बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार देंगे लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। इन्होंने इस बारे में नारा भी लगाया था कि फारेस्ट में इतने पौधे लगाओ और रोजगार पाओ। बेरोजगारों की यह संख्या नौकरी मिलने की वजह से नहीं घटी है बल्कि यह इसलिए घटी है कि बेरोजगार रोजगार कार्यालयों के चक्कर काटते-काटते निराश हो गये हैं और उन्होंने वहां से अपने नाम कटवा लिये हैं।

श्री अध्यक्ष : राव साहब, अब आप दो मिनट में वाईंड अप करें।

राव नरेन्द्र सिंह : इसी तरह से मैं सी.ए.जी. की रिपोर्ट के बारे में कहना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष : राव साहब, आप केवल बजट पर बोलें।

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, *******

श्री अध्यक्ष : अब यह जो भी सी.ए.जी. की रिपोर्ट के बारे में बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाये। (विघ्न)।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के बारे में भी कहना चाहूँगा। इस कार्यक्रम को जो मुख्य मंत्री जी चला रहे हैं वह अच्छी बात है। वे स्टेट के मालिक हैं हाउस के लीडर हैं इसलिए वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमारी आपत्ति इस बात की है कि सरकार का और पार्टी का आपस में मिलान न करें। अध्यक्ष महोदय, पहले भी कई सरकारें आयी लेकिन कभी भी किसी सरकार के समय ऐसा नहीं हुआ कि सरकार की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चैक्स बांटे हों। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि जो मौजूदा सरकार है उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चैक्स बांटे हैं, उद्घाटन किये हैं। हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा किस हैसियत से किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बारे अखबार दिखा सकता हूँ।

Mr. Speaker : Rao Narender Ji, please take your seat. Hon'ble Members, now the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 19th March, 2002.

[*18.55 hrs.] (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Tuesday, the 19th March, 2002)

34832--H.V.S.--H.G.P., Pkl.

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।